NEXT IAS

PTS (GS): CSE 2026

PTS (जी.एस.): सिविल सेवा परीक्षा 2026

GENERAL STUDIES

Paper-I | Sectional Test-1

Polity, Governance and Current Affairs (January 2025)

Test Code: 02100825

DATE : 10/08/2025

Test Booklet Series

B

परीक्षण पुस्तिका अनुक्रम

सामान्य अध्ययन

पेपर-I | सेक्शनल टेस्ट-1

राजव्यवस्था, शासन तथा समसामयिक मामले (जनवरी 2025)

Time Allowed*: *Two Hours ***Maximum Marks: 200***

Before attempting paper please read the instructions given on page no. 2 or 3 carefully and follow them.

समय : दो घण्टे **पूर्णांक : 200**

कृपया प्रश्न-पत्र हल करने से पहले पृष्ठ संख्या 2 अथवा 3 पर दिए गए अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़े तथा उनका अनुसरण करें।

DELHI CENTRE:
Vivekananda House
6-B, Pusa Road, Metro Pillar No. 111,
Near Karol Bagh Metro
New Delhi-110060
Phone: 8081300200

DELHI CENTRE:
Tagore House
27-B, Pusa Road, Metro Pillar No. 118,
Near Karol Bagh Metro
New Delhi-110060
Phone: 8081300200

DELHI CENTRE:
Mukherjee Nagar
637, Banda Bahadur Marg,
Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Phone: 9311667076

PRAYAGRAJ CENTRE:
31/31 Sardar Patel Marg,
Civil Lines, Prayagraj
Uttar Pradesh-211001
Phone: 9958857757

JAIPUR CENTRE:
Plot No. 6 & 7, 3rd Floor,
Sree Gopal Nagar,
Gopalpura Bypass, Jaipur-302015
Phone: 9358200511

जब तक आपको यह परीक्षण पुस्तिका खोलने को न कहा जाए तब तक न खोलें।

अ नु दे श

1. परीक्षा प्रारम्भ होने के तुरन्त बाद आप इस परीक्षण पुस्तिका की पड़ताल अवश्य कर लें कि इसमें कोई बिना छपा, फटा या छूटा हुआ पृष्ठ अथवा प्रश्नांश आदि **न हो**। यदि ऐसा है, तो इसे सही परीक्षण पुस्तिका से बदल लें।

2. **कृपया ध्यान रखें कि** OMR **उत्तर-पत्रक में उचित स्थान पर रोल नम्बर और परीक्षण पुस्तिका अनुक्रम** A **या** B **को ध्यान से एवं बिना किसी चूक या विसंगति के भरने और कूटबद्ध करने की जिम्मेदारी उम्मीदवार की है। किसी भी प्रकार की चूक/विसंगति की स्थिति में उत्तर-पत्रक निरस्त कर दिया जाएगा।**

3. इस परीक्षण पुस्तिका पर साथ में दिए गए कोष्ठक में आपको अपना अनुक्रमांक लिखना है। परीक्षण पुस्तिका पर और कुछ न लिखें।

4. इस परीक्षण पुस्तिका में **100** प्रश्नांश (प्रश्न) दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्नांश **हिन्दी और अंग्रेजी** दोनों में छपा है। प्रत्येक प्रश्नांश में चार प्रत्युत्तर (उत्तर) दिए गए हैं। इनमें से एक प्रत्युत्तर को चुन लें, जिसे आप उत्तर-पत्रक पर अंकित करना चाहते हैं। यदि आपको ऐसा लगे कि एक से अधिक प्रत्युत्तर सही हैं, तो उस प्रत्युत्तर को अंकित करें जो आपको सर्वोत्तम लगे। प्रत्येक प्रश्नांश के लिए **केवल एक** ही प्रत्युत्तर चुनना है।

5. आपको अपने सभी प्रत्युत्तर अलग से दिए गए उत्तर-पत्रक पर ही अंकित करने हैं। उत्तर-पत्रक में दिए गए निर्देश देखें।

6. **सभी** प्रश्नांशों के अंक समान हैं।

7. इससे पहले कि आप परीक्षण पुस्तिका के विभिन्न प्रश्नांशों के प्रत्युत्तर उत्तर-पत्रक पर अंकित करना शुरू करें, आपको प्रवेश प्रमाण-पत्र के साथ प्रेषित अनुदेशों के अनुसार कुछ विवरण उत्तर-पत्रक में देने हैं।

8. आप अपने सभी प्रत्युत्तरों को उत्तर-पत्रक में भरने के बाद तथा परीक्षा के समापन पर **केवल उत्तर-पत्रक** अधीक्षक को सौंप दें। आपको अपने साथ परीक्षण पुस्तिका ले जाने की अनुमति है।

9. कच्चे काम के लिए पत्रक, परीक्षण पुस्तिका के अन्त में संलग्न हैं।

10. **गलत उत्तरों के लिए दण्ड:**

    सभी प्रश्नों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दण्ड दिया जाएगा।

    (i) प्रत्येक के लिए चार वैकल्पिक उत्तर है। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए हेतु नियत किए गए अंकों का एक-तिहाई दण्ड के रूप में काटा जाएगा।

    (ii) यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा, यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी उस के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जाएगा।

    (iii) यदि उम्मीदवार द्वारा कोई हल नहीं किया जाता है अर्थात् उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस के लिए कोई दण्ड नहीं दिया जाएगा।

11. **प्रश्नों से संबंधित चुनौती/आपत्ति:** यदि छात्रों को लगता है कि या तो प्रश्न/उत्तरों को संशोधित करने की आवश्यकता है या स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो वे pts@nextias.com पर ई-मेल कर सकते हैं।

जब तक आपको यह परीक्षण पुस्तिका खोलने को न कहा जाए तब तक न खोलें।

DO NOT OPEN THIS TEST BOOKLET UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SO

INSTRUCTIONS

1. IMMEDIATELY AFTER THE COMMENCEMENT OF THE EXAMINATION, YOU SHOULD CHECK THAT THIS TEST BOOKLET DOES ***NOT*** HAVE ANY UNPRINTED OR TORN OR MISSING PAGES OR ITEMS, ETC. IF SO, GET IT REPLACED BY A COMPLETE TEST BOOKLET.

2. **Please note that it is the candidate's responsibility to encode and fill in the Roll Number and Test Booklet Series A or B carefully and without any omission or discrepancy at the appropriate places in the OMR Answer Sheet. Any omission/kdiscrepancy will render the Answer Sheet liable for rejection.**

3. You have to enter your Roll Number on the Test Booklet in the box provided alongside.

4. This Test Booklet contains **100** items (Questions). Each item is printed in **Hindi** and **English** only. Each item comprises four responses (Answers). You will select the response which you want to mark on the Answer Sheet. In case you feel that there is more than one correct response, mark the response which you consider the best. In any case, choose ***ONLY ONE*** response for each item.

5. You have to mark all your responses ***ONLY*** on the separate answer sheet provided. See directions in the Answer Sheet.

6. ***All*** items carry equal marks.

7. Before you proceed to mark in the Answer Sheet the response to various items in the Test Booklet, you have to fill in some particulars in the Answer Sheet as per instructions sent to you with your Admission Certificate.

8. After you have completed filling in all your responses on the Answer Sheet and the examination has concluded, you should hand over to the invigilator ***only the Answer Sheet.*** You are permitted to take away with you the Test Booklet.

9. Sheets for rough work are appended in the Test Booklet at the end.

10. **Penalty for wrong answers:**

    THERE WILL BE PENALTY FOR WRONG ANSWERS MARKED BY A CANDIDATE IN THE OBJECTIVE.

    (i) There are four alternatives for the answer to every question. For each question for which a wrong answer has been given by the candidate, **one-third** of the marks assigned to that question will be deducted as penalty.

    (ii) If a candidate gives more than one answer, it will be treated as a **wrong answer** even if one of the given answers happens to be correct and there will be same penalty as above to that question.

    (iii) If question is left blank, i.e., no answer is given by the candidate, there will be **no penalty** for that question.

11. **CHALLENGE THE QUESTION:** If students feel that either the question(s)/kanswer(s) needs to be modified or require clarification, they can email at **pts@nextias.com**

DO NOT OPEN THIS TEST BOOKLET UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SO

1. एक सार्वजनिक प्राधिकरण किसी महिला उम्मीदवार को उसकी वैवाहिक स्थिति का उल्लेख करते हुए सरकारी पद के लिए आवेदन करने से अयोग्य घोषित कर देता है, हालाँकि भर्ती नियमों में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। इस स्थिति में उसके लिए निम्नलिखित में से कौन-सी रिट सबसे उपयुक्त है?

(a) अधिकार पृच्छा
(b) उत्प्रेषण
(c) बंदी प्रत्यक्षीकरण
(d) परमादेश

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत में किसी राज्य का विभाजन (Bifurcation) संसद द्वारा साधारण बहुमत (Simple Majority) से बनाए गए कानून के माध्यम से किया जाता है।
2. भारत की किसी भूमि को किसी विदेशी देश को सौंपने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है।
3. भारत सरकार सीमावर्ती विवादों को पड़ोसी देशों के साथ कार्यपालिकीय कार्रवाई (Executive action) के माध्यम से सुलझा सकती है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई नहीं

3. भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए:

1. राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत
2. मूल अधिकार
3. मूल कर्त्तव्य

उपर्युक्त प्रावधानों में से कितने विधायिका और कार्यपालिका की स्वेच्छाचारी कार्रवाइयों पर सीमाएँ आरोपित करते हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई नहीं

4. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य किसी भी मूल अधिकार का हनन करने वाली कोई विधि नहीं बनाएगा। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत "विधि" की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन-से शामिल हैं?

1. अध्यादेश
2. नियम और विनियम
3. विधि का प्रभाव रखने वाली परंपरा या प्रथा
4. संवैधानिक संशोधन

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1, 2 और 4
(b) केवल 1, 2 और 3
(c) केवल 2, 3 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

5. जब भारतीय संसद संविधान के अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों के प्रवेश, स्थापना या पुनर्गठन और उनकी सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित कोई कानून बनाती है, तो निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता हो सकती है?

I. पहली अनुसूची
II. दूसरी अनुसूची
III. तीसरी अनुसूची
IV. चौथी अनुसूची

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल I
(b) केवल II और IV
(c) केवल I और IV
(d) केवल III और IV

6. भारतीय संविधान के भाग III के संदर्भ में, राज्य को निम्नलिखित में से कौन-सी सकारात्मक कार्रवाई करने का अधिकार है?

1. निजी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण प्रदान करना।
2. निजी गैर-सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु नागरिकों के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान करना।

1. A public authority disqualifies a woman candidate from applying to a government post citing her marital status, though no such restriction exists in the recruitment rules. Which of the following writs is most appropriate for her to seek remedy in this scenario?
(a) Quo Warranto
(b) Certiorari
(c) Habeas Corpus
(d) Mandamus

2. Consider the following statements:
1. Bifurcation of a State within India requires a law to be enacted by the Parliament through a simple majority.
2. Ceding a part of Indian territory to a foreign country requires a Constitutional amendment.
3. The Government of India can settle boundary disputes with neighbouring countries through executive action.

How many of the statements given above are correct?
(a) Only one
(b) Only two
(c) All three
(d) None

3. Consider the following provisions of the Constitution of India:
1. Directive Principles of State Policy
2. Fundamental Rights
3. Fundamental Duties

How many of the above provisions constitute limitations on the arbitrary actions of the legislature and the executive?
(a) Only one
(b) Only two
(c) All three
(d) None

4. Article 13 of the Constitution of India states that the State shall not make any law that abridges any Fundamental Right. Which of the following are included in the definition of "law" under Article 13?
1. Ordinances
2. Rules and Regulations
3. Custom or usage having the force of law
4. Constitutional amendments

Select the correct answer using the code given below:
(a) 1, 2 and 4 only
(b) 1, 2 and 3 only
(c) 2, 3 and 4 only
(d) 1, 2, 3 and 4

5. When Indian Parliament enacts a law under Article 2 and Article 3 of the Constitution, relating to the admission, establishment, or reorganization of states and alteration of their boundaries, which of the following Schedules may require modification?
I. First Schedule
II. Second Schedule
III. Third Schedule
IV. Fourth Schedule

Select the correct answer using the code given below:
(a) I only
(b) II and IV only
(c) I and IV only
(d) III and IV only

6. With reference to Part III of the Constitution of India, the State is empowered to undertake which of the following affirmative actions?
1. Providing reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in admission to private aided educational institutions.
2. Providing reservation for economically weaker sections of citizens in admission to private unaided educational institutions.

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

7. भारत की संविधान सभा के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत और रियासत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई थीं।
2. रियासतों के प्रतिनिधियों को ब्रिटिश गवर्नरों द्वारा नामित किया गया था।
3. प्रत्येक ब्रिटिश भारतीय प्रांत में सीटें हिंदू, मुस्लिम और सामान्य लोगों के मध्य उनकी जनसंख्या के अनुसार वितरित की गई थीं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक

(b) केवल दो

(c) सभी तीन

(d) कोई नहीं

8. भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान सभा द्वारा संपूर्ण संविधान के अधिनियमन के बाद प्रस्तावना को अपनाया गया था।
2. प्रस्तावना में संविधान के प्रारंभ की तिथि 26 जनवरी, 1950 बताई गई है।
3. प्रस्तावना, संविधान का एक भाग होते हुए भी, न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 3

(d) 1, 2 और 3

9. यौन उत्पीड़न निवारण (PoSH) अधिनियम, 2013 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह अधिनियम संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के कार्यस्थलों पर लागू होता है।
2. केवल 10 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले कार्यस्थलों को ही आंतरिक शिकायत समिति (ICC) स्थापित करनी होगी।
3. यह अधिनियम केवल तभी सुरक्षा प्रदान करता है, जब पीड़ित महिला उस कार्यस्थल की कर्मचारी हो, जहाँ कथित उत्पीड़न हुआ था।
4. यह अधिनियम कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करने वाले पुरुषों या ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान नहीं करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 1, 2 और 4

(c) केवल 2, 3 और 4

(d) 1, 2, 3 और 4

10. निम्नलिखित में से कौन-सी घटना भारत के इतिहास में सबसे पहले घटित हुई?

(a) भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया जाना।

(b) संविधान सभा द्वारा "जन-गण-मन" को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया जाना।

(c) भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक।

(d) संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाया जाना।

11. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन-I:

उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय से अधिक व्यापक है।

कथन-II:

उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों में भी रिट जारी करने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य नहीं हैं।

Select the correct answer using the code given below:

(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

7. Consider the following statements with reference to the Constituent Assembly of India:

1. Seats in the Constituent Assembly were allotted to each province and princely state in proportion to their respective population.
2. Representatives of princely states were nominated by the British Governors.
3. The Seats in each British Indian Province were distributed among Hindu, Muslims and General as per their respective populations.

How many of the statements given above are correct?

(a) Only one
(b) Only two
(c) All three
(d) None

8. With reference to the Preamble of the Indian Constitution, consider the following statements:

1. The Preamble was adopted after the enactment of the entire Constitution by the Constituent Assembly.
2. Preamble mentions the date of commencement of the Constitution as 26th January 1950.
3. Preamble, though a part of the Constitution, is not enforceable by courts of law.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) 1 and 3 only
(b) 2 and 3 only
(c) 3 only
(d) 1, 2 and 3

9. Consider the following statements regarding the Prevention of Sexual Harassment (PoSH) at workplace Act, 2013:

1. The Act applies to the workplace in both organized and unorganized sectors.
2. Only the workplaces with 10 or more employees have to establish an Internal Complaints Committee (ICC).
3. The Act provides protection only if the aggrieved woman is an employee at the workplace where the alleged harassment occurred.
4. The Act does not extend protection to men or transgender individuals facing sexual harassment at the workplace.

Which of the statements given above are correct?

(a) 1 and 2 only
(b) 1, 2 and 4 only
(c) 2, 3 and 4 only
(d) 1, 2, 3 and 4

10. Which one of the following events occurred earliest in the history of India?

(a) Adoption of the National Flag by the Constituent Assembly of India.
(b) Adoption of the "Jana-gana-mana" as National Anthem of India by the Constituent Assembly.
(c) Last meeting of the Constituent Assembly of India.
(d) Adoption of the Constitution of India by the Constituent Assembly.

11. Consider the following statements:

Statement-I:

The writ jurisdiction of a High Court is wider than that of the Supreme Court.

Statement-II:

High Courts are not constitutionally bound to issue writs even in cases involving the violation of Fundamental Rights.

कथन-III:

उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों के अतिरिक्त कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकते हैं।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

(a) कथन-II और कथन-III दोनों सही हैं और दोनों, कथन-I की व्याख्या करते हैं।
(b) कथन-II और कथन-III दोनों सही हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही कथन-I की व्याख्या करता है।
(c) कथन-II और-III में से केवल एक ही सही है और वह कथन-I की व्याख्या करता है।
(d) न तो कथन-II और न ही कथन-III सही है।

12. भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्त्तव्यों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ये 26 जनवरी, 1950 को अपनाए गए मूल संविधान में शामिल नहीं थे।
2. ये भारत के राज्य-क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं।
3. संसद कानून बनाकर मूल कर्त्तव्यों को लागू कर सकती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 2
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1 और 3
(d) केवल 1, 2 और 3

13. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के संदर्भ में निम्नलिखित परिदृश्यों पर विचार कीजिए:

1. वर्ष 2025 में एक कानून पारित किया जाता है जो किसी अपराध के लिए सज़ा को बढ़ा देता है, और एक व्यक्ति जिसने वह अपराध 2021 में किया था, उसे बढ़ी हुई सज़ा दी जाती है।
2. एक सरकारी कर्मचारी को किसी अपराध के लिए न्यायालय में अभियोजन का सामना करना पड़ता है और बाद में विभागीय जाँच के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है।
3. एक व्यक्ति को आपराधिक जाँच के दौरान अपना रक्त नमूना देने के लिए विवश किया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन-से परिदृश्य अनुच्छेद 20 का उल्लंघन माने जाएँगे?

(a) केवल 2 और 3
(b) केवल 1
(c) 1, 2 और 3
(d) कोई नहीं

14. भारतीय संविधान के तहत शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकारों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान धार्मिक और भाषायी, दोनों अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका संचालन करने का अधिकार प्रदान करता है।
2. संविधान में "अल्पसंख्यक" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है।
3. अनुच्छेद 30 सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के मामलों में नस्लीय अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 3
(d) 1, 2 और 3

15. निम्नलिखित में से कौन 'विधि की सम्यक् प्रक्रिया' की अवधारणा को 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' से उचित रूप से पृथक् करता है?

1. 'विधि की सम्यक् प्रक्रिया' न्यायिक समीक्षा को केवल कार्यपालिका के कार्यों तक सीमित रखती है, जबकि 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' केवल विधायी कार्यों पर लागू होती है।
2. 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' न्यायपालिका को कानून की निष्पक्षता और वैधता दोनों की जाँच करने में सक्षम बनाती है, जबकि 'विधि की सम्यक् प्रक्रिया' प्रक्रियात्मक अनुपालन तक ही सीमित है।

Statement-III:

High Courts can issue writs for the enforcement of legal rights beyond Fundamental Rights under Article 226.

Which one of the following is correct in respect of the above statements?

(a) Both Statement-II and Statement-III are correct and both of them explain Statement-I
(b) Both Statement-II and Statement-III are correct, but only one of them explain Statement-I
(c) Only one of the Statements II and III is correct and that explains Statement-I
(d) Neither Statement-II nor Statement-III is correct

12. With reference to Fundamental Duties under the Constitution of India, consider the following statements:

1. These were not present in the original Constitution adopted on 26th January 1950.
2. They are applicable to all persons residing in the territory of India.
3. Parliament can enforce the Fundamental duties by enacting a law.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) 2 only
(b) 1 and 2 only
(c) 1 and 3 only
(d) 1, 2 and 3

13. Consider the following scenarios in the context of Article 20 of the Constitution of India:

1. A law enacted in 2025 increases the punishment for an offence, and a person who committed the offence in 2021 is awarded the enhanced punishment.
2. A government employee is prosecuted in a court for an offence and later dismissed from service after a departmental enquiry.
3. A person is compelled to give his blood sample during a criminal investigation.

Which of the above action(s) would amount to violation of Article 20?

(a) 2 and 3 only
(b) 1 only
(c) 1, 2 and 3
(d) None

14. In the context of educational and cultural rights under the Indian Constitution, consider the following statements:

1. The Constitution confers the right on both religious and linguistic minorities to establish and administer educational institutions of their choice.
2. The term "minority" has not been defined in the Constitution.
3. Article 30 protects the interests of racial minorities in matters of cultural and educational rights.

Which of the above statements is/are correct?

(a) 1 only
(b) 1 and 2 only
(c) 3 only
(d) 1, 2 and 3

15. Which of the following correctly distinguishes the concept of 'Due Process of Law' from 'Procedure Established by Law'?

1. 'Due Process of Law' restricts judicial review to executive actions only, while 'Procedure Established by Law' applies exclusively to legislative actions.
2. 'Procedure Established by Law' enables the judiciary to examine both the fairness and validity of a law, whereas 'Due Process of Law' is confined to procedural compliance.

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

16. निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए:

1. संयुक्त राज्य अमेरिका
2. मैक्सिको
3. क्यूबा
4. होंडुरास
5. ग्वाटेमाला

उपर्युक्त देशों में से कौन-से मैक्सिको की खाड़ी की सीमा पर स्थित हैं?

(a) केवल 1, 2 और 3
(b) केवल 1, 3 और 4
(c) केवल 1, 2 और 5
(d) केवल 2, 3, 4 और 5

17. पनामा नहर के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. पनामा नहर आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है।
2. यह नहर उत्तरी अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों के मध्य समुद्री दूरी को बहुत कम कर देती है।
3. वर्ष 1999 में हस्ताक्षरित स्थायी तटस्थता संधि के तहत इसका प्रशासनिक नियंत्रण संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3
(b) केवल 2
(c) केवल 1 और 2
(d) 1, 2 और 3

18. हाल ही में ख़बरों में रहने वाला फ़िलाडेल्फी कॉरिडोर, भूमि की एक संकरी पट्टी है, जो निम्नलिखित के बीच स्थित है:

(a) इज़राइल और लेबनान
(b) गज़ा पट्टी और मिस्र
(c) वेस्ट बैंक और जॉर्डन
(d) सीरिया और इराक

19. भारत निम्नलिखित में से कौन-से समूहों का सदस्य है?

1. क्वाड
2. ऑकस (AUKUS)
3. ब्रिक्स
4. फाइव आईज़ अलायंस

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1, 2 और 3
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

20. नीति आयोग के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है।
2. यह न तो संवैधानिक निकाय है और न ही वैधानिक निकाय है।
3. सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शासी परिषद् (Governing Council) के सदस्य हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

21. निम्नलिखित में से कौन-से मूल अधिकार भारत के नागरिक को प्राप्त हैं, लेकिन भारत में रहने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के नागरिक को प्राप्त नहीं हैं?

1. विधि के समक्ष समता का अधिकार
2. धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध
3. धर्म के अनुपालन और प्रचार की स्वतंत्रता
4. कोई भी वृत्ति अपनाने या व्यवसाय करने का अधिकार
5. भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार

Select the correct answer using the code given below:
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

16. Consider the following countries:
1. United States of America
2. Mexico
3. Cuba
4. Honduras
5. Guatemala

Which of the above countries border the Gulf of Mexico?
(a) 1, 2 and 3 only
(b) 1, 3 and 4 only
(c) 1, 2 and 5 only
(d) 2, 3, 4 and 5 only

17. With reference to the Panama Canal, consider the following statements:
1. The Panama Canal connects the Arctic Ocean with the Pacific Ocean.
2. The canal significantly shortens the maritime distance between the east and west coasts of North America.
3. It is administratively controlled by the USA under the Permanent Neutrality Treaty signed in 1999.

Which of the statements given above is/are correct?
(a) 1 and 3 only
(b) 2 only
(c) 1 and 2 only
(d) 1, 2 and 3

18. The Philadelphi Corridor, recently seen in the news, is a narrow strip of land located between:
(a) Israel and Lebanon
(b) Gaza Strip and Egypt
(c) West Bank and Jordan
(d) Syria and Iraq

19. Which of the following groupings involve India as a member?
1. Quad
2. AUKUS
3. BRICS
4. Five Eyes Alliance

Select the correct answer using the code given below:
(a) 1, 2 and 3 only
(b) 1 and 3 only
(c) 2, and 4 only
(d) 1, 2, 3 and 4

20. With reference to NITI Aayog, consider the following statements:
1. The Prime Minister of India is the Ex-officio Chairperson of NITI Aayog.
2. It is neither a Constitutional nor a statutory body.
3. Chief Ministers of all States are members of the Governing Council.

Which of the statements given above are correct?
(a) 1 and 2 only
(b) 2 and 3 only
(c) 1 and 3 only
(d) 1, 2 and 3

21. Which of the following Fundamental Rights are available to a citizen of India but not to a citizen of the United States of America (USA) living in India?
1. Right to Equality before Law
2. Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth
3. Freedom of practice and propagation of religion
4. Right to practice any profession, or to carry on any occupation
5. Right to move freely throughout the territory of India

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2, 3 और 4
(c) केवल 2, 4 और 5
(d) केवल 1, 2, 3 और 4

22. निम्नलिखित में से कौन-सा मूल अधिकार बच्चों को खतरनाक कामों में लगाने से रोकता है?

(a) स्वतंत्रता का अधिकार
(b) शोषण के विरुद्ध अधिकार
(c) समता का अधिकार
(d) जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार

23. भारत के प्रवासी नागरिक (OCI) कार्डधारकों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अनिवासी भारतीयों (NRI) के विपरीत, OCI कार्डधारक भारत के नागरिक नहीं हैं।
2. OCI कार्डधारक भारत में सार्वजनिक पद धारण करने के हकदार नहीं हैं।
3. उन्हें भारत में किसी भी अवधि के प्रवास हेतु स्थानीय पुलिस प्राधिकरण के साथ पंजीकरण नहीं कराना होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

24. भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह संविधान सभा में डॉ. बी.आर. अंबेडकर द्वारा तैयार और प्रस्तुत 'उद्देश्य प्रस्ताव' पर आधारित है।
2. यह विधायिका और न्यायपालिका के लिए शक्ति के स्रोत के रूप में कार्य करती है।
3. संविधान के लागू होने के बाद से इसमें केवल एक बार संशोधन किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 3
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

25. संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए:

1. समाजवादी
2. पंथनिरपेक्ष
3. एकता
4. अखंडता

उपर्युक्त में से कौन-से शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम (1976) द्वारा जोड़े गए थे?

(a) केवल 1, 2 और 3
(b) केवल 2, 3 और 4
(c) केवल 1, 2 और 4
(d) केवल 1, 3 और 4

26. नीचे दी गई किन परिस्थितियों में कोई भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता खो सकता है?

1. यदि कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है।
2. यदि पंजीकरण के बाद पाँच वर्षों के भीतर किसी नागरिक को किसी देश में कम-से-कम दो वर्ष की अवधि के कारावास की सज़ा सुनाई गई हो।
3. यदि कोई नागरिक लगातार पाँच वर्षों तक सामान्यत: भारत से बाहर निवासी रहा हो।
4. जब कोई व्यक्ति युद्ध के दौरान दुश्मन देश के साथ अवैध रूप से व्यापार या संचार करता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 4
(b) केवल 2, 3 और 4
(c) केवल 1, 2 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

Select the correct answer using the code given below:

(a) 1 and 2 only
(b) 2, 3 and 4 only
(c) 2, 4 and 5 only
(d) 1, 2, 3 and 4 only

22. Which one of the following categories of Fundamental Rights prohibits the employment of the children in hazardous work?

(a) Right to freedom
(b) Right against exploitation
(c) Right to equality
(d) Right to life and personal liberty

23. With respect to the Overseas Citizen of India (OCI) Cardholders, consider the following statements:

1. Unlike Non-Resident Indians (NRIs), OCI cardholders are not citizens of India.
2. OCI cardholders are not entitled to hold public offices in India
3. They are exempted from registration with local police authority for any length of stay in India.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) 1 only
(b) 3 only
(c) 1 and 3 only
(d) 1, 2 and 3

24. Consider the following statements about the Preamble to the Indian Constitution:

1. It is based on the 'Objectives Resolution' drafted and moved by Dr. B.R. Ambedkar in the Constituent Assembly.
2. It serves as a source of power for the legislature and the judiciary.
3. It has been amended only once since the commencement of the Constitution.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) 1 and 2 only
(b) 3 only
(c) 2 and 3 only
(d) 1, 2 and 3

25. With reference to the Preamble of the Constitution, consider the following terms:

1. Socialist
2. Secular
3. Unity
4. Integrity

Which of the above were added by the 42nd Constitutional Amendment Act (1976)?

(a) 1, 2 and 3 only
(b) 2, 3 and 4 only
(c) 1, 2 and 4 only
(d) 1, 3 and 4 only

26. In which of the situations stated below, an Indian citizen can lose his/her citizenship?

1. If an Indian Citizen acquires citizenship of another country.
2. If a Citizen within five years after the registration, has been sentenced in any country to imprisonment for a term of not less than two years
3. If a citizen has been ordinarily resident out of India for five years continuously.
4. When a person illegally traded or communicated with the enemy during war.

Select the correct answer using the code given below:

(a) 1 and 4 only
(b) 2, 3 and 4 only
(c) 1, 2 and 4 only
(d) 1, 2, 3 and 4

27. संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों के अंत के संबंध में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?

1. राज्य को किसी भी प्रकार की उपाधि प्रदान करने से प्रतिबंधित किया गया है, सिवाय सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टता को दर्शाने वाली उपाधियों के।
2. यह भारतीय नागरिकों को किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगाता है।
3. यह राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का कोई भी पद धारण करने वाले नागरिकों को प्रधानमंत्री की पूर्व स्वीकृति से उपाधियाँ स्वीकार करने की अनुमति देता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3
(d) केवल 3

28. भारतीय संविधान के भाग IV में राज्य के लिए कुछ नीतिगत निर्देश दिए गए हैं। इनमें से एक, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 50 में किया गया है, कहता है कि "राज्य, राज्य की लोक सेवाओं में _____ के लिए कदम उठाएगा।"

रिक्त स्थान भरने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए:

(a) न्यायपालिका को विधायिका से अलग करना सुनिश्चित करने
(b) न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना सुनिश्चित करने
(c) विधायिका को कार्यपालिका से अलग करना सुनिश्चित करने
(d) न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका को अलग करना सुनिश्चित करने

29. भारत के संविधान के अंतर्गत निवारक निरोध (Preventive Detention) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. निवारक निरोध के अंतर्गत निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधारों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।
2. हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
3. निवारक निरुद्ध व्यक्ति को निरुद्ध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन देने का अधिकार है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई नहीं

30. भारतीय नागरिकता के प्रावधानों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत का संविधान, संविधान लागू होने के बाद वंशानुक्रम और राज्यक्षेत्र के समावेशन के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रदान करता है।
2. नागरिकता अधिनियम, 1955 पंजीकरण और देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का प्रावधान करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

31. भारतीय इतिहास के संदर्भ में, रानी वेलु नचियार को निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है?

(a) किसी भारतीय रानी द्वारा ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रथम सशस्त्र प्रतिरोध का नेतृत्व करने के लिए।
(b) तमिलनाडु से ब्रिटिशों को निष्कासित करने हेतु डचों के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए।
(c) ब्रिटिशों के साथ औपचारिक रूप से सहायक संधि स्वीकार करने वाली पहली भारतीय शासक होने के लिए।
(d) इंडियन नेशनल आर्मी में एक महिला रेजिमेंट की स्थापना करने के लिए।

27. Which of the following statements regarding the abolition of titles under Article 18 of the Constitution is ***not*** correct?

1. State is prohibited from conferring any title, except those signifying military or academic distinction.
2. It prohibits Indian citizens from accepting any titles from a foreign State.
3. It allows citizens holding any office of profit or trust under the State to accept titles with prior approval of the Prime minister.

Select the correct answer using the code given below:

(a) 1 and 2 only
(b) 2 only
(c) 1 and 3 only
(d) 3 only

28. The Indian Constitution in Part IV lays down certain policy directives for the State to follow. One of these, mentioned in Article 50, states that "The State shall take steps to _____ in the public services of the State."

Choose the correct option to fill in the blank:

(a) ensure separation of judiciary from legislature
(b) ensure separation of judiciary from executive
(c) ensure separation of legislature from executive
(d) ensure separation of judiciary, legislature, and executive

29. With reference to preventive detention under the Constitution of India, consider the following statements:

1. A person detained under preventive detention must be informed of the grounds for detention as soon as possible.
2. It is mandatory to produce the person before a magistrate within 24 hours of detention.
3. The person detained preventively has the right to make a representation against the detention order.

How many of the above statements are correct?

(a) Only one
(b) Only two
(c) All three
(d) None

30. With reference to the provisions of Indian citizenship, consider the following statements:

1. The Constitution of India provides procedure for acquisition of citizenship through descent and incorporation of territory after the commencement of Constitution.
2. The Citizenship Act, 1955 provides for acquisition of citizenship by registration and naturalisation.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

31. With reference to Indian history, Rani Velu Nachiyar is best known for:

(a) Leading the first recorded armed resistance against British colonial rule by an Indian queen.
(b) Signing a treaty with the Dutch to expel the British from Tamil Nadu.
(c) Being the first Indian ruler to formally accept a subsidiary alliance with the British.
(d) Establishing a women's regiment in the Indian National Army.

32. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

	पुरस्कार	विवरण
1.	अर्जुन पुरस्कार	विगत् चार वर्षों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन के साथ-साथ नेतृत्व, खेल भावना और अनुशासन की भावना दर्शाने के लिए
2.	द्रोणाचार्य पुरस्कार	खेलों और क्रीड़ाओं में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए
3.	मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार	खेलों और क्रीड़ाओं में आजीवन योगदान के लिए

उपर्यक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

33. निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए:

1. इथोपिया
2. मिस्र
3. इंडोनेशिया
4. ईरान
5. इराक

उपर्युक्त में से कौन-से देश BRICS समूह के सदस्य हैं?

(a) केवल 1, 2 और 4
(b) केवल 2, 3 और 5
(c) केवल 1, 2, 3 और 4
(d) केवल 3, 4 और 5

34. वर्ष 2024 में जारी की गई "बिजनेस रेडी (B-READY)" रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख प्रकाशन है?

(a) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
(b) विश्व बैंक समूह
(c) विश्व आर्थिक मंच
(d) आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD)

35. सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. एक अभिभावक केवल तभी SSY खाता खोल सकता है, जब बालिका की आयु 10 वर्ष से कम हो।
2. SSY खाता खोलने की तिथि से अधिकतम पंद्रह वर्षों तक ही खाते में राशि जमा की जा सकती है।
3. SSY खाते को केवल खाताधारक की मृत्यु की स्थिति में ही समय से पहले बंद किया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

36. अनुच्छेद 25 के अंतर्गत निम्नलिखित घटकों का उनके सही विवरण से मिलान कीजिए:

	सूची-I		सूची-II
A.	अंत:करण की स्वतंत्रता	1.	धार्मिक आस्था और विश्वास की घोषणा
B.	धर्म को मानने का अधिकार	2.	ईश्वर के साथ अपने संबंध को आकार देने की आंतरिक स्वतंत्रता
C.	धर्म के आचरण का अधिकार	3.	दूसरों तक धार्मिक विश्वासों का प्रसार
D.	धर्म के प्रचार का अधिकार	4.	धार्मिक अनुष्ठान और समारोह करना

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) A-2, B-1, C-4, D-3
(b) A-1, B-2, C-3, D-4
(c) A-3, B-1, C-4, D-2
(d) A-4, B-3, C-1, D-2

37. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(A) के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन-से नागरिकों के मूल कर्त्तव्य हैं?

1. देश की समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्त्व देना और उसका संरक्षण करना।
2. सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा का परित्याग करना।

32. Consider the following pairs:

	Award	*Description*
1.	Arjuna Awards	For good performance over a period of the previous four years and for showing qualities of leadership, sportsmanship and a sense of discipline.
2.	Dronacharya Award	For outstanding coaches in sports and games
3.	Major Dhyan Chand Khel Ratna Award	For lifetime contribution to sports and games

Which of the pairs given above is/are correct?

(a) 1 and 2 only
(b) 2 only
(c) 1 and 3 only
(d) 1, 2 and 3

33. Consider the following countries:

1. Ethiopia
2. Egypt
3. Indonesia
4. Iran
5. Iraq

Which of the above countries are members of the BRICS organisation?

(a) 1, 2 and 4 only
(b) 2, 3 and 5 only
(c) 1, 2, 3 and 4 only
(d) 3, 4 and 5 only

34. The "Business Ready (B-READY)" report, launched in 2024, is a flagship publication of which of the following?

(a) International Monetary Fund
(b) World Bank Group
(c) World Economic Forum
(d) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

35. With reference to the Sukanya Samriddhi Yojana (SSY), consider the following statements:

1. A guardian can open the SSY account only until the girl child attains the age of 10 years.
2. Deposits into the SSY account can be made for a maximum of fifteen years from the date of account opening.
3. Early closure of the SSY account is permitted only in case of the account holder's death.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) 1 and 2 only
(b) 2 only
(c) 1 and 3 only
(d) 1, 2 and 3

36. Match the following components under Article 25 with their correct descriptions:

	List-I		*List-II*
A.	Freedom of conscience	1.	Declaration of religious faith and belief
B.	Right to profess	2.	Inner freedom to shape one's relationship with God
C.	Right to practice	3.	Dissemination of religious beliefs to others
D.	Right to propagate	4.	Performing religious rituals and ceremonies

Select the correct answer using the code given below:

(a) A-2, B-1, C-4, D-3
(b) A-1, B-2, C-3, D-4
(c) A-3, B-1, C-4, D-2
(d) A-4, B-3, C-1, D-2

37. Which of the following are the Fundamental Duties of citizens as per Article 51A of the Indian Constitution?

1. To value and preserve the rich heritage of the country's composite culture.
2. To safeguard public property and to abjure violence.

3. प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना तथा जीवित प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

38. यह रिट सामान्य तौर पर उच्चतर न्यायालय द्वारा निचली अदालत को तब जारी की जाती है, जब निचली अदालत ने अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण किया हो या किसी ऐसे मामले पर निर्णय लिया हो, जिसके लिए उसके पास कोई क्षेत्राधिकार नहीं था। यह एक प्रकार की उपचारात्मक रिट होती है, क्योंकि यह किसी मामले में निचली अदालत के आदेश को रद्द/निरस्त करने के लिए जारी की जाती है।

उपर्युक्त अनुच्छेद में, निम्नलिखित में से किस रिट का वर्णन किया गया है?

(a) परमादेश
(b) उत्प्रेषण
(c) प्रतिषेध
(d) अधिकार-पृच्छा

39. विभिन्न स्रोतों से प्राप्त भारतीय संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

	विशेषताएँ	प्रेरणा स्रोत
1.	राज्यपाल का पद	1935 का भारत सरकार अधिनियम
2.	उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाना	अमेरिका का संविधान
3.	समवर्ती सूची (सातवीं अनुसूची के अंतर्गत)	कनाडा का संविधान

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-से सही सुमेलित हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

40. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन-I:

राज्य सभी बच्चों को छह वर्ष की आयु पूरी होने तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा।

कथन-II:

शिक्षा का उल्लेख भारतीय संविधान के राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों और मूल कर्त्तव्यों, दोनों में मिलता है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

(a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या है।
(b) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं, तथा कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है।
(c) कथन-I सही है, लेकिन कथन-II गलत है।
(d) कथन-I गलत है, लेकिन कथन-II सही है।

41. भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों द्वारा मूल अधिकारों के प्रयोग पर निम्नलिखित प्रतिबंधों पर विचार कीजिए:

1. विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध
2. किसी अपराध के लिए उकसाना
3. किसी भी अनुसूचित जनजाति के हितों का संरक्षण
4. लोक व्यवस्था

उपर्युक्त में से कौन-से अनुच्छेद 19 के तहत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग पर वैध प्रतिबंध हैं?

(a) केवल 1, 2 और 3
(b) केवल 2, 3 और 4
(c) केवल 1, 2 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

3. To protect and improve the natural environment and to have compassion for living creatures.

Select the correct answer using the code given below:
(a) 1 and 2 only
(b) 2 and 3 only
(c) 1 and 3 only
(d) 1, 2 and 3

38. "This writ is usually issued by a higher court to a lower court when the lower court has exceeded its jurisdiction or when it has dealt with a case for which it did not have any jurisdiction. It is in the nature of a curative writ since it is issued to quash/squash the order of a lower court in a case".

Which of the following writs is described in the above paragraph?
(a) Mandamus
(b) Certiorari
(c) Prohibition
(d) Quo Warranto

39. In the context of the features of the Indian Constitution drawn from various sources, consider the following pairs:

	Feature	*Inspired from*
1.	Office of Governor	Government of India Act of 1935
2.	Removal of Judges of Supreme Court and High Court	US Constitution
3.	Concurrent List (under VII Schedule)	Canadian Constitution

Which of the pairs given above are correctly matched?
(a) 1 and 2 only
(b) 2 and 3 only
(c) 1 and 3 only
(d) 1, 2 and 3

40. Consider the following statements:

Statement-I:

The State shall provide free and compulsory education to all children until they complete the age of six years.

Statement-II:

Education finds mention in both the Directive Principles of State Policy and the Fundamental Duties under the Constitution of India.

Which one of the following is correct in respect of the above statements?
(a) Both Statement-I and Statement-II are correct and Statement-II is the correct explanation for Statement-I
(b) Both Statement-I and Statement-II are correct, but Statement-II is not the correct explanation for Statement-I
(c) Statement-I is correct, but Statement-II is incorrect
(d) Statement-I is incorrect, but Statement-II is correct

41. Consider the following restrictions under the Constitution on the exercise of Fundamental Rights by citizens in India:
1. Friendly relations with Foreign States
2. Incitement to an offence
3. Protection of the interests of any Scheduled Tribes
4. Public order

Which of the above constitute valid restrictions on the exercise of the Right to Freedom of speech and expression under Article 19?
(a) 1, 2 and 3 only
(b) 2, 3 and 4 only
(c) 1, 2 and 4 only
(d) 1, 2, 3 and 4

42. भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के विरुद्ध अधिकार को मान्यता दी है?

(a) अनुच्छेद 48(A)
(b) अनुच्छेद 14 और 21
(c) अनुच्छेद 51(A)
(d) अनुच्छेद 21 और 48(A)

43. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

	भारतीय संविधान सभा द्वारा नियुक्त समितियाँ	अध्यक्ष
1.	प्रारूप समिति	बी.एन. राव
2.	प्रांतीय संविधान समिति	सरदार पटेल
3.	कार्यविधि नियम समिति	डॉ. राजेंद्र प्रसाद

उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई नहीं

44. समान नागरिक संहिता के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत का संविधान राज्य को यह निर्देश देता है कि वह पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रयास करे।
2. केवल संसद ही समान नागरिक संहिता पर कानून बना सकती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

45. भारतीय संविधान के मूल अंग्रेजी संस्करण की सुंदर हस्तलिपि (Calligraphy) प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से किसने इसके हिंदी संस्करण की हस्तलिपि की थी?

(a) नंदलाल बोस
(b) वसंत कृष्ण वैद्य
(c) व्यौहार राम मनोहर सिन्हा
(d) एस.एन. बापना

46. भारतीय राजव्यवस्था के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत के संविधान के अनुसार, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत देश के शासन का आधार हैं।
2. उच्चतर न्यायपालिका कुछ कानूनों को इस आधार पर अमान्य घोषित कर सकती है कि वे राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

47. निम्न में से कौन-सा कथन कठोर (Rigid) और लचीले (Flexible) संविधान के मध्य मुख्य अंतर को सही ढंग से दर्शाता है?

(a) एक कठोर संविधान में संशोधन केवल न्यायपालिका द्वारा किया जा सकता है, जबकि एक लचीले संविधान में संशोधन विधायिका द्वारा किया जा सकता है।
(b) एक कठोर संविधान में संशोधन के लिए सामान्य विधायी प्रक्रिया से अलग एक विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, जबकि एक लचीले संविधान में सामान्य विधायी प्रक्रिया के माध्यम से संशोधन किया जा सकता है।
(c) एक लचीला संविधान हमेशा अलिखित होता है और परंपराओं पर आधारित होता है, जबकि एक कठोर संविधान अनिवार्य रूप से लिखित और विस्तृत होता है।
(d) एक कठोर संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होता, जबकि एक लचीले संविधान में कभी भी स्वतंत्र रूप से संशोधन किया जा सकता है।

42. Under which of the following Article(s) of the Constitution of India, has the Supreme Court of India recognised the Right against the Adverse Effects of Climate Change?
(a) Article 48A
(b) Article 14 and 21
(c) Article 51A
(d) Article 21 and 48A

43. Consider the following pairs:

	Committees appointed by the Constituent Assembly of India	*Chairman*
1.	Drafting Committee	B. N. Rau
2.	Provincial Constitution Committee	Sardar Patel
3.	Rules of Procedure Committee	Dr. Rajendra Prasad

How many of the above pairs are correctly matched ?
(a) Only one
(b) Only two
(c) All three
(d) None

44. With reference to Uniform Civil Code, consider the following statements:
1. The Constitution of India directs the State to make efforts to ensure that a Uniform Civil Code is implemented across the entire country.
2. Only Parliament can make laws on Uniform Civil Code.

Which of the statements given above is/are correct?
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

45. Prem Behari Narain Raizada was the calligrapher of the English version of the original Constitution of India. Who among the following did the calligraphy of its Hindi version?
(a) Nandalal Bose
(b) Vasant Krishan Vaidya
(c) Beohar Rammanohar Sinha
(d) S.N. Bapna

46. With reference to the Indian Polity, consider the following statements :
1. According to the Constitution of India, Directive Principles of State Policy are fundamental in the governance of the country.
2. Higher Judiciary can declare certain laws to be invalid on the ground that it contravenes a Directive Principle of State Policy.

Which of the statements given above is/are correct?
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

47. Which of the following statements accurately reflects the key distinction between rigid and flexible Constitutions?
(a) A rigid Constitution can be amended only by the judiciary, while a flexible Constitution can be amended by the legislature.
(b) A rigid Constitution requires a procedure distinct from ordinary legislation for its amendment, whereas a flexible Constitution can be amended through the normal legislative process.
(c) A flexible Constitution is always unwritten and based on customs, while a rigid Constitution is necessarily written and exhaustive.
(d) A rigid Constitution does not permit any amendments, while a flexible Constitution can be changed freely at any time.

48. सूची-I में दिए गए संविधान संशोधन अधिनियमों का मिलान सूची-II में दिए गए उनके द्वारा जोड़े या संशोधित किए गए नीति निदेशक तत्त्वों (Directive Principles) से कीजिए:

	सूची-I (संविधान संशोधन अधिनियम)		सूची-II (नीति निदेशक तत्त्व)
A.	44वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (1978)	1.	सहकारी समितियों को बढ़ावा देना
B.	86वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (2002)	2.	प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा
C.	97वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (2011)	3.	आय और अवसरों में असमानता को न्यूनतम करना

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए:
(a) A–1, B–2, C–3
(b) A–3, B–2, C–1
(c) A–2, B–1, C–3
(d) A–2, B–3, C–1

49. भारतीय संविधान में राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों (Directive Principles of State Policy) में से कुछ गाँधीवादी सिद्धांतों को दर्शाते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा इनमें से एक नहीं है?
(a) ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना
(b) स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेयों और नशीले पदार्थों पर निषेध लगाना
(c) पशु नस्लों के संरक्षण और सुधार तथा गायों के वध पर प्रतिबंध लगाने हेतु उपाय करना
(d) नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना

50. भारतीय परिषद् अधिनियम, 1909 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसने मुसलमानों के लिए पृथक् निर्वाचन की शुरुआत की।
2. इसने वायसराय की कार्यकारी परिषद् में भारतीयों को शामिल होने की अनुमति दी।
3. इसने एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया।
4. इसने केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर विधान परिषदों की सदस्य संख्या बढ़ाई।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(a) केवल 1 और 3
(b) केवल 2 और 4
(c) केवल 1, 2 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

51. भारतीय संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों (DPSPs) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ये भारत सरकार अधिनियम, 1935 में शामिल "निर्देश उपकरणों (Instruments of Instructions)" के समान हैं।
2. डॉ. भीमराव अंबेडकर ने निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान की नवीन विशेषताएँ (Novel features) बताया था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

52. UNFCCC को सौंपी गई भारत की चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट (BUR-4) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में भारत के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी आई है।
2. ऊर्जा क्षेत्रक को वर्ष 2020 में कुल उत्सर्जन में सबसे बड़े योगदानकर्ता के रूप में पहचाना गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

48. Match the Constitutional Amendments in List-I with the corresponding Directive Principles introduced or modified in List-II:

	List – I (Amendment Act)		*List – II (Directive Principle)*
A.	44th Amendment Act (1978)	1.	Promotion of cooperative societies
B.	86th Amendment Act (2002)	2.	Early childhood care and education
C.	97th Amendment Act (2011)	3.	Minimise inequalities in income and opportunities

Select the correct answer using the code given below:

(a) A–1, B–2, C–3
(b) A–3, B–2, C–1
(c) A–2, B–1, C–3
(d) A–2, B–3, C–1

49. Some of the Directive Principles of State Policy in the Constitution of India reflect Gandhian principles. Which of the following is ***not*** one among them?

(a) Promotion of cottage industries in rural areas.
(b) To prohibit intoxicating drinks and drugs that are injurious to health.
(c) To take steps for preserving and improving the breeds, and prohibiting the slaughter of cows.
(d) Securing uniform civil code for the citizens.

50. With reference to the Indian Councils Act, 1909, consider the following statements:

1. It introduced separate electorates for Muslims.
2. It allowed Indians to be associated with the Viceroy's Executive Council.
3. It provided for the establishment of a Public Service Commission.
4. It expanded the membership of Legislative Councils both at central and provincial level.

Which of the statements given above are correct?

(a) 1 and 3 only
(b) 2 and 4 only
(c) 1, 2 and 4 only
(d) 1, 2, 3 and 4

51. With reference to the Directive Principles of State Policy (DPSPs) in the Indian Constitution, consider the following statements:

1. They are similar in nature to the "Instruments of Instructions" contained in the Government of India Act, 1935.
2. Dr. B.R. Ambedkar described the DPSPs as the novel features of the Constitution of India.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

52. With reference to India's 4th Biennial Update Report (BUR-4) submitted to the UNFCCC, consider the following statements:

1. India's greenhouse gas emissions in 2020 declined as compared to 2019.
2. The energy sector was identified as the highest contributor to total emissions in 2020.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

53. हाल ही में भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने के मानदंडों में संशोधन करके निम्नलिखित में से कौन-सा प्रमुख मानदंड हटा दिया गया है?

(a) प्रारंभिक ग्रंथों की अत्यधिक प्राचीनता
(b) ठोस पुरातात्विक और ऐतिहासिक साक्ष्य
(c) साहित्यिक परंपरा की मौलिकता
(d) गद्यात्मक और काव्यात्मक ग्रंथों की उपलब्धता

54. निम्नलिखित में से कौन-सा प्रधानमंत्री यशस्वी योजना के प्राथमिक घटक का सर्वोत्तम वर्णन करता है?

(a) UPSC उम्मीदवारों को लक्षित करने वाले निजी कोचिंग संस्थानों के लिए विशेष वित्तपोषण प्रदान करना।
(b) ग्रामीण क्षेत्रों के सभी मेधावी छात्रों को लैपटॉप का वितरण करना।
(c) OBC, EBC, और DNT छात्रों के लिए प्री और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति तथा छात्रावास सहायता प्रदान करना।
(d) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के स्कूल छोड़ने वालों युवाओं के लिए अनिवार्य व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना।

55. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ब्रिटेन और भारत, दोनों में प्रधानमंत्री को निम्न सदन का सदस्य होना अनिवार्य है।
2. ब्रिटेन में, विधिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत वास्तविक कार्यपालिका के किसी भी सार्वजनिक कार्य से संबंधित आदेश पर किसी मंत्री द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जाता है; जबकि भारतीय संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं है।
3. राजनीतिक तटस्थता बनाए रखने के लिए अध्यक्ष द्वारा अपने राजनीतिक दल से त्याग-पत्र देने की परंपरा का पालन भारत और ब्रिटेन दोनों में किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3
(d) केवल 2

56. निम्नलिखित राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों पर विचार कीजिए:

1. राज्य आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करेगा।
2. राज्य उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा।
3. राज्य समान न्याय को बढ़ावा देगा और गरीबों को नि:शुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से निदेशक तत्त्व 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया है/जोड़े गए हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 3
(d) केवल 2 और 3

57. व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह अधिनियम मंत्रियों सहित लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार या सत्ता के दुरुपयोग की सूचनाओं को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रकट करने की अनुमति देता है।
2. यह अधिनियम सुनिश्चित करता है कि अनाम शिकायतों की अनिवार्य रूप से जाँच की जाए, यदि पर्याप्त प्रमाण सामग्री प्रस्तुत की जाती है।
3. यह अधिनियम झूठी या तुच्छ शिकायतों के लिए दण्डित करता है, जिसमें कारावास और जुर्माना शामिल है।
4. विशेष सुरक्षा समूह को इस अधिनियम के उपबंधों से छूट प्राप्त है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1, 2 और 3
(b) केवल 2, 3 और 4
(c) केवल 1, 3 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

53. Which of the following key criteria was recently dropped while revising norms for granting Classical Language status in India?
(a) High antiquity of early texts
(b) Tangible archaeological and historical evidence
(c) Originality of literary tradition
(d) Availability of prose and poetic texts

54. Which of the following best describes a primary component of the PM YASASVI Scheme?
(a) Exclusive funding for private coaching institutes targeting UPSC aspirants
(b) Distribution of laptops to all meritorious students in rural areas
(c) Provision of pre- and post-matric scholarships and hostel support for OBC, EBC, and DNT students.
(d) Mandatory vocational training for school dropouts from economically weaker sections

55. Consider the following statements:
1. In Britain as well as in India, the Prime Minister should definitely be a member of the Lower House.
2. In Britain, there is a system of legal responsibility wherein every order of the de jure Executive for any public act is countersigned by a minister, whereas there is no such provision under the Indian Constitution.
3. The Convention of the Speaker resigning from his political party to uphold political neutrality, is followed in both India and Britain.

Which of the above statements is/are correct?
(a) 1 only
(b) 1 and 3 only
(c) 2 and 3 only
(d) 2 only

56. Consider the following Directive Principles of State Policy:
1. The State shall minimise inequalities in income, status, facilities and opportunities.
2. The State shall take steps to secure the participation of workers in the management of industries.
3. The State shall promote equal justice and provide free legal aid to the poor.

Which of the above mentioned Directive Principle(s) was added to the Indian Constitution by the 42nd Amendment Act, 1976?
(a) 1 and 2 only
(b) 1 and 3 only
(c) 3 only
(d) 2 and 3 only

57. With reference to the Whistle Blowers Protection Act, 2014, consider the following statements:
1. The Act allows disclosures of corruption or misuse of power by public servants, including ministers, before a competent authority.
2. The Act ensures that anonymous complaints are mandatorily inquired into, provided sufficient material evidence is submitted.
3. The Act penalizes false or frivolous complaints with imprisonment and fine.
4. The Special Protection Group is exempt from the provisions of this Act.

Which of the statements given above are correct?
(a) 1, 2 and 3 only
(b) 2, 3 and 4 only
(c) 1, 3 and 4 only
(d) 1, 2, 3 and 4

58. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(A) के अंतर्गत मूल कर्त्तव्यों की सूची में इसके शामिल होने के बाद से केवल एक बार संशोधन किया गया है। उस संशोधन के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन-सा कर्त्तव्य जोड़ा गया था?

(a) देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना।

(b) वनों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना।

(c) सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा का परित्याग करना।

(d) छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना।

59. निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए:

1. संसद के प्रति मंत्रिपरिषद् की सामूहिक जवाबदेही
2. द्विसदनीय विधायिका की उपस्थिति
3. कार्यपालिका द्वारा निचले सदन को भंग करने का प्रावधान

उपर्युक्त में से कौन-सी विशेषताएँ संसदीय शासन प्रणाली की आवश्यक विशेषताएँ हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

60. निम्नलिखित में से कौन-सा ब्रिटिश भारत में लागू चार्टर अधिनियम, 1833 की दीर्घकालिक संवैधानिक महत्ता को सही रूप में दर्शाता है?

(a) इसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय द्वैध शासन की शुरुआत की।

(b) इसने कार्यपालिका परिषद् में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की।

(c) इसने विधायी शक्तियों का केंद्रीयकरण गवर्नर-जनरल के अधीन किया और भारत में विधि संहिताकरण (Law codification) की नींव रखी।

(d) इसने विधायिका को बजट पर चर्चा करने का अधिकार प्रदान किया।

61. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं में से एक है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई?

(a) 44वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1978

(b) 61वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1988

(c) 42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1976

(d) 86वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2002

62. निम्नलिखित में से कौन-से मूल अधिकार निजी व्यक्तियों या संस्थाओं के विरुद्ध भी प्रवर्तनीय (Enforceable) हैं?

1. मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी का प्रतिषेध
2. कारखानों में बच्चों के रोजगार का प्रतिषेध
3. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
4. अस्पृश्यता का उन्मूलन

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1, 2 और 4

(b) केवल 1, 3 और 4

(c) केवल 2, 3 और 4

(d) 1, 2, 3 और 4

63. विश्व के बहुत कम देशों का संविधान अलिखित है। निम्नलिखित में से कौन-से देश ऐसे हैं, जिनका संविधान अलिखित है?

1. इज़राइल
2. ऑस्ट्रेलिया
3. जापान

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1

(b) केवल 1 और 2

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

58. The list of Fundamental Duties under Article 51A of the Constitution of India has been amended only once since its incorporation. Which one of the following duties was added through that amendment?

(a) To defend the country and render national service when called upon to do so.
(b) To protect and improve the natural environment including forests and wildlife.
(c) To safeguard public property and abjure violence.
(d) To provide opportunities for education to children between the age of six and fourteen years.

59. Consider the following features:

1. Collective responsibility of the Council of Ministers to the Parliament.
2. Presence of a bicameral Legislature.
3. Provision of the dissolution of the Lower House by Executive.

Which of the above mentioned features is/ are considered as essential features of the Parliamentary System of Government?

(a) 1 only
(b) 1 and 3 only
(c) 2 and 3 only
(d) 1, 2 and 3

60. Which one of the following correctly identifies the long term constitutional significance of the Charter Act of 1833 introduced in British India?

(a) It introduced provincial dyarchy in British India.
(b) It introduced a portfolio system in the executive council.
(c) It centralized legislative powers with the Governor General and laid the foundation for law codification in India.
(d) It granted legislative assembly power to discuss the budget.

61. Universal adult franchise is a salient feature of the Indian Constitution. The voting age in India was reduced from 21 years to 18 years by which of the following Constitutional Amendment Acts?

(a) 44th Constitutional Amendment Act, 1978
(b) 61st Constitutional Amendment Act, 1988
(c) 42nd Constitutional Amendment Act, 1976
(d) 86th Constitutional Amendment Act, 2002

62. Which of the following Fundamental Rights are enforceable against private individuals or entities?

1. Prohibition of traffick in human beings and forced labour
2. Prohibition of employment of children in factories
3. Right to freedom of religion
4. Abolition of untouchability

Select the correct answer using the code given below:

(a) 1, 2 and 4 only
(b) 1, 3 and 4 only
(c) 2, 3 and 4 only
(d) 1, 2, 3 and 4

63. Very few countries in the world have an unwritten constitution. Which of the following countries are among them?

1. Israel
2. Australia
3. Japan

Select the correct answer using the code given below:

(a) 1 only
(b) 1 and 2 only
(c) 2 and 3 only
(d) 1, 2 and 3

64. निम्नलिखित में से कौन-सा भारत के संविधान और 1955 के नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है?

(a) पंजीकरण द्वारा
(b) क्षेत्र के विलय द्वारा
(c) किसी भारतीय नागरिक से विवाह द्वारा
(d) वंशानुक्रम द्वारा

65. डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने संविधान के किस प्रावधान को सबसे महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद बताया था और उसे भारत के संविधान की "आत्मा और हृदय" कहा था?

(a) विधि के समक्ष समानता
(b) अस्पृश्यता का उन्मूलन
(c) जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण
(d) संवैधानिक उपचारों का अधिकार

66. निम्नलिखित में से कौन-से सामान्यतः राष्ट्रपति शासन प्रणाली की तुलना में संसदीय शासन प्रणाली के लाभ माने जाते हैं?

1. यह सामान्य तौर पर कार्यपालिका और विधायिका के मध्य शक्तियों का कठोर पृथक्करण सुनिश्चित करता है।
2. यह नीति निर्माण में कार्यपालिका और विधायिका के मध्य निकटस्थ समन्वय को बढ़ावा देता है।
3. यह शासन प्रमुख के लिए एक निश्चित कार्यकाल सुनिश्चित करके नीतिगत स्थिरता को बढ़ावा देता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 3
(b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3
(d) केवल 1 और 3

67. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह नागरिकता अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत तैयार किया गया है।
2. इसमें केवल भारत के नागरिकों का विवरण दर्ज किया जाता है।
3. भारत के प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए NPR में पंजीकरण कराना स्वैच्छिक है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

68. भारत के संविधान के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन-I:

सशस्त्र बलों के सदस्यों के मूल अधिकारों को कुछ परिस्थितियों में प्रतिबंधित किया जा सकता है।

कथन-II:

संविधान संसद और राज्य विधानमंडल को सशस्त्र बलों के कार्मिकों के मूल अधिकारों के अनुप्रयोग में संशोधन करने का अधिकार देता है।

कथन-III:

सशस्त्र बलों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करने का प्रावधान केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लागू होता है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

(a) कथन-II और कथन-III दोनों सही हैं और दोनों, कथन-I की व्याख्या करते हैं।
(b) कथन-II और कथन-III दोनों सही हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही कथन-I की व्याख्या करता है।
(c) कथन-II और-III में से केवल एक ही सही है और वह कथन-I की व्याख्या करता है।
(d) न तो कथन-II और न ही कथन-III सही है।

69. भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान की संघीय विशेषता (Federal Character) इसकी मूल संरचना (Basic Structure) का हिस्सा है।
2. संविधान में कहीं भी "संघवाद" (Federalism) शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है।

64. Which of the following is ***not*** one of the ways to acquire Indian citizenship under the Constitution and the Citizenship Act of 1955?
(a) By registration
(b) By incorporation of territory
(c) By marriage to an Indian citizen
(d) By descent

65. Dr. B.R. Ambedkar referred to which provision as the most important Article of the Constitution and described it as the "heart and soul" of the Constitution of India?
(a) Equality before law
(b) Abolition of untouchability
(c) Protection of life and personal liberty
(d) Right to constitutional remedies

66. Which of the following are generally considered advantages of the Parliamentary form of government over the Presidential form?
1. It generally allows for stricter separation of powers between the executive and legislature.
2. It facilitates closer coordination between the executive and the legislature in policymaking.
3. It promotes policy stability by ensuring a fixed tenure for the head of government.

Select the correct answer using the code given below:
(a) 3 only
(b) 2 only
(c) 2 and 3 only
(d) 1 and 3 only

67. With reference to the National Population Register (NPR), consider the following statements:
1. It is prepared under the provisions of the Citizenship Act, 1955.
2. It records details of only citizens of India.
3. Registration in the NPR is voluntary for every usual resident of India.

Which of the statements given above is/are correct?
(a) 1 only
(b) 1 and 2 only
(c) 2 and 3 only
(d) 1, 2 and 3

68. With reference to the Constitution of India, consider the following statements:

Statement-I:

Fundamental Rights of members of the armed forces can be restricted in certain circumstances.

Statement-II:

The Constitution empowers Parliament and State Legislature to modify the application of Fundamental Rights to armed forces personnel.

Statement-III:

The provision to restrict Fundamental Rights of armed forces applies only during National Emergency.

Which one of the following is correct in respect of the above statements?
(a) Both Statement-II and Statement-III are correct and both of them explain Statement-I
(b) Both Statement-II and Statement-III are correct, but only one of them explains Statement-I
(c) Only one of the Statements II and III is correct and that explains Statement-I
(d) Neither Statement-II nor Statement-III is correct

69. With reference to the Constitution of India, consider the following statements:
1. The federal character of the Constitution is part of its Basic Structure.
2. The term "federalism" is not mentioned anywhere in the text of the Constitution.

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

70. भारतीय संविधान में मूल कर्त्तव्यों को निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था?

(a) सरकारिया समिति
(b) राजमन्नार समिति
(c) स्वर्ण सिंह समिति
(d) बलवंतराय मेहता समिति

71. भारत सरकार की ब्याज समकारी योजना (Interest Equalisation Scheme) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह पात्र निर्यातकों को प्री-शिपमेंट और पोस्ट-शिपमेंट गतिविधियों के लिए रुपये ऋण का एक सस्ता स्रोत प्रदान करता है।
2. इसका कार्यान्वयन भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा किया जाता है।
3. MSME क्षेत्रक के विनिर्माता इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 3
(d) केवल 2 और 3

72. प्रतिभूति लेन-देन कर (STT) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. STT भारत के मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री पर लगाया जाता है।
2. STT की दरें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
3. STT का भार स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा वहन किया जाता है और इसे निवेशकों पर नहीं डाला जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1
(c) केवल 3
(d) केवल 2 और 3

73. उजाला योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (EESL) द्वारा डिस्कॉम के सहयोग से कार्यान्वित किया जाता है।
2. यह योजना ऊर्जा-दक्ष लाइटिंग उत्पादों को केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष वित्तीय सब्सिडी के साथ प्रदान करती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

74. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:

1. मणिपुर को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ
2. नागालैंड राज्य का गठन
3. अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) 1 - 2 - 3
(b) 2 - 1 - 3
(c) 2 - 3 - 1
(d) 3 - 2 - 1

75. निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषता भारत सरकार अधिनियम, 1935 द्वारा प्रारंभ की गई थी?

(a) राज्य सचिव की सहायता के लिए "भारत परिषद्" की स्थापना
(b) प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन व्यवस्था
(c) संघीय न्यायालय की स्थापना
(d) पृथक् निर्वाचन व्यवस्था का उन्मूलन

Which of the statements given above is/are correct?
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

70. The Fundamental Duties were incorporated into the Constitution of India based on the recommendation of which one of the following Committees?
(a) Sarkaria Committee
(b) Rajamannar Committee
(c) Swaran Singh Committee
(d) Balwantrai Mehta Committee

71. Consider the following statements with reference to the Interest Equalisation Scheme of the Government of India:
1. It provides a cheaper source of rupee credit for pre-shipment and post-shipment activities to the eligible exporters.
2. It is implemented by the Reserve Bank of India (RBI).
3. MSME sector manufacturers are not eligible under this scheme.

Which of the statements given above is/are correct?
(a) 1 and 2 only
(b) 1 and 3 only
(c) 3 only
(d) 2 and 3 only

72. With reference to the Securities Transaction Tax (STT), consider the following statements:
1. STT is levied on the purchase and sale of securities listed on recognized stock exchanges in India.
2. The rates of STT are prescribed by the State Government.
3. The burden of STT is borne by the stock exchanges and is not passed on to investors.

Which of the statements given above is/are correct?
(a) 1 and 2 only
(b) 1 only
(c) 3 only
(d) 2 and 3 only

73. With reference to the UJALA scheme, consider the following statements:
1. It is implemented by Energy Efficiency Services Limited (EESL) in collaboration with DISCOMs.
2. The scheme provides energy-efficient lighting products with direct financial subsidy from the Central Government.

Which of the above statements is/are correct?
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

74. Arrange the following events in the history of post-Independence India in chronological order:
1. Manipur attained statehood
2. Formation of the State of Nagaland
3. Arunachal Pradesh attained statehood

Select the correct answer using the code given below:
(a) 1 – 2 – 3
(b) 2 – 1 – 3
(c) 2 – 3 – 1
(d) 3 – 2 – 1

75. Which of the following was a feature introduced by the Government of India Act, 1935?
(a) Establishment of "Council of India" to assist the Secretary of State
(b) Dyarchy at the provincial level
(c) Establishment of the Federal Court
(d) Abolition of separate electorates

76. भारत में जनगणना आयोजित करने के लिए उत्तरदायी महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय का प्रशासनिक नियंत्रण निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है?

(a) गृह मंत्रालय
(b) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
(c) कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
(d) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

77. संविधान के भाग III के अंतर्गत "अस्पृश्यता" के उन्मूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन निरपेक्ष और बिना किसी सशर्त के है।
2. संविधान में 'अस्पृश्यता' शब्द की स्पष्ट परिभाषा दी गई है।
3. अस्पृश्यता के कारण उत्पन्न किसी भी प्रतिबंध को लागू करना एक दण्डनीय अपराध है, चाहे वह सार्वजनिक प्राधिकारी द्वारा किया गया हो या निजी व्यक्ति द्वारा।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3
(d) केवल 2 और 3

78. भारतीय संविधान के निर्माण में अनेक महिलाओं ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा की सदस्य नहीं थीं?

(a) विजया लक्ष्मी पंडित
(b) हंसा मेहता
(c) राजकुमारी अमृत कौर
(d) प्रीतिलता वाडेकर

79. 'भूल जाने का अधिकार' (Right to be Forgotten), जिसे कभी-कभी ख़बरोंमें देखा जाता है, का तात्पर्य है:

(a) किसी व्यक्ति का यह अधिकार कि उसकी पिछली आपराधिक दोषसिद्धियों को अधिकारिक न्यायिक रिकॉर्ड से मिटा दिया जाए।
(b) किसी व्यक्ति का यह अधिकार कि उसकी सहमति के बिना मीडिया उसके संबंध में किसी घटना की रिपोर्ट न करे।
(c) किसी लेखक का यह अधिकार कि वह पहले से प्रकाशित रचना को वापस ले सके।
(d) किसी व्यक्ति का यह अधिकार कि वह डिजिटल प्लेटफॉर्म से अपने व्यक्तिगत डेटा को मिटा सके।

80. भारत का संविधान कठोर और लचीले संविधान दोनों की विशेषताओं को समाहित करता है। निम्नलिखित में से कौन-से प्रावधान इस बात को दर्शाते हैं कि संविधान लचीला है?

1. अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना
2. पाँचवीं अनुसूची के किसी भी प्रावधान में संशोधन
3. राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

81. निम्नलिखित में से किस स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के परिनियोजन की पृष्ठभूमि में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त "जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार" के उल्लंघन का सबसे प्रत्यक्ष जोखिम है?

(a) समाचार सामग्री तैयार करने के लिए एआई-आधारित प्रणालियों का उपयोग, जिससे विचारधारात्मक फिल्टर बबल्स बनते हैं।
(b) उपभोक्ताओं को उचित रूप से सूचित किए बिना विज्ञापन अभियानों में एआई-जनित वॉयसओवर का प्रयोग।
(c) न्यायालयों में एआई-सक्षम अनुवाद उपकरणों का उपयोग, जो कभी-कभी भाषायी सीमाओं के कारण गवाही का गलत अर्थ निकालते हैं।
(d) बिना किसी कानूनी ढाँचे या व्यक्तिगत सुरक्षा उपायों के, सार्वजनिक स्थानों पर एआई-आधारित निगरानी प्रणालियों की तैनाती।

76. Which of the following Ministries has administrative control over the Office of the Registrar General and Census Commissioner, responsible for conducting the Census in India?
(a) Ministry of Home Affairs
(b) Ministry of Statistics and Programme Implementation
(c) Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
(d) Ministry of Housing and Urban Affairs

77. With reference to the abolition of "untouchability" under Part III of the Constitution, consider the following statements:
1. The abolition of untouchability under Article 17 is absolute and unconditional.
2. The Constitution expressly defines the term 'untouchability'.
3. Enforcement of any disability arising out of untouchability is an offence punishable by law, whether committed by public authorities or private individuals.

Which of the statements given above is/are correct?
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) 1 and 3 only
(d) 2 and 3 only

78. Numerous women played an important role in the making of the Constitution of India. Which one of the following was ***not*** a member of the Constituent Assembly of India?
(a) Vijayalakshmi Pandit
(b) Hansa Mehta
(c) Rajkumari Amrit Kaur
(d) Pritilata Waddedar

79. 'Right to be Forgotten', sometimes seen in news, refers to:
(a) The right of a person to demand that past criminal convictions be erased from official court records
(b) The right to prevent the media from reporting on any events involving the individual without prior consent.
(c) The right of an author to withdraw a published work.
(d) The right of an individual to erase personal data from digital platforms.

80. The Constitution of India embodies features of both a rigid and a flexible constitution Which of the following provisions indicate that the Constitution is flexible?
1. Admission or establishment of new States under Article 2.
2. Amendment of any of the provisions of the Fifth schedule.
3. Manner of election of President

Select the correct answer using the code given below:
(a) 1 only
(b) 1 and 2 only
(c) 2 and 3 only
(d) 1, 2 and 3

81. In which of the following situations is there the most direct risk of infringement of the "Right to life and personal liberty" as guaranteed under Article 21 of the Indian Constitution, in the context of artificial intelligence deployment?
(a) Use of AI-based systems to curate news content that creates ideological filter bubbles.
(b) Application of AI-generated voiceovers in advertising campaigns without proper consumer disclosures.
(c) Utilisation of AI-enabled translation tools in courts that occasionally misinterpret testimony due to linguistic limitations.
(d) Deployment of AI-based surveillance systems in public spaces without a legal framework or individual safeguards.

82. स्वतंत्रता के बाद राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. जेवीपी समिति (JVP Committee) ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा को आधार के रूप में अपनाने की सिफारिश की थी।
2. आंध्र प्रदेश स्वतंत्र भारत में भाषायी आधार पर गठित पहला राज्य था।

इनमें से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, और न ही 2

83. भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन-सा प्रावधान मुख्य रूप से सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का उद्देश्य रखता है?

(a) मूल अधिकार
(b) राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व
(c) मूल कर्त्तव्य
(d) मूल अधिकार एवं मूल कर्त्तव्य दोनों

84. भारत सरकार की ई-गवर्नेंस पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

	पहल	उद्देश्य
1.	डिजिलॉकर	नागरिकों को व्यक्तिगत दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से संगृहित करने और उन तक क्लाउड-आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुँच प्रदान करता है।
2.	एंटिटी लॉकर	व्यवसायों और संगठनों को प्रमाणित डिजिटल दस्तावेज जारी करने और प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है।
3.	उमंग	एकल मोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न सरकारी सेवाओं तक एकीकृत पहुँच प्रदान करता है।

उपर्युक्त में से कौन-से युग्म सही सुमेलित हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

85. निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प भारत सरकार के PARIVESH पोर्टल का प्रमुख उद्देश्य सबसे उपयुक्त रूप से वर्णित करता है, जिसे प्रायः समाचारों में देखा जाता है?

(a) केंद्र सरकार के तहत जन शिकायत निवारण सेवाओं तक नागरिकों की पहुँच को सुविधाजनक बनाना।
(b) पर्यावरण, वन और वन्यजीव संबंधी अनुमोदनों के लिए एकल-खिड़की स्वीकृति प्रणाली प्रदान करना।
(c) संपूर्ण भारत में ग्रामीण बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना।
(d) एकीकृत मोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से रीयल-टाइम मौसम और आपदा अलर्ट प्रदान करना।

86. भारत के संविधान में शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा से संबंधित प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. किसी भी ऐसे शैक्षणिक संस्थान में जो पूर्ण रूप से राज्य के धन से संचालित होता है, धार्मिक शिक्षा निषिद्ध है।
2. राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन किसी भी विद्यार्थी को उसमें भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, और न ही 2

82. With reference to the reorganisation of States in the post-independence period, consider the following statements:

1. The JVP Committee recommended language as the basis for reorganisation of States.
2. Andhra Pradesh was the first State to be created on linguistic grounds in independent India.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

83. Which of the following provisions of the Constitution of India primarily aims to establish social and economic democracy?

(a) Fundamental Rights
(b) Directive Principles of State Policy
(c) Fundamental Duties
(d) Both Fundamental Rights and Fundamental Duties.

84. Consider the following pairs with reference to e-Governance initiatives of the Government of India:

	Initiative	*Objective*
1.	DigiLocker	Provides a cloud-based platform for citizens to store and access personal documents securely.
2.	Entity Locker	Enables businesses and organisations to issue and access verifiable digital documents.
3.	UMANG	Provides unified access to various government services through a single mobile platform.

Which of the pairs given above are correctly matched?

(a) 1 and 2 only
(b) 2 and 3 only
(c) 1 and 3 only
(d) 1, 2 and 3

85. Which of the following best describes the primary objective of the Government of India's PARIVESH Portal, often seen in news?

(a) To facilitate citizens' access to public grievance redressal services under the Central Government.
(b) To provide a single-window clearance mechanism for environmental, forest, and wildlife-related approvals.
(c) To monitor the implementation of rural infrastructure schemes across India.
(d) To offer real-time weather and disaster alerts through an integrated mobile platform.

86. With reference to the provisions of the Constitution of India regarding religious instruction in educational institutions, consider the following statements:

1. Religious instruction is prohibited in any educational institution wholly maintained out of State funds.
2. Religious instruction may be imparted in State-recognised institutions, but no student can be compelled to participate in it.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

87. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. देशी रियासतों को स्वतंत्र रहने, या भारत या पाकिस्तान में से किसी एक डोमिनियन में शामिल होने का विकल्प दिया गया था।
2. इस अधिनियम ने गवर्नर-जनरल के पद को समाप्त कर दिया और सभी कार्यपालिकीय शक्तियाँ मंत्रिपरिषद् को सौंप दीं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, और न ही 2

88. बोधगम्य भिन्नताओं (Doctrine of Intelligible Differentia) का सिद्धांत मुख्य रूप से संविधान के किस सिद्धांत की व्याख्या में लागू किया जाता है?

(a) समानता का अधिकार (Right to Equality)
(b) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Speech and Expression)
(c) जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण (Protection of Life and Personal Liberty)
(d) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religion)

89. एक स्टैंड-अप कॉमेडियन सामाजिक रीति-रिवाजों और राजनीतिक घटनाक्रमों की आलोचना करने वाला एक व्यंग्यात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत करने की योजना बना रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रदर्शन संविधान की सीमाओं के भीतर रहे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन न हो, निम्नलिखित में से कौन-सा मूल कर्तव्य सावधानीपूर्वक निभाना आवश्यक है?

1. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर अग्रसर होने का प्रयास करना।
2. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, और न ही 2

90. राज्य सभा में एक नया निदेशक सिद्धांत (Directive Principle) जोड़ने हेतु एक संविधान संशोधन विधेयक मतदान के लिए प्रस्तुत किया गया है, जहाँ 180 सदस्य उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं। यदि सदन में 10 रिक्तियाँ हैं, तो यह विधेयक केवल तब पारित किया जा सकता है, जब कम-से-कम कितने सदस्य इसका समर्थन करें?

(a) 118 सदस्य
(b) 120 सदस्य
(c) 123 सदस्य
(d) 130 सदस्य

91. भारत की संविधान सभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसने राष्ट्रमंडल (Commonwealth of Nations) की सदस्यता को स्वीकृति दी थी।
2. इसने डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया था।
3. यह 1952 में पहले आम चुनाव होने तक भारत की अस्थायी संसद में परिवर्तित हो गई थी।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

92. नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6A से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो प्राय: ख़बरों में देखी जाती है:

1. यह 1985 में हस्ताक्षरित असम समझौते के कुछ प्रावधानों को लागू करने के लिए लाई गई थी।
2. यह उन भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करती है जो 25 मार्च, 1971 से पहले असम में प्रवेश कर चुके थे।
3. यह विशेष रूप से बांग्लादेश से उत्पीड़न का शिकार धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करती है।

87. With reference to the provisions of the Indian Independence Act, 1947, consider the following statements:

1. The princely states were given the option to remain independent, or to accede to either the Dominion of India or the Dominion of Pakistan.
2. The Act abolished the office of the Governor-General and vested all executive powers in the Council of Ministers.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

88. The Doctrine of Intelligible Differentia is primarily applied in the interpretation of which of the following constitutional principles?

(a) Right to Equality
(b) Freedom of Speech and Expression
(c) Protection of Life and Personal Liberty
(d) Right to Freedom of Religion

89. A stand-up comedian plans to perform a satirical act that critiques social customs and political developments. In order to ensure that the performance remains within constitutional limits, which of the following Fundamental Duties must be consciously observed to avoid violating restrictions on the Right to Freedom of Speech and Expression?

1. To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity
2. To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India

Select the correct answer using the code given below:

(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

90. A Constitutional Amendment Bill to insert a new Directive Principle is put to vote in the Rajya Sabha, where 180 members are present and voting. If there are 10 vacancies in the House, the Bill can be passed only if it is supported by at least:

(a) 118 members
(b) 120 members
(c) 123 members
(d) 130 members

91. Consider the following statements regarding the Constituent Assembly of India:

1. It ratified India's membership of the Commonwealth of Nations.
2. It elected Dr. Rajendra Prasad as the first President of India.
3. It was converted into the Provisional Parliament of India until the first general elections were held in 1952.

Which of the statements given above are correct?

(a) 1 and 2 only
(b) 2 and 3 only
(c) 1 and 3 only
(d) 1, 2 and 3

92. Consider the following statements regarding Section 6A of the Citizenship Act, 1955, often seen in the news:

1. It was introduced to give effect to certain provisions of the Assam Accord signed in 1985.
2. It grants Indian citizenship to persons of Indian origin who entered Assam before March 25, 1971.
3. It confers citizenship exclusively on religious minorities from Bangladesh who faced persecution.

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

93. निम्नलिखित में से कौन-सा भारत के संविधान की संघात्मक (Federal) विशेषता नहीं है?

(a) कठोर संविधान
(b) द्विसदनीयता (Bicameralism)
(c) एकीकृत न्यायपालिका (Integrated Judiciary)
(d) संविधान की सर्वोच्चता

94. भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल ढाँचा सिद्धांत (Doctrine of Basic Structure) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. "मूल ढांचा" (Basic Structure) शब्द संविधान में उल्लिखित नहीं है, लेकिन संसद ने इसके दायरे को परिभाषित करने के लिए कानून बनाए हैं।
2. संविधान के अंतर्गत प्रदत्त सभी मूल अधिकारों (Fundamental Rights) को मूल संरचना का हिस्सा माना गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, और न ही 2

95. निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए:

1. किसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय निकाय में कुछ रोजगारों के लिए निवास को एक शर्त के रूप में निर्धारित करना।
2. अस्पृश्यता (Untouchability) के अपराध के लिए दण्ड निर्धारित करना।

उपर्युक्त में से किन विषयों के संबंध में भारत की संसद को विशेष रूप से कानून बनाने का अधिकार है?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, और न ही 2

96. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं?

1. संसद किसी राज्य के क्षेत्र को अलग करके या दो या अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है।
2. राष्ट्रपति को राज्य की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित किसी भी विधेयक को संबंधित राज्य विधानमंडल के पास उसके विचार हेतु भेजना आवश्यक है।
3. किसी राज्य के नाम में परिवर्तन से संबंधित विधेयक केवल राज्य सभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
4. किसी राज्य की सीमाओं या नाम में परिवर्तन के लिए संबंधित राज्य की विधानमंडल की पूर्व सहमति आवश्यक होती है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1, 2 और 3
(c) केवल 2 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

97. भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन-से उद्देश्य उल्लिखित हैं?

1. राजनीतिक न्याय
2. अवसर की समानता
3. विश्वास की स्वतंत्रता

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 3
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 2
(d) 1, 2 और 3

98. निम्नलिखित स्थितियों पर विचार कीजिए:

1. नागरिकों पर सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा थोपना

Which of the statements given above are correct?

(a) 1 and 2 only
(b) 2 and 3 only
(c) 1 and 3 only
(d) 1, 2 and 3

93. Which of the following is ***not*** a federal feature of the Constitution of India?

(a) Rigid Constitution
(b) Bicameralism
(c) Integrated Judiciary
(d) Supremacy of the Constitution

94. Consider the following statements regarding the Doctrine of Basic Structure under the Constitution of India:

1. The term "Basic Structure" is not mentioned in the Constitution, but Parliament has enacted laws to define its scope.
2. All the Fundamental Rights guaranteed under the Constitution are considered part of the Basic Structure.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

95. Consider the following matters:

1. Prescribing residence as a condition for certain employment in a state or union territory or local authority.
2. Prescribing punishment for the offence of untouchability.

The Parliament of India has the exclusive power to make laws with respect to which of the above mentioned matters?

(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

96. With reference to Article 3 of the Indian Constitution, which of the following statements are correct?

1. Parliament can form a new state by separating territory from an existing state or by merging two or more states.
2. President is required to refer any Bill related to the alteration of the boundaries of the State to the concerned State Legislature for its views.
3. A bill related to the changing the name of a State can only be introduced in Rajya Sabha.
4. The prior consent of the concerned State Legislature is mandatory for altering its boundaries or name.

Select the correct answer using the code below:

(a) 1 and 2 only
(b) 1, 2 and 3 only
(c) 2 and 4 only
(d) 1, 2, 3 and 4

97. Which of the following objectives are mentioned in the Preamble to the Constitution of India?

1. Political justice
2. Equality of opportunity
3. Liberty of faith

Select the correct answer using the code given below:

(a) 3 only
(b) 2 and 3 only
(c) 1 and 2 only
(d) 1, 2 and 3

98. Consider the following situations:

1. Imposing compulsory service on citizens for public purpose

2. सामाजिक दायित्व के कारण किसी व्यक्ति पर जबरन बंधुआ मजदूरी थोपी जाती है।
3. युद्ध के समय किसी विशेष धर्म के लोगों पर सरकार द्वारा अनिवार्य नागरिक रक्षा सेवा (Civil Defence Service) लागू करना

उपर्युक्त में से कौन-सी स्थितियाँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 का उल्लंघन होंगी?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

99. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन मूल अधिकारों और राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों (DPSP) के मध्य संवैधानिक संतुलन को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है?

(a) किसी टकराव की स्थिति में, अनुच्छेद 14 DPSP को निरस्त कर देता है।
(b) किसी भी DPSP को लागू करने के लिए बनाया गया कानून मूल अधिकारों को निरस्त कर सकता है, बशर्ते वह संविधान के मूल ढाँचे का उल्लंघन न करे।
(c) DPSP मूल अधिकारों के अधीन हैं और किसी भी परिस्थिति में उन्हें निरस्त नहीं कर सकते हैं।
(d) संसद कुछ DPSPs को लागू करने के लिए ऐसा कानून बना सकती है, जो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने पर भी अमान्य नहीं होगा।

100. निम्नलिखित में से कौन-सा संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी सामान्य कानून (Ordinary law) की वैधता को न्यायालय में चुनौती देने के लिए एकमात्र वैध आधार (Sole ground) है?

1. यह मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है।
2. यह राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों के अनुरूप नहीं है।
3. यह संविधान की मूल संरचना (Basic Structure) का उल्लंघन करता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

■■■■

2. Bonded labour enforced on a person due to social obligation.
3. Compulsory Civil Defence service imposed by the government on persons of a certain religion during times of war.

Which of the above would constitute a violation of Article 23 of the Indian Constitution?

(a) 1 only
(b) 2 only
(c) 2 and 3 only
(d) 1, 2 and 3

99. Which of the following options best reflects the constitutional balance between the Fundamental Rights and the Directive Principles of State Policy (DPSPs)?

(a) In case of a conflict, Article 14 overrides all Directive Principles of State Policy.
(b) A law enacted to implement any DPSP may override the Fundamental Rights, provided it does not violate the Basic Structure of the Constitution.
(c) Directive Principles are subordinate to Fundamental Rights and cannot override them in any circumstance.
(d) Parliament may enact a law to implement certain DPSPs without being invalidated for violating Article 14.

100. Which of the following constitutes a valid sole ground for challenging the validity of an ordinary law enacted by the Parliament or a State Legislature in a court of law?

1. It infringes upon the Fundamental Rights.
2. It is inconsistent with the Directive Principles of State Policy.
3. It violates the Basic Structure of the Constitution.

Select the correct answer using the codes given below:

(a) 1 only
(b) 1 and 2 only
(c) 1 and 3 only
(d) 1, 2 and 3

■■■■

Space for Rough Work

© Copyright: NEXT IAS

Space for Rough Work

© Copyright: NEXT IAS

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

NEXT IAS

GENERAL STUDIES

CSE Prelims Test Series (PTS): 2026

10th August, 2026 | Test-1 [Sectional Test]

Answer Key

1. (d)	21. (c)	41. (c)	61. (b)	81. (d)
2. (c)	22. (b)	42. (b)	62. (a)	82. (b)
3. (a)	23. (d)	43. (b)	63. (a)	83. (b)
4. (b)	24. (b)	44. (a)	64. (c)	84. (d)
5. (c)	25. (c)	45. (b)	65. (d)	85. (b)
6. (c)	26. (c)	46. (a)	66. (b)	86. (c)
7. (a)	27. (d)	47. (b)	67. (a)	87. (a)
8. (a)	28. (b)	48. (b)	68. (d)	88. (a)
9. (b)	29. (b)	49. (d)	69. (c)	89. (b)
10. (a)	30. (b)	50. (c)	70. (c)	90. (c)
11. (b)	31. (a)	51. (c)	71. (a)	91. (d)
12. (c)	32. (a)	52. (c)	72. (b)	92. (a)
13. (b)	33. (c)	53. (c)	73. (a)	93. (c)
14. (b)	34. (b)	54. (c)	74. (b)	94. (d)
15. (d)	35. (a)	55. (d)	75. (c)	95. (c)
16. (a)	36. (a)	56. (d)	76. (a)	96. (a)
17. (b)	37. (d)	57. (c)	77. (c)	97. (d)
18. (b)	38. (b)	58. (d)	78. (d)	98. (c)
19. (b)	39. (a)	59. (b)	79. (d)	99. (d)
20. (d)	40. (d)	60. (c)	80. (b)	100. (a)

DELHI CENTRE:
Vivekananda House
6-B, Pusa Road, Metro Pillar No. 111,
Near Karol Bagh Metro
New Delhi-110060
Phone: 8081300200

DELHI CENTRE:
Tagore House
27-B, Pusa Road, Metro Pillar No. 118,
Near Karol Bagh Metro
New Delhi-110060
Phone: 8081300200

DELHI CENTRE:
Mukherjee Nagar
637, Banda Bahadur Marg,
Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Phone: 9311667076

PRAYAGRAJ CENTRE:
31/31 Sardar Patel Marg,
Civil Lines, Prayagraj
Uttar Pradesh-211001
Phone: 9958857757

JAIPUR CENTRE:
Plot No. 6 & 7, 3rd Floor,
Sree Gopal Nagar,
Gopalpura Bypass, Jaipur-302015
Phone: 9358200511

© Copyright: NEXT IAS

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

General Studies
Test - 1

Sectional Test:
Polity, Governance & Current Affairs

1. (d)

- **Option (d) is the correct answer:** Mandamus writ is issued by the court to a public official asking him to perform his official duties that he has failed or refused to perform. In the given case, the public authority has a **duty to follow the recruitment rules** in letter and spirit. Disqualifying someone arbitrarily based on marital status (without legal backing) is discriminatory as it violates Article 14 (equality before law). Hence, the candidate can file a writ of Mandamus before the High Court or Supreme Court to enforce her Fundamental Rights and compel the authority to act lawfully.
- **Additional information:**

Writ	Objective
Habeas Corpus	It is in the nature of an order calling upon the person who has detained another to produce the latter before the court, in order to let the court know on what ground he has been 'confined, and to set him free if there is no legal justification for the imprisonment.
Quo Warranto	In the literal sense, it means 'by what authority or warrant'. It is issued by the court to enquire into the legality of claim of a person to a public office. Hence, it prevents illegal usurpation of public office by a person.
Certiorari	It is issued by a higher court—the Supreme Court or a high court to a lower court or tribunal either to transfer a case pending with the latter to itself or to quash the order of the lower court.
Prohibition	. It is issued by a higher court to a lower court or tribunal to prevent the latter from exceeding its jurisdiction or usurping a jurisdiction that it does not possess. Thus, unlike mandamus that directs activity, the prohibition directs inactivity.

2. (c)

- **Statement 1 is correct:** Article 4 of the Constitution states that any law made for admitting or establishing new states under Article 2, and forming new states or altering the areas, boundaries, or names of existing states under Article 3 shall not be treated as a constitutional amendment under Article 368. This implies that such laws can be enacted by a simple majority in Parliament through the ordinary legislative process.
- **Statement 2 is correct:** As per the Supreme Court ruling in the **Berubari Union case (1960)**, that Parliament's authority under Article 3 to reduce the area of a state does not extend to ceding Indian territory to a foreign nation. Therefore, transferring any part of India's territory to another country is possible only through a Constitutional amendment under Article 368.
- **Statement 3 is correct:** The Supreme Court held that resolving a boundary dispute between India and another country does not call for a constitutional amendment. Such a settlement can be carried out through executive action, as it does not entail ceding any part of India's territory to a foreign nation.

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

3. (a)

- **1 is not correct, but 2 is correct: Directive Principles are affirmative directions to the Legislative and Executive organs of the government.** They declare the duty of the State to achieve certain social and economic objectives. Thus, they do not limit the legislative or executive functions. On the contrary, **Fundamental Rights are negative or prohibitive in nature because they put limitations on the State.**
- **3 is not correct:** Fundamental duties, enshrined in **Part IVA** (Article 51A) are moral obligations for citizens, not constraints on the State.
- **Hence, option (a) is the correct answer.**

4. (b)

- **1, 2 and 3 are correct:** Article 13 states that the State shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this Part and any law made in contravention of this clause shall, to the extent of the contravention, be void. It further clarifies that the "law" here includes any **Ordinance**, order, bye-law, **rule, regulation**, notification, **custom or usage having in the territory of India the force of law.**
- **4 is not correct:** Article 13(4) states that nothing in Article 13 shall apply to any amendment of this Constitution made under article 368. Therefore, Article 13(4) explicitly excludes constitutional amendments made under Article 368 from the definition of "law" for the purposes of this article. This means such amendments are not tested against Article 13.

Additional Information:

- Article 13(1) declares that **all laws in force before the commencement of the Constitution**, if inconsistent with Fundamental Rights, become void to the extent of such inconsistency.

5. (c)

- **Statement I is correct: 1st Schedule** contains the list of **States and Union Territories** and their **territorial extent**. Any change in boundaries, creation of new states, or renaming of states necessitates amending this Schedule.
- **Statement II is not correct: 2nd Schedule** deals with **salaries and emoluments** of constitutional authorities. It is not affected by territorial or state reorganization.
- **Statement III is not correct: 3rd Schedule** contains **forms of oaths and affirmations** for constitutional functionaries. It also remains unaffected by changes under Article 2 or 3.
- **Statement IV is correct: 4th Schedule** allocates **seats in the Rajya Sabha** to each state and union territory. Changes in statehood or territory can affect this allocation, requiring updates to the Schedule.
- **Therefore,** only the **First Schedule** and the **Fourth Schedule** require modification when Parliament enacts a law under Article 2 or Article 3.
- **Additional Information:**
  - **5th Schedule** – Provisions relating to administration and control of Scheduled Areas and Scheduled Tribes.
  - **6th Schedule** – Provisions for administration of tribal areas in the North-Eastern states (Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram).
  - **7th Schedule** – Division of powers between Union and States (Union List, State List, Concurrent List).
  - **8th Schedule** – List of recognized languages (currently 22 languages).
  - **9th Schedule** – Added by 1st Amendment Act to protect the laws from being challenged in the court of law on the ground of violating Fundamental right.

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

- **10th Schedule** – Provisions relating to disqualification on the grounds of defection (Anti-defection law, added by 52nd Amendment, 1985).
- **11th Schedule** – Powers, authority, and responsibilities of Panchayats (29 subjects, added by 73rd Amendment, 1992).
- **12th Schedule** – Powers, authority, and responsibilities of Municipalities (18 subjects, added by 74th Amendment, 1992).

6. (c)

- **Statement 1 is correct:** According tor Article 15(5), **State can make any special provision**, by law, for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or **for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes** in so far as such special provisions relate to their admission to educational institutions including p**rivate educational institutions, whether aided or unaided by the State,** other than the minority educational institutions referred to in clause (1) of article 30. Therefore, SC/ST reservation in private aided institutions is constitutionally permitted.
- **Statement 2 is correct:** According to the Article 15(6), State can make special provisions for the advancement of economically weaker sections (EWS) — other than the socially and educationally backward classes, Scheduled Castes, and Scheduled Tribes — for their admission to educational institutions, including private (aided or unaided) ones, but excluding minority institutions. If these provisions involve reservation, it can be in addition to existing reservations, but must be capped at 10% of total seats in each category.

7. (a)

- **Statement 1 is correct:** Each province and princely state (or group of states in case of small states) were to be **allotted seats in proportion to their respective population.** Roughly, one seat was to be allotted for every million population.
- **Statement 2 is not correct: The nominees of the Princely States were not nominated** by the British Governors **but were nominated by the respective Princes.** The Constituent Assembly was to have 389 members out of which 296 were to be elected from the British Indian Provinces and 93 were to be the nominated members of various Princely States.
- **Statement 3 is not correct:** The seats in each Province were distributed among the **three main communities: Muslim, Sikh and General,** in proportion to their respective populations.

8. (a)

- **Statement 1 is correct:** The Preamble was adopted by the Constituent Assembly on 26 November 1949, after the adoption of the rest of the Constitution.
- **Statement 2 is not correct:** The Preamble does not mention the date of commencement of the Constitution as 26th January 1950. Instead, the Preamble mentions the date of adoption of the Constitution (which is 26th November 1949).
- **Statement 3 is correct:** The Preamble is an integral part of the Constitution as ruled in the Kesavananda Bharati case (1973). However, it is non-justiciable, i.e., its provisions cannot be enforced in a court of law.
- **Additional Information:** The words "Socialist" and "Secular" were inserted in the Preamble by the 42nd Constitutional Amendment Act, 1976.

9. (b)

- **Background of PoSH Act, 2013:** PoSH Act, 2013 traces its roots to the 1992 Bhanwari Devi case, where a Rajasthan government worker was gang-raped for stopping child

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

marriage, leading to the Supreme Court's landmark Vishaka Guidelines (1997) that recognized workplace sexual harassment as a violation of fundamental rights. These guidelines later formed the basis for enacting the PoSH law.

- **Statement 1 is c**orrect: Section 2(o) of the PoSH Act defines the workplace for the purpose of the Act. The Act covers all workplaces — organized and unorganized — including the private sector, government offices, NGOs, etc. It includes even non-traditional workplaces (for example those that involve telecommuting) and places visited by employees for work.
- **Statement 2 is correct**: The law requires any employer with more than 10 employees to form an Internal Complaints Committee (ICC) which can be approached by any woman employee to file a formal sexual harassment complaint. It has to be headed by a woman, have at least two women employees, another employee, and, to pre-empt any undue pressure from senior levels, to include a third party such as an NGO worker with five years of experience.
    - Besides, the Act mandates every district in the country to create a local committee (LC) to receive complaints from women working in firms with less than 10 employees and from the informal sector, including domestic workers.
- **Statement 3 is not correct:** The definition of "aggrieved woman" under the Act is broad. The Act protects any woman at a workplace—whether employed or not—such as clients, customers, interns, visitors, domestic workers, and students.
- **Statement 4 is correct:** Act is specifically for protection of women against sexual harassment. Men and transgender persons are not covered under its provisions.
- **Additional information:**
    - PoSH Act defines sexual harassment to include unwelcome acts such as physical contact and sexual advances, a demand or request for sexual favours, making sexually coloured remarks, showing pornography, and any other unwelcome physical, verbal, or non-verbal conduct of a sexual nature.
    - There are two ways to resolve the issue by the committee- "through conciliation" between the complainant and the respondent (which cannot be a financial settlement), or committees could initiate an inquiry, taking appropriate action based on what it finds.

10. (a)

- **Correct answer is A: chronological order starting from the earliest is,**
    - **Option A: National Flag** of India was adopted during a meeting of the Constituent Assembly held on **22 July 1947.**
    - **Option D:** The Constituent Assembly adopted the final draft of the **Constitution on 26th November 1949,** and it came into force on 26 January 1950.
    - **Option C & D : Last meeting** of the Constituent Assembly was held on **24 Jan, 1950.** The song **Jana-gana-mana,** composed originally in Bangla by Rabindranath Tagore, was adopted in its Hindi version by the Constituent Assembly as the **National Anthem of India on January 24, 1950** (i.e. in the last session of Constituent assembly).

11. (b)

- **Statement I is correct:** The writ jurisdiction of a High Court is wider than that of the Supreme Court.
- **Statement II is correct, but doesn't explain Statement I:** The writ jurisdiction

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

of the Supreme Court is provided under Article 32 of the Constitution, which itself is a Fundamental Right. Hence, the Supreme Court cannot decline to issue a writ when a Fundamental Right is violated. In contrast, the High Court derives its writ jurisdiction from Article 226, and it retains the discretion to decide whether or not to issue a writ, even in cases involving the violation of Fundamental Rights.

- **Statement III is correct and explains Statement I:** Article 226 explicitly states that High Courts can issue writs "for the enforcement of any of the rights conferred by Part III [Fundamental Rights] **and for any other purpose**." This "any other purpose" means for the enforcement of any legal right (statutory, constitutional but not fundamental, etc.). The fact that **High Courts can issue writs "for any other purpose" (i.e., beyond just Fundamental Rights) is precisely what makes their writ jurisdiction wider than that of the Supreme Court,** which primarily exercises its writ jurisdiction under Article 32 only for the enforcement of Fundamental Rights.
- **Therefore Both Statement-II and Statement-III are correct, but only one of them (Statement III) explains Statement-I.**

12. (c)

- **Statement 1 is correct:** Fundamental Duties mentioned in **article 51A** of Indian Constitution were not part of the original Constitution. Ten of them were added by the **42nd Constitutional Amendment Act, 1976,** based on the recommendations of the **Swaran Singh Committee.** Eleventh was added later with the 86th Constitutional Amendment Act, 2002.
- **Statement 2 is not correct:** Fundamental Duties are applicable only to citizens, not all residents (which would include foreigners too).
- **Statement 3 is correct:** Although Fundamental Duties are non-justiciable i.e., they are not enforceable by courts on their own, **Parliament can make laws to give them effect.**

13. (b)

- **About Article 20:** It **safeguards** individuals - whether citizens, foreigners, or legal entities such as companies and corporations - **against arbitrary and excessive punishment**. It provides three key protections in respect of conviction for offences:
- **Article 20(1) – Protection against ex post facto laws: No person can be convicted for an act that was not an offence when committed**, **nor** be subjected to a **penalty greater than that prescribed at the time of the offence**.
  - **In Scenario 1**, law in 2025 imposes a higher punishment for an offence committed in 2021 — applying this increased punishment retrospectively would violate **Article 20(1).**
- **Article 20(2) – Protection against double jeopardy: No person** can be **prosecuted and punished for the same offence more than once**.
  - **In Scenario 2**, departmental enquiry and **dismissal from service after a criminal trial does not amount to double jeopardy** because departmental action is not a criminal prosecution, but an **administrative**/disciplinary **measure**.
- **Article 20(3) – Protection against self-incrimination: No person** accused of an offence can be **compelled to be a witness against themselves**. This **applies to testimonial evidence**, **not to physical evidence like fingerprints, handwriting samples, or blood samples**.

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

- **In Scenario 3**, compelling a **blood sample does not violate Article 20(3)** as it is physical evidence, not personal testimony.

14. (b)

- **Statement 1 is correct:** Article 30(1) of the Indian Constitution states: "All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice."
- **Statement 2 is correct**: The Constitution of India uses the term "minority" (in Articles 29 and 30) but **does not define** it.
- **Statement 3 is not correct:** Article 30 of the Constitution of India states that all minorities, **whether based on religion or language**, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice. Therefore, Article 30 recognises only religious and linguistic minorities, and not racial minorities.

15. (d)

- **Statement 1 is not correct:**
  - Due Process of Law safeguards citizens from **both** executive and legislative actions, not just executive actions.
  - Procedure Established by Law also applies to laws passed by the legislature, but it primarily protects against **executive arbitrariness**.
- **Statement 2 is not correct:**
  - Procedure Established by Law limits judicial review to checking **only if the correct procedure** was followed while enacting the law — it does **not** examine the law's fairness, justice, or arbitrariness.
  - Due Process of Law, on the other hand, examines **both procedural compliance and substantive fairness** of the law.

Additional Information:

- **Origin:**
  - Procedure Established by Law → British origin.
  - Due Process of Law → Mentioned in Magna Carta, developed in the USA.
- **Indian Position:** Initially, the Indian Constitution adopted Procedure Established by Law, but post Maneka Gandhi vs. Union of India (1978), the Supreme Court interpreted it in a manner similar to Due Process of Law, by reading "just, fair, and reasonable" into the procedure under Article 21.

16. (a)

- The Gulf of Mexico is bordered by the **United States (to the north), Mexico (to the west and south), and Cuba (to the southeast).**
- Honduras and Guatemala are located in Central America and do not directly border the Gulf of Mexico.
- The Gulf of Mexico (GOM), Central America, and the Caribbean consist of small, interconnected ocean basins, strings of oceanic islands of various land areas and topographic elevations, and the isthmus of Central America that provides the only continuous, terrestrial connection between North and South America.

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

17. (b)

- **Context:** The President of the USA threatened to take back the Panama canal, calling the transfer treaty "foolish". The major reason for the U.S. President-elect's upset is the high transit fees applied on U.S. vessels by the ACP (Panama Canal Authority).
- **Statement 1 is not correct:** Panama Canal is an 82-km-long strategic waterway that connects the **Pacific and Atlantic Oceans.**
- **Statement 2 is correct: The Panama Canal provides a shortcut for ships traveling between the East Coast (e.g., New York) and the West Coast (e.g., Los Angeles/San Francisco) of the United States.** Without the canal, ships would have to navigate the lengthy and dangerous route around South America, which adds thousands of kilometers.
- **Statement 3 is not correct:** In 1977, then President Jimmy Carter and Panama's military leader Omar Torrijos signed two treaties — the Permanent Neutrality Treaty and the Panama Canal treaty that saw the U.S. hand over the control of the canal to Panama in 1999.

18. (b)

- **Context:** Recently in the news (2024–2025) due to the ongoing Israel–Hamas conflict, the Philadelphi Corridor became a focal point in negotiations over border control, with concerns about its potential use for military operations and the humanitarian impact on Palestinians in Rafah.
- The **Philadelphi Corridor** (also known as the **Salah al-Din Corridor**) is a **narrow strip of land** situated along the **border between the Gaza Strip and Egypt**, specifically the Egyptian town of **Rafah**.
- It serves as a **buffer zone** and has strategic importance due to its use for the **movement of goods and people**, and previously for **smuggling tunnels** between Gaza and Egypt.

19. (b)

- **Context:** Foreign Ministers of the member-nations of the grouping pledged in a joint statement commemorating the 20th anniversary of "Quad cooperation" on 21st of January 2025.
- **1 and 3 are correct:** India is a member of the QUAD and BRICS.
  - **Quad:** It is a diplomatic partnership between **Australia, India, Japan, and the United States** committed to supporting a peaceful, stable and prosperous Indo-Pacific that is inclusive and resilient.
  - **AUKUS:** It is a security pact between **Australia, the United Kingdom, and the United States** that focuses on technology sharing in the Indo-Pacific region.
  - **BRICS:** It is a group formed by major emerging countries: Brazil, Russia, India, China, South Africa, Iran, Egypt, Ethiopia, United Arab Emirates, and Indonesia.
  - **Five Eyes Alliance:** It is an intelligence-sharing alliance of US, UK, Australia, Canada, and New Zealand.

20. (d)

- **Statement 1 is correct: As per the official mandate of NITI Aayog, the Prime Minister of India is the** Ex-officio Chairperson of the institution.
- **Statement 2 is correct:** NITI Aayog was established via an executive resolution of the Union Cabinet on January 1, 2015, replacing the Planning Commission. It is not mentioned in the Constitution. **It is not created through an Act of Parliament (so not a statutory body). Hence, it is an executive/extra-constitutional body.**

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

- **Statement 3 is correct: The Governing Council of NITI Aayog, comprising Chief Ministers of all the States and Union Territories** with legislatures and Lt Governors of other Union Territories, came into effect on 16 February 2015 via a notification by the Cabinet Secretariat.

21. (c)

- **Among the given options, 2, 4 and 5 are available only to a citizen of India.**
- Fundamental rights that are available to **only citizens** are as follows:
- **Article 15:** Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth (Hence, 2 is correct)
- **Article 16:** Equality of opportunity in matters of public employment
- **Article 19:** Protection of six rights regarding freedom of :
  (i) speech and expression,
  (ii) assembly,
  (iii) association,
  (iv) movement,
  (v) residence, and
  (vi) profession / occupation (Hence, 4 and 5 are correct)
- **Article 29:** Protection of language, script and culture of minorities
- **Article 30:** Right of minorities to establish and administer educational institutions

22. (b)

- **Option B is the correct answer:** The Right against Exploitation is enshrined in Articles 23 and 24 of the Constitution of India. It includes the following rights:
  - **Article 23** prohibits human trafficking, begar (forced labour), and other similar forms of forced labour.
  - **Article 24** states that **No child below the age of fourteen years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment.**

23. (d)

- **Statement 1 is correct:** Non Resident Indian (NRI) is an Indian citizen who is ordinarily residing outside India. OCI cardholders are not citizens of India. OCI is a person of Indian origin who is a foreign national and gets registered as Overseas Citizen of India Cardholder under Section 7A of the Citizenship Act, 1955.
- **Statement 2 is correct:** OCIs are not entitled to hold public offices in India nor can they vote in elections in India.
- **Statement 3 is correct:** Following benefits are allowed to an OCI:
  - Multi-purpose, multiple entry, lifelong visa for visiting India.
  - **Exemption from registration with local police authority for any length of stay in India.**
  - Parity with NRIs in respect of economic, financial and education fields except in matters relating to the acquisition of agricultural/plantation properties.

24. (b)

- **Statement 1 is not correct: 'Objective Resolution' was moved on December 13, 1946 by Pandit Jawaharlal Nehru,** and was adopted by the Constituent Assembly on January 22, 1947. It provided the philosophy and guiding principles for framing the Constitution and later took the form of Preamble of the Constitution of India.
- **Statement 2 is not correct: Preamble does not grant power to the legislature, nor does it place any restrictions on its authority.** However, it plays a guiding role in interpreting the Constitution and clarifying ambiguous provisions.

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

- **Statement 3 is correct:** The Preamble has been amended only once by the **42nd Constitutional Amendment Act, 1976.** This amendment inserted the words "Socialist" and "Secular" into the Preamble and also added "Integrity" to the phrase "unity of the nation".

25. (c)

- The Preamble has been amended by the **42nd Constitutional Amendment Act (1976),** which added three new words– **Socialist, Secular and Integrity.**
- **Additional information: 4 main ingredients of the Preamble:**
  - **Source of authority**: The Preamble affirms that the Constitution's authority comes from the people of India.
  - **Nature of the Indian State**: It proclaims India as a sovereign, socialist, secular, democratic, and republican nation.
  - **Objectives:** It sets justice, liberty, equality, and fraternity as the guiding goals.
- Justice: Social, Economic and Political
- Liberty: Of thought, expression, belief, faith and worship
- Equality: Of status and of opportunity
- Fraternity: assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation
  - **Date of adoption:** It mentions November 26, 1949, as the date on which the Constitution was adoption

26. (c)

- **Statement 1 is correct:** If an Indian citizen voluntarily acquires citizenship of any other country, his/her Indian citizenship automatically stands terminated from the date of such acquisition.
- **Statement 2 is correct:** Applicable to persons who became citizens through registration or naturalisation. If such a person, within five years of obtaining citizenship, is sentenced in any country to imprisonment for not less than two years, the Central Government may deprive him/her of Indian citizenship.
- **Statement 3 is not correct: The Act specifies seven years of continuous residence outside India, not five years.**
- **Statement 4 is correct:** If a citizen has traded or communicated with an enemy during a war in which India is engaged, or has been engaged in acts against the sovereignty, security, or integrity of India, the Government may deprive such person of citizenship.
- **Additional information: The constitutional provisions with respect to the citizenship are as follows:**

1. No person shall be a citizen of India or be deemed to be a citizen of India, if he has voluntarily acquired the citizenship of any foreign state.
2. Every person who is or is deemed to be a citizen of India shall continue to be such citizen, subject to the provisions of any law made by Parliament.
3. Parliament shall have the power to make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship and all other matters relating to citizenship.

27. (d)

- **Statement 1 is correct:** Article 18(1) prohibits the State from conferring any title except military or academic distinctions.
- **Statement 2 is correct:** Article 18(2) bars Indian citizens from accepting titles from a foreign State.
- **Statement 3 is not correct:** Article 18(3) requires the **President's** prior consent, not the Prime Minister's, for accepting titles from a foreign State while holding an office of profit or trust under the State.

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

- **Additional information:** The Supreme Court upheld the constitutional validity of the **National Awards–Bharat Ratna, Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Sri.** It ruled that these awards do not amount to 'titles' within the meaning of Article 18 that prohibits only hereditary titles of nobility. Therefore, they are not violative of Article 18 as the theory of equality does not mandate that merit should not be recognised.

28. (b)

- **Article 50 of the Part IV** (Directive Principles of State Policy) talks about **Separation of judiciary from executive.** It states that the State shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the State.

29. (b)

- **Statement 1 and Statement 3 are correct:** When any person is detained in pursuance of an order made under any law providing for preventive detention, the authority making the order shall, as soon as may be, communicate to such person the grounds on which the order has been made and shall afford him the earliest opportunity of making a representation against the order.
- **Statement 2 is not correct:** Article 22(2) states that every person who is arrested and detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours of such arrest excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the magistrate. But Article 22(3) states that **nothing in Article 22(2) shall apply to any person who is arrested or detained under any preventive detention law.**
- **Additional information:**
  - The second part of Article 22 grants protection to persons who are arrested or detained under a preventive detention law. This protection is available to both citizens as well as aliens and includes the following:
    (i) The detention of a person cannot exceed three months unless the advisory board reports sufficient cause for extended detention The board is to consist of judges of a high court.
    (ii) The authorities must inform the detainee of the grounds for detention, except when disclosure is deemed against the public interest.
    (iii) The detenu should be afforded an opportunity to make representation against the detention order.

30. (b)

- **Statement 1 is not correct:** Constitution addresses citizenship in Articles 5 to 11 under Part II, but provides neither permanent nor detailed provisions on the subject. It only specifies who became citizens of India at its commencement on January 26, 1950, without covering how citizenship may be acquired or lost thereafter. Instead, it authorizes Parliament to make laws on these matters, under which the Citizenship Act, 1955 was enacted.
- **Statement 2 is correct:** The Citizenship Act, 1955 provides for acquisition of citizenship by registration and naturalisation, along with other modes like birth, descent, and incorporation of territory.

31. (a)

- Rani Velu Nachiyar, born in 1730, was a courageous and visionary queen of the Sivaganga estate in Tamil Nadu. She is best known for being **the first Indian queen to lead an armed resistance against British colonial rule**, well before the Revolt of 1857.
- When the British East India Company allied with the Nawab of Arcot to seize her kingdom, she refused to surrender and

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

went into exile. During this period, she **spent eight years strategically planning her counterattack**, forging alliances and gathering forces.

- Her comeback was marked by a bold and well-executed military campaign. One of the turning points was a **daring act of sacrifice by her commander Kuyili**, who immolated herself to destroy the British ammunition depot, giving Nachiyar's forces a critical advantage.
- Moreover, Rani Velu Nachiyar **formed an all-women regiment called the "Udaiyal Padai"**, demonstrating her progressive leadership in empowering women in warfare.
- Her valiant struggle and successful resistance mark **the first recorded instance of a woman in India leading a fight against British colonialism**, earning her a significant place in the annals of Indian history.

32. (a)

- **National Sports Awards are given every year to recognize and reward excellence in sports.**
- **Pair 1 is correctly matched:** 'Arjuna Award for outstanding performance in Sports and Games' is given for good performance over a period of the previous four years and for showing qualities of leadership, sportsmanship and a sense of discipline.
- **Pair 2 is correctly matched:** 'Dronacharya Award for outstanding coaches in Sports and Games' is given to coaches for doing outstanding and meritorious work on a consistent basis and for enabling sportspersons to excel in International events.
- **Pair 3 is not correctly matched:** 'Major Dhyan Chand Khel Ratna Award' is given for the spectacular and most outstanding performance in the field of sports by a sportsperson over the period of the previous four years.
- **Additional information:** Arjuna Award (Lifetime) is given to honour and motivate those sportspersons who have contributed to sports by their performance and continue to contribute to promotion of sports even after their retirement from active sporting career.

33. (c)

- As a formal grouping, BRIC started after the meeting of the Leaders of Russia, India and China in St. Petersburg on the margins of the G8 Outreach Summit in 2006. The grouping was formalized during the 1st meeting of BRIC Foreign Ministers on the margins of UNGA in New York in 2006. The 1st BRIC Summit was held in Yekaterinburg, Russia, in 2009.
- The **BRICS** grouping—originally comprising **Brazil, Russia, India, China, and South Africa**—expanded in 2024 to include **Egypt, Ethiopia, Iran, and the UAE** as full members.
- In **January 2025**, **Indonesia** officially joined the BRICS.
- **Iraq**, however, is **not** a member of BRICS.

34. (b)

- **Business Ready (B-READY)** is a **flagship report** of the **World Bank Group**, launched in **2024**.
- It **replaces and improves** upon the earlier Doing Business project.
- **Purpose:** Evaluates the **business and investment climate** globally, considering not just the interests of firms, but also **workers, consumers, new enterprises, and the environment**.
- **Framework:** Benchmarks economies on **three pillars** — Regulatory Framework, Public Services, and Operational Efficiency.

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

- **Coverage in 2024: 50 economies**, with plans to expand and refine methodology.

Additional Information:

- **10 topics** align with the **life cycle of a firm** (e.g., starting a business, paying taxes, accessing utilities).
- **Three cross-cutting themes:** digital adoption, environmental sustainability, and gender.
- Uses **expert questionnaires** and **firm-level surveys** for data.
- Supports **reform advocacy**, **policy guidance**, and further research.

35. (a)

Context: This year 22nd January 2025, marks the **10 years of Sukanya Samriddhi Yojana** encouraging families to invest in the bright futures of their daughters, fostering a culture of inclusion and progress.

- **Statement 1 is correct:** A guardian can open the account immediately after the birth of the girl child until she attains the age of **10 years**.
- **Statement 2 is correct:** Deposits into the account can be made for a maximum of **15 years** from the date of account opening.
- **Statement 3 is not correct:** Early closure is **not limited to death** — it is also allowed in cases of intended marriage before maturity and on **compassionate grounds** (life-threatening medical issues of the account holder or death of the guardian).

Additional Information:

- **One account per child**; max **two accounts** per family (exception for **twins/triplets**).
- **Guardian manages** the account until the girl turns **18**, then she can operate it herself.
- **Maturity: 21 years** from opening date.
- **Withdrawal:** Up to **50%** of the balance (preceding FY) allowed for **education** — as lump sum or in installments (**max 1 per year for up to 5 years**).

36. (a)

- **Option (a) is the correct answer:**
  - **Freedom of conscience:** Inner freedom of an individual to mould their relation with God or creatures in whatever way they desire. Therefore, A-2 is correct.
  - **Right to profess:** Declaration of one's religious beliefs and faith openly and freely. Therefore, B-1 is correct.
  - **Right to practice:** Performance of religious worship, rituals, ceremonies, and exhibition of beliefs and ideas. Therefore, C-4 is correct.
  - **Right to propagate:** Transmission and dissemination of one's religious beliefs to others or exposition of the tenets of one's religion. Therefore, D-3 is correct.

Additional Information:

- Article 25 guarantees **freedom of conscience** and the right to **profess, practice, and propagate religion** to all persons, including non-citizens.
- This freedom is subject to **public order, morality, health**, and other fundamental rights.
- Forcible conversions are not allowed as they violate another person's freedom of conscience.
- The State can regulate secular activities associated with religion and promote social reform, including opening Hindu religious institutions to all classes and sections.
- Wearing and carrying of kirpans is considered part of the Sikh profession of religion.
- In this context, "Hindus" also include **Sikhs, Jains, and Buddhists**.

37. (d)

- **Statement 1 is correct:** Article 51A(f) states that it is the duty of every citizen to value and preserve the rich heritage of the country's composite culture.

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

- **Statement 2 is correct:** Article 51A(i) provides that citizens must safeguard public property and abjure violence.
- **Statement 3 is correct:** Article 51A(g) specifies that citizens must protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife, and have compassion for living creatures.
- **Additional Information: Fundamental Duties under Article 51A:** According to **Article 51A**, it shall be the duty of every citizen of India:
  (a) to **abide by the Constitution** and respect its ideals and institutions, the **National Flag** and the **National Anthem**;
  (b) to **cherish and follow** the noble ideals that inspired the **national struggle for freedom**;
  (c) to **uphold and protect** the **sovereignty, unity and integrity** of India;
  (d) to **defend the country** and render **national service** when called upon to do so;
  (e) to **promote harmony** and the spirit of **common brotherhood** amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities, and to **renounce practices derogatory to the dignity of women**;
  (f) to **value and preserve** the rich heritage of the country's **composite culture**;
  (g) to **protect and improve** the **natural environment** including forests, lakes, rivers and wildlife, and to have **compassion for living creatures**;
  (h) to develop **scientific temper**, **humanism**, and the **spirit of inquiry and reform**;
  (i) to **safeguard public property** and to **abjure violence**;
  (j) to **strive towards excellence** in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to **higher levels of endeavour and achievement**; and
  (k) to **provide opportunities for education** to his child or ward between the age of **six and fourteen years**. This duty was added by the **86th Constitutional Amendment Act, 2002**.

38. (b)

- **Option (b) is the correct answer:** The writ of **Certiorari** means "**to be certified**" or "to be informed." It is **issued by a higher court to a lower court or tribunal to either transfer an ongoing case to itself or to annul the latter's order**. **Grounds** for its issue include **acting beyond jurisdiction, absence of jurisdiction, or legal error**. Unlike Prohibition, which is purely preventive, Certiorari serves both a preventive and corrective role.
- **Additional information:** The writ of **Certiorari** can be **issued against judicial authorities, quasi-judicial authorities** as well as **administrative authorities**.

39. (a)

- **Pair 1 is correctly matched: Office of Governor** is inspired from the **Government of India Act of 1935**. Other features inspired from this Act include **Federal Scheme, Judiciary, Public Service Commissions, Emergency provisions and administrative details.**
- **Pair 2 is correctly matched:** The **process of removal of Supreme Court and High Court judges** is inspired from the **Constitution of USA**. Other features include **Fundamental rights**, independence of judiciary, **judicial review**, **impeachment of the president** and post of vice president.
- **Pair 3 is not correctly matched: Concurrent List** is inspired from the **Australian Constitution**. Other features

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

inspired from Australian Constitution include freedom of trade, commerce and inter-course, and joint sitting of the two Houses of Parliament.

- **Additional information:** Features of the Indian Constitution inspired from the Constitutions of other countries:
  - **Britain** - Parliamentary government, Rule of Law, legislative procedure, single citizenship, cabinet system, prerogative writs, parliamentary privileges and bicameralism.
  - **Ireland** - Directive Principles of State Policy, nomination of members to Rajya Sabha and method of election of President.
  - **Canada** - Federation with a strong Centre, vesting of residuary powers in the Centre, appointment of state governors by the Centre, and advisory jurisdiction of the Supreme Court.
  - **Germany** - Suspension of Fundamental Rights during Emergency.
  - **USSR (Russia)** - Fundamental duties and the ideal of justice (social, economic and political) in the Preamble.
  - **France** - Republic and the ideals of liberty, equality and fraternity in the Preamble.
  - **South Africa** - Procedure for amendment of the Constitution and election of members of Rajya Sabha.
  - **Japan** - Procedure established by Law.

40. (d)

- **Statement-I is not correct**: Article 21A of the Constitution (added by the 86th Constitutional Amendment Act, 2002) makes it the **responsibility of the State** to provide **free and compulsory education to all children aged 6 to 14 years as a Fundamental Right.**
- **Statement-II is correct**:
  - **Directive Principles of State Policy**: Article 45 directs the State to endeavour to provide early childhood care and education to all children until they **complete the age of six years.**
  - **Fundamental Duties**: Article 51A(k) places the duty on parents/guardians to provide educational opportunities to their children **between the ages of 6 and 14.**

41. (c)

- **About Article 19:** It deals with **protection of certain rights of citizens regarding freedom of speech** etc. **Article 19(1)** states that all citizens shall have the right to:
  - freedom of speech and expression
  - to assemble peaceably and without arms;
  - to form associations or unions or co-operative societies;
  - to move freely throughout the territory of India;
  - to reside and settle in any part of the territory of India; and
  - to practise any profession, or to carry on any occupation, trade or business.
- **Article 19(2)** deals with the **reasonable restrictions on the exercise of the right** conferred by Article 19(1). The restrictions include the following:
  - interests of the sovereignty and integrity of India.
  - security of the State.
  - **friendly relations with Foreign States. Thus, 1 is correct.**
  - **public order. Thus, 4 is correct.**
  - decency or morality.
  - contempt of court.
  - defamation.
  - **incitement to an offence. Thus, 2 is correct.**

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

- **3 is not correct**: **Protection of the interests of any Scheduled Tribes** is a **restriction on the right to move freely throughout the territory of India and the right to reside and settle in any part of the territory** of India.
- **About Article 19:** It deals with **protection of certain rights of citizens regarding freedom of speech** etc. **Article 19(1)** states that all citizens shall have the right to:
  - freedom of speech and expression
  - to assemble peaceably and without arms;
  - to form associations or unions or co-operative societies;
  - to move freely throughout the territory of India;
  - to reside and settle in any part of the territory of India; and
  - to practise any profession, or to carry on any occupation, trade or business.
- **Article 19(2)** deals with the **reasonable restrictions on the exercise of the right** conferred by Article 19(1). The restrictions include the following:
  - interests of the sovereignty and integrity of India.
  - security of the State.
  - **friendly relations with Foreign States. Thus, 1 is correct.**
  - **public order. Thus, 4 is correct.**
  - decency or morality.
  - contempt of court.
  - defamation.
  - **incitement to an offence**. **Thus, 2 is correct.**
- **3 is not correct**: **Protection of the interests of any Scheduled Tribes** is a **restriction on the right to move freely throughout the territory of India and the right to reside and settle in any part of the territory** of India.

42. (b)

- **Option B is the correct answer:** The Supreme Court has recognised a much-felt, but less articulated right against the adverse effects of climate change as a distinct fundamental right in the Constitution.
- "It is yet to be articulated that the people have a right against the adverse effects of climate change. This is perhaps because this right and the right to a clean environment are two sides of the same coin.
- As the havoc caused by climate change increases year-by-year, it becomes necessary to articulate this as a distinct right. It is recognised by **Articles 14 (right to equality) and 21 (right to life),"** the Supreme Court observed in a judgment.
- The judgment came in a case connected with the survival of the endangered Great Indian Bustard species earlier.

43. (b)

- **Pair 1 not correctly matched: The Drafting Committee was chaired by Dr. B. R. Ambedkar.** B. N. Rau was the Constitutional Adviser to the Constituent Assembly, not the chairman of any committee.
- **Pair 2 correctly matched: Sardar Vallabhbhai Patel chaired the Provincial Constitution Committee.** It dealt with provisions related to the governance of provinces in the new Constitution.
- **Pair 3 correctly matched:** Dr. Rajendra Prasad chaired the Rules of Procedure Committee.
- **Additional Information: Other committees and their Chairman**
  1. Union Powers Committee - Jawaharlal Nehru
  2. Union Constitution Committee -Jawaharlal Nehru
  3. Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities and Tribal and Excluded Areas - Sardar Patel.

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

4. States Committee (Committee for Negotiating with States) - Jawaharlal Nehru
5. Steering Committee - Dr. Rajendra Prasad

44. (a)

- **Statement 1 is correct:** Article 44 contained in part IV of the Constitution says that the state "shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India".
- **Statement 2 is not correct:** Personal laws such as intestacy and succession; wills; joint family and partition; marriage and divorce, relate to Entry 5 of List-III-Concurrent List of the Seventh Schedule to the Constitution, and hence, both Parliament and State Legislature are empowered to legislate upon them.

45. (b)

- **Option (b) is the correct answer:** The **calligraphy of the Hindi version of the Constitution** was done by **Vasant Krishan Vaidya**, while the artwork and **beautification for both versions were contributed by Nandalal Bose** and his team from Santiniketan.
- **Additional information:** Other notable personalities associated with the Constitution:
  - **Sir B.N. Rau** - constitutional advisor (Legal advisor) to the Constituent Assembly.
  - **H.V.R. Iyengar** - Secretary to the Constituent Assembly.
  - **S.N. Mukherjee** - Chief draftsman of the constitution in the Constituent Assembly.
  - **Beohar Rammanohar Sinha** - illuminated and beautified the original Preamble calligraphed by Prem Behari Narain Raizada.

46. (a)

- **Statement 1 is correct:** According to Article 37 of the Constitution of India, the provisions contained in the Part IV (Directive Principles of State Policy) shall not be enforceable by any court, but the principles therein laid down are **nevertheless fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the State to apply these principles in making laws.**
- **Statement 2 is not correct:** Directive Principles of State Policies (DPSPs) are **non-justiciable in nature,** which implies that they are non enforceable in the court. Therefore, the judiciary can not declare a law invalid only because it violates the DPSPs.

47. (b)

Option (b) is correct: A rigid Constitution requires a procedure distinct from ordinary legislation for its amendment, whereas a flexible Constitution can be amended through the normal legislative process.

Additional Information:

- **Rigid Constitution:** Needs a special procedure for amendment (e.g., the US Constitution).
- **Flexible Constitution:** Can be amended like ordinary laws (e.g., the UK Constitution).
- **Indian Constitution:** A blend of both —
  - Certain provisions require a **special majority** of Parliament.
  - Some require a **special majority plus ratification by half of the states**.
  - Others can be amended by a **simple majority**, similar to ordinary laws (these do not fall under Article 368).

48. (b)

- **44th Amendment Act (1978):** Added a Directive Principle requiring the State to minimise inequalities in income, status, facilities, and opportunities (Article 38). Therefore, **A-3 is correct**.

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

- **86th Amendment Act (2002):** Amended Article 45 to require the State to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of six years. Therefore, **B-2 is correct.**
- **97th Amendment Act (2011):** Added Article 43B, directing the State to promote voluntary formation, autonomous functioning, democratic control, and professional management of cooperative societies. Therefore, **C-1 is correct.**
- **Additional Information:**
  - **42nd Amendment Act (1976)** earlier expanded the list of Directive Principles with provisions for legal aid, participation of workers in management, environmental protection, and child development.
  - The **44th Amendment** was part of the post-Emergency reforms to restore constitutional balance and strengthen socio-economic directives.
  - The **86th Amendment** simultaneously made elementary education a Fundamental Right (Article 21A) and shifted early childhood care to the Directive Principles.
  - The **97th Amendment** was partly struck down by the Supreme Court in 2021 for lack of ratification by half the states, but the part relating to cooperative societies in the DPSP remains valid.

49. (d)

- **Option (d) is the correct answer:** The **Directive Principles of State Policy (DPSP)** in Part IV of the Constitution include certain provisions inspired by **Mahatma Gandhi's ideals**, often referred to as **Gandhian Principles**. These focus on promoting self-reliance, rural development, and social harmony, and include:
  - Promotion of cottage industries in rural areas (Article 43)
  - Prohibition of intoxicating drinks and drugs injurious to health (Article 47)
  - Preserving and improving breeds and prohibiting slaughter of cows and calves (Article 48)
- However, **securing a Uniform Civil Code for citizens** (Article 44) falls under the **Liberal-Intellectual Principles**, not the Gandhian Principles.

Additional Information:

- Gandhian DPSPs aim to realise the vision of a self-sufficient rural economy and moral upliftment.
- Other Gandhian provisions include promoting panchayati raj (Article 40) and organising village-level khadi & cottage industries.

50. (c)

- **Statement 1 is correct:** The Indian Councils Act, 1909 known as the Morley–Minto Reforms **introduced the principle of separate electorates for Muslims.** Under this system, Muslim voters could elect their representatives through a separate electoral roll. It marked the beginning of communal representation in Indian politics.
- **Statement 2 is correct:** For the first time, the Act allowed Indians to be associated with the Viceroy's Executive Council. Satyendra Prasanna Sinha (later Lord Sinha) became the first Indian to be appointed as a member of the Viceroy's Executive Council in 1909, holding the Law portfolio.
- **Statement 3 is not correct:** The Indian Councils Act, 1909 did not provide for the establishment of a Public Service Commission. The idea of a Public Service Commission was introduced later under the Government of India Act, 1919.
- **Statement 4 is correct:** The Act increased the size of both the Central Legislative Council and the Provincial Legislative

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

Councils. At the central level, the number of members was increased from 16 to 60, and at the provincial level, the number was also significantly expanded.

51. (c)

- **Statement 1 is correct:** The Directive Principles of State Policy (Part IV, Articles 36–51) are inspired in part by the **"Instruments of Instructions"** provided in the Government of India Act, 1935. These Instruments guided the Governor-General and Governors in exercising their powers, much like how DPSPs guide the State in policy-making.
- **Statement 2 is correct: Dr. B.R. Ambedkar, the Chairman of the Drafting Committee, referred to the DPSPs as the "novel features"** of the Indian Constitution, as they aimed to promote the welfare of the people by securing social and economic democracy.
- **Additional information:**
  - The provision of DPSP in the Constitution of India is inspired from the from the Irish Constitution of 1937, which had copied it from the Spanish Constitution.

52. (c)

- **Statement 1is correct:** India's **4th Biennial Update Report (BUR-4)**, submitted to the **UNFCCC** on **30th December 2024**, reported a **7.93% reduction** in **total greenhouse gas (GHG) emissions** in **2020** compared to **2019**.
- **Statement 2 is correct:** In **2020**, the **energy sector** was the **largest contributor** to India's GHG emissions, **accounting for 75.66%** of total emissions.
  - Other sectors: Agriculture, Industrial processes, Waste, and **LULUCF** (Land Use, Land-Use Change, and Forestry).
  - **LULUCF** activities helped **sequester ~522 million tonnes of CO_2**, offsetting around **22%** of gross emissions.

Additional Information:

- **Excluding LULUCF:** India's emissions in 2020 were **2,959 million tonnes of CO_2e**.
- **Including LULUCF:** Net emissions stood at **2,437 million tonnes of CO_2e**.
- **NDC Goal:** Net-zero emissions by **2070** (announced at **COP26, 2021**).
- **BURs** are submitted every **two years** to update GHG inventories, report mitigation measures, and record support received.

53. (c)

Context: The Union Cabinet's decision to accord classical language status to five new languages, including Marathi and Bengali, came after a key provision, **which mandated that a language must have original literary tradition, was dropped.**

- **Earlier Criteria (2005):**

To qualify as a **Classical Language**, one of the requirements was that **"the literary tradition must be original and not borrowed from another speech community"**.

- **Recent Change (2024):**

This **"originality of literary tradition"** requirement was **dropped** in the revised norms, enabling more languages to qualify.

- **Impact:**

Under the revised norms, **Marathi, Bengali, Assamese, Pali, and Prakrit** were accorded classical language status (Gazette notification: **4 October 2024**).

Additional Information:

- **Current criteria for classical language:**
  - High antiquity of its early texts/ recorded history over a period of 1500-2000 years.
  - A body of ancient literature/texts, which is considered a heritage by generations of speakers.

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

- Knowledge texts, especially prose texts in addition to poetry, epigraphical and inscriptional evidence.
- The Classical Languages and literature could be distinct from its current form or could be discontinuous with later forms of its offshoots.

- **Before revision:** 6 classical languages — **Tamil, Sanskrit, Kannada, Telugu, Malayalam, Odia**.
- **After revision:** 11 classical languages — above six + **Marathi, Bengali, Assamese, Pali, Prakrit**.

54. (c)

- **Option (c) is the correct answer: PM YASASVI Scheme** (PM Young Achievers Scholarship Award Scheme for Vibrant India) is aimed at empowering students from **Other Backward Classes (OBC), Economically Backward Classes (EBC),** and **De-notified Tribes (DNT)**.
- **Primary components include:**
  - **Pre-Matric Scholarship:** ₹1.25 lakh annually for students in classes 9–12
  - **Post-Matric Scholarship:** Financial support for higher education (₹12.75 crore disbursed)
  - **Top-Class School & College Education**
  - **Hostel construction** for OBC students

Additional Information:

- **Launch Objective:** To provide **educational, social, and economic empowerment** to disadvantaged groups.
- **Special Recognition:** In 2025, 400 student beneficiaries from **21 states** were invited as special guests to the Republic Day Parade.
- **Nodal Ministry:** Ministry of Social Justice and Empowerment.

55. (d)

- **Statement 1 is not correct: In India, the Constitution allows the Prime Minister to be a member of either House of Parliament.** For instance, **Indira Gandhi, Deve Gowda, and Manmohan Singh** served as Prime Ministers while being **members of the Rajya Sabha**. In contrast, **in Britain, the Prime Minister must be a member of the Lower House** (House of Commons).
- **Statement 2 is correct: In Britain, every public order issued by the King must be countersigned by a minister, who is then legally accountable for it**. If the order violates any law, the minister can be held responsible in court. The principle followed there is, "The King can do no wrong". **In India, there is no constitutional** provision making ministers legally responsible in this way, nor is there a **requirement that the President's public orders be countersigned by a minister**.
- **Statement 3 is not correct: In Britain, the Speaker** is expected to be completely nonpartisan. He **resigns from party membership upon election** to maintain political neutrality. **In India**, however, this convention is not fully practiced, and the **Speaker generally retains party membership even after assuming office**.

56. (d)

- **About 42nd Amendment Act of 1976:** It **added** four new Directive Principles to the list of DPSPs. They direct the State:
  - To secure opportunities for healthy development of children (Article 39).
  - To **promote equal justice** and to **provide free legal aid** to the poor (Article 39 A). **Thus, Statement 3 is correct.**
  - To take steps **to secure the participation of workers in the management of industries** (Article 43 A). **Thus, Statement 2 is correct.**
  - To protect and improve the environment and to safeguard forests and wild life (Article 48 A).

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

- **Statement 1 is not correct:** The directive to **minimise inequalities in income, status, facilities, and opportunities** (**Article 38**) was added later by the **44th Amendment Act of 1978.**
- **Additional information:** Other Amendments in DPSPs include:
  - **86th Amendment Act, 2002** - amended the subject-matter of **Article 45**. It requires the State to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of six years.
  - **97th Amendment Act, 2011** - added a new DPSP relating to cooperative societies. It requires the state to promote voluntary formation, autonomous functioning, democratic control and professional management of co-operative societies **(Article 43B)**.

57. (c)

- **Statement 1 is correct:** The Act allows disclosures of **corruption** or **misuse of power** by public servants, including **ministers**, before a competent authority such as the **Central Vigilance Commission (CVC)**.
- **Statement 2 is not correct:** The Act does not mandate inquiry into **anonymous complaints**, even if evidence is provided. It explicitly states that no action shall be taken if the **identity** of the complainant or public servant is not indicated or is found to be incorrect.
- **Statement 3 is correct:** The Act penalizes **false or frivolous complaints** with imprisonment of up to **two years** and a fine of up to **₹30,000**.
- **Statement 4 is correct:** The **Special Protection Group (SPG)** is exempt from the provisions of this Act.
- **Additional Information:** The **Whistle Blowers Protection Act, 2014** provides a mechanism to protect whistleblowers' **identity** and ensure they are not **victimized**. Disclosures must be made **in good faith**, in **writing** or via **email**, with **supporting documents** or material evidence. The **government** can designate authorities other than the **CVC** to receive such complaints.

58. (d)

- **Option D is the correct answer: Fundamental Duties** were added to the Constitution by the **42nd Constitutional Amendment Act, 1976**, inserting **Article 51A**. Originally, there were **10 Fundamental Duties**.
- The list has been amended **only once**, by the **86th Constitutional Amendment Act, 2002**.
- This amendment added **Clause (k)** to Article 51A:

"Who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, ward between the age of six and fourteen years."

- The amendment was in line with **Article 21A**, which made education a Fundamental Right for children in that age group.

59. (b)

- **1 is correct:** In a parliamentary form of government, **collective responsibility of ministers to the Parliament** is a **foundational principle**. Under **Article 75**, **ministers are accountable to the Parliament as a whole and specifically to the Lok Sabha**. This means the Lok Sabha can dismiss the entire council of ministers, led by the Prime Minister, through a vote of no confidence.
- **2 is not correct: Bicameralism is not an inherent requirement of the parliamentary system**. Several parliamentary democracies operate successfully with a single legislative

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

chamber. What defines the parliamentary system is the executive's responsibility to the legislature, not whether the legislature has one or two houses.

- **3 is correct: Dissolution of the lower house** is an inherent **feature of the parliamentary system**. The **executive has the authority to recommend dissolution**, reflecting the close link between the legislature and the executive in this system.
- **Additional information:** Other features of Parliamentary system (in India) include:
  - Presence of Nominal and Real Executives.
  - Majority Party Rule.
  - Ministers are members of both the legislature and the executive.
  - Leadership of the Prime Minister.

60. (c)

- **Option (c) is the correct answer: The Charter Act of 1833** was a significant step in the constitutional development of British India. It mainly dealt with the **centralization of legislative powers**. It **ended the legislative powers of the Bombay and Madras Presidencies and vested all law-making authority in the Governor-General of India**. It transformed the Governor-General of Bengal into Governor-General of India, who had authority over the whole of British India.
- The Charter Act of 1833 also **laid the foundation for codification of laws**. It provided for the **Law Commission, headed by Lord Macaulay**, which began systematic codification of Indian laws (leading to the Indian Penal Code, Criminal Procedure Code, etc.)

61. (b)

- **Option B is the correct answer:** Article 326 of the Constitution provides that the elections to the House of the People and to the Legislative Assembly of every State shall be on the basis of adult suffrage.
- Every citizen who is not less than 18 years of age has a right to vote without any discrimination of caste, race, religion, sex, literacy, wealth and so on.
- **The voting age was reduced to 18 years from 21 years in 1989 by the 61st Constitutional Amendment Act of 1988.**

62. (a)

Some Fundamental Rights under the Constitution are enforceable not just against the 'State' (as defined in Article 12) but also against **private individuals or entities**.

1 is correct: Prohibition of traffic in human beings and forced labour (Article 23)

Applies to both State and private persons. It bans trafficking, begar, and other similar forms of forced labour. The Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 and Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976 operationalise this right.

2 is correct: Prohibition of employment of children in factories (Article 24)

Applies to both State and private employers. Prohibits employment of children below 14 years in factories, mines, and other hazardous occupations. Enforced through the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (amended 2016).

3 is not correct: Right to freedom of religion (Articles 25–28)

Primarily enforceable against the State to ensure non-interference in religious practices, except in cases where legislation also makes it applicable to private actions.

4 is correct: Abolition of untouchability (Article 17)

Applies to both State and private persons. Forbids untouchability and makes its practice an offence. Implemented through the Protection of Civil Rights Act, 1955 and the SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989.

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

63. (a)

- **About unwritten Constitution:** It refers to a **constitution not codified in a single formal document but based on statutes, judicial decisions, conventions, and traditions**. They are also known as "uncodified" constitutions.
- **6 countries** in the world have **unwritten or uncodified Constitutions**. They include the **United Kingdom, San Marino, New Zealand, Canada, Sweden and Israel. Thus, 1 is correct.**
- **2 is not correct: Australia** has a **written Constitution** that came into effect in 1901.
- **3 is not correct: Japan** has a **written Constitution** that came into effect in 1947.

64. (c)

- **Option (c) is the correct option:** While the Citizenship Act, 1955 provides for acquisition of Indian citizenship in five ways—**by birth, by descent, by registration, by naturalisation, and by incorporation of territory**—marriage to an Indian citizen **by itself** is **not** a mode of acquiring citizenship. A foreigner married to an Indian citizen can apply for citizenship **only through registration** under Section 5(1)(c) of the Citizenship Act, provided they have been ordinarily resident in India for **at least 7 years** before making the application. Thus, marriage is only a qualifying factor under the registration category, not an independent mode.

65. (d)

- **Option (d) is the correct answer: Dr. B.R. Ambedkar called Article 32 (Right to Constitutional Remedies)** as the "**heart and soul of the Constitution"**. This is because **Article 32 empowers individuals to approach the Supreme Court directly for enforcement of Fundamental Rights**. Thus, it acts as a guarantee against the violation of the fundamental rights by the State. This provision **ensures that Fundamental Rights are not merely theoretical but enforceable in practice**.
- The **Supreme Court and High Courts can issue the writs** of **Habeas Corpus, Mandamus, Prohibition, Certiorari, Quo Warranto** to safeguard Fundamental Rights.

66. (b)

- **Statement 1 is not correct: Stricter separation of powers between the executive and legislature** is a characteristic of the **Presidential form of government**, not the Parliamentary form. In the Parliamentary system, there is a **fusion of powers**: the executive (Prime Minister and Council of Ministers) is drawn from and is collectively responsible to the legislature.
- **Statement 2 is correct:** Parliamentary form of government **facilitates closer coordination between the executive and the legislature in policymaking.** Because of the fusion of powers, ministers are members of the legislature and directly accountable to it. This allows for smoother communication and coordination in policy formulation and execution.
- **Statement 3 is not correct:** Fixed tenure is a feature of the **Presidential system**. In the Parliamentary system, the government can be removed at any time through a vote of no-confidence, so tenure is not fixed.
- Additional information: The features of parliamentary government in India are:
  (a) Presence of nominal and real executives;
  (b) Majority party rule,
  (c) Collective responsibility of the executive to the legislature,
  (d) Membership of the ministers in the legislature,
  (e) Leadership of the Prime Minister or the Chief Minister,
  (f) Dissolution of the lower House (Lok Sabha or Assembly).

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

67. (a)

- **Statement 1 is correct:** The **National Population Register (NPR)** is prepared under the provisions of the Citizenship Act, 1955 and the Citizenship (Registration of Citizens and Issue of National Identity Cards) Rules, 2003.
- **Statement 2 is not correct:** NPR contains details of **all "usual residents"** of India, not just citizens. A "usual resident" is a person who has resided in a local area for the past 6 months or intends to reside there for the next 6 months or more, regardless of nationality.
- **Statement 3 is not correct:** Registration in the NPR is **mandatory** for every usual resident, not voluntary.
- **Additional Information:**
- NPR is a database maintained by the **Office of the Registrar General and Census Commissioner, India**, under the Ministry of Home Affairs.
- It was first prepared in 2010 and updated in 2015, linking with Aadhaar and other databases to improve delivery of government schemes.

68. (d)

- **Statement-I is correct:** Article 33 empowers the Parliament to restrict or abrogate the Fundamental Rights of the members of armed forces, para-military forces, police forces, intelligence agencies and analogous forces.
- **Statement-II is not correct:** Only Parliament has the power under Article 33. State Legislatures are not empowered under this article to make laws on Fundamental Rights of armed forces. Any such law made by Parliament cannot be challenged in any court on the ground of contravention of any of the fundamental rights.
- **Statement-III is not correct:** Article 33 applies irrespective of whether a national emergency is in force or not. The provision is a general power given to Parliament to maintain discipline within armed and related forces.
- **Additional information:** The term "members of the armed forces" also includes non-combatant personnel such as barbers, carpenters, mechanics, cooks, chowkidars, bootmakers, and tailors serving in the armed forces.

69. (c)

- **Statement 1 is correct:**

The Supreme Court of India in the **Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973)** case held that the federal character of the Constitution is part of the **Basic Structure** doctrine. This means that while Parliament can amend most provisions, it cannot alter the essential federal framework of the polity.

- **Statement 2 is correct:**

The term "federalism" is **not explicitly mentioned** in the text of the Constitution. Instead, India's federal nature is inferred from provisions like the **Union and State Lists (Seventh Schedule)**, distribution of legislative, administrative, and financial powers, and the role of the judiciary in resolving Centre–State disputes. The Constitution describes India in **Article 1** as a "Union of States," reflecting a federal system with a strong unitary bias.

- **Additional Information:**
  - India's federal structure is often called "quasi-federal" because it combines federal features (division of powers, bicameralism, independent judiciary) with unitary features (strong Centre, emergency powers).
  - The Basic Structure doctrine also protects other principles like separation of powers, secularism, judicial review, and the supremacy of the Constitution.

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

70. (c)

- **Option (c) is the correct answer:** The **Fundamental Duties** were **added** to the Constitution **by** the **42nd Constitutional Amendment Act, 1976**. These duties were inserted as **Part IVA** of the Constitution under **Article 51A**.
- They were partly **inspired from the Constitution of USSR** and were **based on the recommendations of** the **Swaran Singh Committee**.
- Originally, there were **10 Fundamental Duties**; the **86th Constitutional Amendment Act, 2002** added the 11th duty (to provide opportunities for education to children between 6 and 14 years).

71. (a)

- **Statement 1 is correct:** The **Interest Equalisation Scheme** aims to make export credit cheaper by offering an **interest rate subsidy on rupee-denominated pre-shipment and post-shipment credit to eligible exporters**.
- **Statement 2 is correct:** The scheme is implemented through the **Reserve Bank of India (RBI)**, which issues operational guidelines and reimburses banks.
- **Statement 3 is not correct:** The scheme specifically covers the **MSME manufacturing sector** among eligible beneficiaries.

72. (b)

- **Statement 1 is correct: Securities Transaction Tax is a tax levied on the purchase and sale of securities listed on recognized stock exchanges in India.** This tax is charged at the time of executing a transaction and is **applicable to all equity and derivative transactions, including stocks, equity futures, and options**. STT was introduced to curb tax evasion, enhance transparency in trading, and simplify the taxation process for investors.
- **Statement 2 is not correct:** The **rates of STT are prescribed by the Central/ Union Government** through its Budget from time to time.
- **Statement 3 is not correct:** Securities Transaction Tax is categorised as a direct tax. The **cost of STT is passed on to investors/traders** as part of their transaction cost; stock exchanges only collect and remit it to the government.

73. (a)

- **Context:** The UJALA scheme, launched on 5th January 2015 by Prime Minister Narendra Modi, marked its 10th anniversary as a groundbreaking initiative in energy efficiency.
- **Statement 1 is correct.**

The effort was jointly undertaken by the Energy Efficiency Services Limited (EESL) and DISCOMs under the Ministry of Power.

- **Statement 2 is not correct.**

Over the past decade, UJALA has evolved into the world's largest **zero-subsidy** domestic lighting programme.

- **Additional Information :** The UJALA scheme was launched on 5th January 2015 by Prime Minister Narendra Modi.
- It was initially introduced as the Domestic Efficient Lighting Programme (DELP) and later rebranded as UJALA.
- It aimed to provide affordable energy-efficient LED bulbs, tube lights, and fans to Indian households.
- The initiative addressed high electrification costs and carbon emissions.
- A 7W LED bulb provides the same light output as a 14W CFL and a 60W Incandescent Lamp, saving up to 90% energy.

74. (b)

- The correct chronological order of the formation of the above states is 2-1-3.

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

- **Nagaland** became the 16th state of India on **1 December 1963**.
- Under the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, **Manipur** became a full-fledged state on **21 January 1972**.
- **Arunachal Pradesh** became the 24th state of India on **20 February 1987**.

75. (c)

- **Option (c) is the correct answer:** The **Government of India Act, 1935** was the longest piece of legislation passed by the British Parliament for India and introduced several key constitutional changes. One of its major features was the **establishment of the Federal Court in 1937, to resolve disputes between provinces and the centre** and interpret legal provisions.
- **Additional information:** Other important provisions of the 1935 Act included:
  - **Provincial autonomy** (replacing dyarchy at the provincial level, which was earlier introduced by the Government of India Act, 1919).
  - **Introduction of dyarchy at the centre** (never implemented).
  - Provision for an **All-India Federation** (not implemented due to lack of princely state participation).
  - Division of powers into **Federal, Provincial, and Concurrent lists**.
  - **Extension of separate electorates**.

76. (a)

- **Option (a) is the correct answer:** The **Office of the Registrar General & Census Commissioner (RGI)** works under the **Ministry of Home Affairs (MHA)**, Government of India. The Census in India is conducted every **10 years**; the first synchronous census was held in **1881** during British rule.

77. (c)

- **Statement 1 is correct: Article 17 abolishes "untouchability" and forbids its practice in any form**, making it **absolute and unconditional**.
- **Statement 2 is not correct: The Constitution does not define the term 'untouchability'**. Judiciary, in its various judgments has interpreted it to mean practices related to caste-based discrimination. Untouchability relates to the social disabilities imposed on certain classes of persons by reason of their birth in certain castes.
- **Statement 3 is correct: Enforcement of any disability arising out of untouchability is an offence punishable by law**, whether by a **private individual** or **public authority**, as per **Article 17** of the Constitution and the **Protection of Civil Rights Act, 1955.**

78. (d)

- **Option (d) is the correct answer.**
- **About women members of the Constituent Assembly:** The contributions of **fifteen distinguished women shaped India's constitutional landscape**. Some of their contributions include the following:
  - Smt. Ammu Swaminathan - vocal advocate for gender equality in constitutional provisions, ensuring that women's rights were duly recognized.
  - Smt. Annie Mascarene - played a key role in discussions on federalism and state integration, reinforcing India's unity in diversity.
  - Begum Qudsia Aizaz Rasul, the only Muslim woman in the Assembly, stood as a staunch advocate for secularism, arguing for an inclusive national identity.

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

- Smt. Dakshayani Velayudhan, the first Dalit woman in the Assembly, fearlessly opposed untouchability and fought for the rights of marginalized communities.
- Smt. Durgabai Deshmukh was instrumental in shaping social welfare policies and promoting women's education, contributing to India's early framework for social justice.
- **Smt. Hansa Jivraj Mehta** played a crucial **role in drafting India's fundamental rights, ensuring that gender justice** remained at the core of constitutional debates.
- **Rajkumari Amrit Kaur**, a pioneering stateswoman, was the architect of India's public health policies and **laid the foundation for modern healthcare in the country**.
- Smt. Sarojini Naidu, called as the "Nightingale of India", was an eloquent advocate for civil liberties, leaving a lasting impact on India's democratic ethos.
- Smt. Sucheta Kripalani, who later became India's first female Chief Minister, was a prominent voice in the Assembly and championed labour rights and governance reforms.
- **Smt. Vijayalakshmi Pandit**, a distinguished diplomat, strongly **supported international cooperation and India's role in global governance.**

- **Pritilata Waddedar** was a Bengali revolutionary nationalist who fought against British colonial rule but died in 1932—well before the Constituent Assembly was formed in 1946.

79. (d)

- The **Right to be Forgotten (RTBF)** refers to an individual's right to have personal data removed from internet platforms, search engines, or public databases, particularly when the information is outdated, irrelevant, or no longer necessary. It is connected to the **Right to Privacy**, recognized as a **Fundamental Right** by the Supreme Court in Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) vs. Union of India (2017).

80. (b)

- **About the nature of Constitutions:** A **flexible constitution** can be **amended in the same way as ordinary legislation,** without requiring a special procedure. On the other hand, a **rigid Constitution** is one that requires a **special procedure for its amendment**, as for example, the American Constitution.
- The **Indian Constitution** depicts a **unique blend of both rigidity and flexibility**. Some provisions of the Constitution can be amended by a simple majority in Parliament, making it flexible in parts. However, various other features require a special majority for amendment and also ratification by half of States.
- **1 is correct: Admission or establishment of new States under Article 2** can be done **through an ordinary legislative process**, thus it indicates that the **Constitution is flexible**.
- **2 is correct: Amendment of any of the provisions of the Fifth schedule** can also be done through **ordinary legislative process**, thereby indicating that the Constitution is **flexible**.
- **3 is not correct: Election of the President and its manner** is related to the **federal structure** of the polity can be **amended by a special majority of the Parliament** and also with the **consent of half of the state legislatures** by a simple majority. This provision embodies the **rigid nature** of the Indian Constitution.

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

81. (d)

- **Option (d) is the correct answer: Article 21 guarantees that "No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law."** This **includes privacy**, freedom of movement, and protection from arbitrary state actions, as affirmed in the retd. **Justice K.S. Puttaswamy (2017) judgment**.
- **AI-based surveillance without a legal framework** poses the most direct risk to these rights, as it **can lead to constant tracking of individuals' movements, profiling, and potential misuse of personal data**, all without lawful oversight.

82. (b)

- **Statement 1 is not correct:** In 1948, the **Dhar Commission** was appointed to look into the reorganisation of states. It recommended **administrative convenience** as the basis, not language. **In 1949, the JVP Committee (Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel, Pattabhi Sitaramayya) was set up to examine the same issue.** The **JVP Committee rejected language as the sole basis** for reorganisation, stating that it could lead to administrative and communal problems. Instead, it prioritised **unity, security, and economic well-being** over linguistic criteria.
- **Statement 2 is correct:** A strong demand for a separate Telugu-speaking state led to the death of **Potti Sriramulu** after a 56-day hunger strike in 1952. This resulted in the creation of **Andhra State** (carved out from the Madras Presidency) in 1953, making it the **first state created on linguistic grounds in independent India**.

Additional Information:

- The **States Reorganisation Commission (SRC)** was appointed in 1953 (Fazl Ali, K.M. Panikkar, H.N. Kunzru) and submitted its report in 1955, and broadly accepted language as the basis of reorganisation of states. But, it rejected the theory of 'one language-one state'.
- The **States Reorganisation Act, 1956** led to the creation of 14 states and 6 Union Territories.

83. (b)

- **Option (b) is the correct answer:** The **Directive Principles of State Policy (DPSPs)**, enshrined in **Part IV** of the Constitution (**Articles 36 to 51**), are guidelines for the State to frame laws and policies aimed at achieving the ideals of **social and economic democracy**.
- **Social democracy** under DPSPs **involves ensuring equality, justice, and dignity for all citizens by reducing socio-economic inequalities**.
- **Economic democracy** aims at **equitable distribution of wealth, prevention of exploitation, and provision of adequate livelihood to all sections of society**.
- **Additional information:** DPSPs are inspired from the **Irish Constitution** and rooted in the **concept of a welfare state**. These are **non-justiciable**—meaning they cannot be enforced in a court of law. However, they are **fundamental in the governance of the country** (Article 37).

84. (d)

- **Pair 1 is correctly matched**: DigiLocker is a flagship initiative of Ministry of Electronics & IT (MeitY) under Digital India programme. DigiLocker aims at 'Digital Empowerment' of citizen by providing access to authentic digital documents to citizen's digital document wallet. DigiLocker is a secure cloud based platform for storage, sharing and verification of documents & certificates.
- **Pair 2 is correctly matched**: EntityLocker is a flagship initiative designed to empower

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

organizations by providing a secure, cloud-based platform for storing, sharing, and verifying digital documents and certificates. Aligned with the goals of digital transformation, EntityLocker offers a 'Digital Empowerment' solution that grants organizations access to authentic digital documents through their digital document wallet. This platform ensures safe, efficient, and streamlined document management for businesses and institutions.

- **Pair 3 is correctly matched:** UMANG (Unified Mobile Application for New-age Governance) is a multi-channel platform integrating services of central, state, and local governments, as well as utility bill payments, Aadhaar services, EPFO, Passport Seva, etc., into a single app. UMANG has innumerable services offered by many Government bodies and organisations.

85. (b)

- **Option (b) is the correct answer:** The **PARIVESH Portal** (Pro-Active and Responsive facilitation by Interactive, Virtuous and Environmental Single-window Hub) is an integrated online platform developed by the **Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC)**. It aims to provide **single-window clearance** for various environmental approvals, including: Environmental Clearances (EC), Forest Clearances (FC), Wildlife Clearances, Coastal Regulation Zone (CRZ) clearances. It streamlines processes for project proponents and ensures transparency, accountability, and faster decision-making.
- **Additional Information:**
  - Launched in **August 2018** by the Prime Minister.
  - Links all stakeholders — project proponents, citizens, and government agencies — through a unified dashboard.
  - Enables real-time monitoring of applications and compliance reporting.
  - Part of the government's effort to promote **Ease of Doing Business** while safeguarding environmental norms.

86. (c)

Statement 1 is correct: As per **Article 28(1)** of the Constitution of India, no religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of State funds. However, this restriction does not apply to State-run institutions set up under an endowment or trust that specifically requires religious instruction to be given.

- **Statement 2 is correct:** Under **Article 28(3)**, in educational institutions recognised or aided by the State, religious instruction or worship is allowed, but no person attending such institution can be required to take part in it without their consent (or guardian's consent in the case of minors).

87. (a)

- **About the Indian Independence Act, 1947:** It was the **final piece of legislation passed by the British Parliament dealing with the affairs of India**. It eventually laid the foundations of the British withdrawal from India.
- **Statement 1 is correct:** The Act **proclaimed the lapse of British paramountcy over the Indian princely** states from August 15, 1947. It granted **freedom to** the princely states either to **join the Dominion of India or Dominion of Pakistan or to remain independent**.
- **Statement 2 is not correct:** The Act did **not abolish the Governor-General's office**. Each Dominion (India and Pakistan) was to have a Governor-General appointed by the British King (until Constitutions were framed). **Lord Mountbatten** became the **first Governor-General of independent**

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

India whereas **C. Rajagopalachari became the first Governor-General of independent India.**

- **Additional information:** Other features of the Indian Independence Act, 1947 included:
  - It ended the British rule in India and declared India as an independent and sovereign state from August 15, 1947.
  - It provided for the partition of India and creation of two independent dominions of India and Pakistan with the right to secede from the British Commonwealth.
  - It empowered the Constituent Assemblies of the two dominions to frame and adopt any constitution for their respective nations and to repeal any act of the British Parliament, including the Independence act itself.
  - It provided for the governance of each of the dominions and the provinces by the Government of India Act of 1935, till the new Constitutions were framed.

88. (a)

- **Option (a) is the correct answer:** The **Doctrine of Intelligible Differentia** is a judicial principle **applied while interpreting Article 14** of the Constitution, which guarantees **Equality before Law and Equal Protection of Laws**. According to this doctrine:
  - **Any classification made by law must be based on intelligible differentia**—a clear, reasonable distinction that separates one group from others.
  - This **differentia must have a rational nexus with the objective the law seeks to achieve**.
- This **ensures that laws do not arbitrarily discriminate between individuals or groups, but allow reasonable classifications when justified**. For **Example, a** law providing special benefits to persons with disabilities has an intelligible differentia (physical/mental disability) and a rational nexus (to promote welfare of a disadvantaged group).

89. (c)

- **Article 19(1)(a) of the Constitution** guarantees freedom of speech and expression to citizens, but **Article 19(2)** allows **reasonable restrictions** in the interests of **sovereignty and integrity of India, security of the State, public order, etc.**
- **Statement 2 is correct:** "To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India" is a Fundamental Duty under Article 51A(c). It directly relates to the restrictions under Article 19(2). A satirical act can be critical, but it must not undermine or incite actions against the sovereignty, unity, or integrity of India; otherwise, it could face legal action under Article 19(2) limits.
- **Statement 1 is not correct:** Though Striving towards excellence (Article 51A(j)) is a Fundamental duty, it is not specifically linked to any of the Constitutional restrictions placed on free speech under Article 19(2).

90. (c)

- A bill amending Part IV of the Constitution (i.e. DPSP), is deemed as a **constitutional amendment bill under Article 368** of the Constitution. A **Constitutional Amendment Bill** under **Article 368** requires:
  1. Majority of the total membership of the House
  2. Two-thirds majority of the members present and voting
- **Minimum votes required to meet 1st condition:** More than 50% of the total strength of the House = > 50% of 245 (current strength

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

of Rajya Sabha is 245) = 123

- **Minimum votes required to meet 2nd condition:** (⅔* 180) = 120
- For the Bill to pass, **both** conditions must be met **simultaneously**.
  - **Condition 1:** Needs 123 votes
  - **Condition 2:** Needs 120 votes.
- The **higher number** is the deciding threshold. Therefore, **at least 123** members must support the Bill.

91. (d)

- **Statement 1 is correct:** On 26 January 1950, the **Constituent Assembly ratified India's membership of the Commonwealth of Nations**, agreeing to remain in the association as a Republic.
- **Statement 2 is correct:** The **Assembly elected Dr. Rajendra Prasad as the first President of India** on January 24, 1950.
- **Statement 3 is correct:** After the Constitution came into effect, the **Constituent Assembly was transformed into the Provisional Parliament of India**, functioning in that capacity **until the first general elections in 1952**.
- **Additional information:** Other functions performed by the Constituent Assembly of India:
  - It **adopted** the **national flag on July 22, 1947**.
  - It adopted the **national anthem on January 24, 1950.**
  - It adopted the **national song on January 24, 1950.**

92. (a)

- **Statement 1 is correct: Section 6A** was added to the Citizenship Act, 1955 through the Citizenship (Amendment) Act, 1985. Its purpose was **to give legal effect to key provisions of the Assam Accord,** signed between the Government of India, the Government of Assam, and leaders of the Assam Movement in 1985. The **Assam Accord aimed to address large-scale migration from East Pakistan (now Bangladesh) into Assam** and sought to differentiate between migrants who came before and after a specific cut-off date.
- **Statement 2 is correct:** Under Section 6A, **persons of Indian origin who entered Assam on or before 25 March 1971 from the specified territories (including Bangladesh) are eligible to acquire Indian citizenship**, provided they fulfill certain residency and other conditions.
- **Statement 3 is not correct: Section 6A does not restrict citizenship to religious minorities or to people facing persecution**. The provision is **based on the date of entry and place of origin**, irrespective of religion.

93. (c)

- **Option (c) is the correct answer:** In a **true federation**, there are **two distinct judicial systems** — one for the **Union** and another for the **States**. In contrast, **India follows a unified judicial structure**, with the **Supreme Court at the apex, followed by High Courts and subordinate courts**, which reflects a **unitary characteristic**.
- **Additional information:** Other federal features of Indian Constitution include:
  - **Dual polity - at the Union and State levels**
  - **Written Constitution**
  - **Division of powers between the Centre and States**
  - **Supremacy of the Constitution**

94. (d)

- **Statement 1 is not correct:** The term "**Basic Structure**" refers to the **fundamental and essential features of the Constitution that cannot be altered or destroyed by amendments under Article 368**. This concept was **propounded by the Supreme**

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

Court in the Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973) case. Neither the term "Basic Structure" is mentioned in the Constitution, nor the Parliament has enacted any legislation to define its scope. Instead, the doctrine has been developed and clarified by the judiciary through a series of judicial pronouncements.

- **Statement 2 is not correct:** Not all Fundamental Rights are considered part of the Basic Structure. **Only certain core rights** — such as those ensuring the **rule of law, judicial review, and certain provisions of Articles 14, 19, and 21** — have been **recognised by the Supreme Court as forming part of the Basic Structure**.
- **Additional information**: Other elements of the 'basic structure' of the constitution include:
  - Supremacy of the Constitution **(Kesavananda Bharati case)**
  - Sovereign, democratic and republican nature of the Indian polity
  - Secular character of the Constitution **(Kesavananda Bharati case)**
  - Separation of powers between the legislature, the executive and the judiciary
  - Federal character of the Constitution **(Kesavananda Bharati case)**
  - Unity and integrity of the nation **(S.R. Bommai Case)**
  - Welfare state (socio-economic justice)
  - Judicial review **(Indira Nehru Gandhi case)**
  - Freedom and dignity of the individual
  - Parliamentary system
  - Rule of law **(Indira Nehru Gandhi case)**
  - Harmony and balance between Fundamental Rights and Directive Principles
  - Principle of equality
  - Free and fair elections **(Indira Nehru Gandhi case)**
  - Independence of Judiciary
  - Limited power of Parliament to amend the Constitution **(Minerva Mills case)**
  - Effective access to justice
  - Principles (or essence) underlying fundamental rights
  - Powers of the Supreme Court under Articles 32, 136, 141 and 142
  - Powers of the High Courts under Articles 226 and 227 **(L. Chandra Kumar Case)**

95. (c)

- **About Article 35:** It specifies that **only the Parliament, and not state legislatures, has the authority to make laws for giving effect to certain specified fundamental rights**. This provision **ensures uniformity** across the country in the nature of these rights and in the penalties for violating them.
- **Statement 1 is correct:** Under **Article 16**, the **power to prescribe residence as a condition for certain jobs** or appointments in a state, union territory, or local authority rests solely with Parliament.
- **Statement 2 is correct: Article 17 abolishes untouchability and makes its practice a punishable offence.** Article 35 further provides that **only Parliament can determine the punishment for such offences** declared under fundamental rights, including untouchability.
- **Additional information:** Other instances where the Parliament has the exclusive power to make laws include the following:
  - Granting authority to courts, apart from the Supreme Court and High Courts, to issue various directions, orders, and writs for enforcing fundamental rights (**Article 32**).

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

- Limiting or removing the applicability of Fundamental Rights to members of the armed forces, police, and similar forces (**Article 33**).
- Providing legal protection to government servants or any individual for actions taken during the enforcement of martial law in any area (**Article 34**).
- Prescribing punishment for the offence of promoting Traffic in human beings and forced labour (**Article 23**).

96. (a)

Statement 1 is correct: Article 3 authorises Parliament to form a new state by separating territory from any state or by uniting two or more states or parts of states, or by uniting any territory to a part of any state.

Statement 2 is correct: Before recommending a Bill related to the alteration of state boundaries, the President must refer it to the concerned State Legislature for its views within a specified period.

Statement 3 is not correct: There is no constitutional provision stating that a Bill for changing the name of a state can only be introduced in the Rajya Sabha. Such a bill can be introduced in either Lok Sabha or Rajya Sabha.

Statement 4 is not correct: The consent of the concerned State Legislature is not mandatory; Parliament can alter boundaries or names without their approval, even if their views are against the proposal.

Additional Information:

- Article 3 also empowers Parliament to **increase or diminish the area of a state**, alter boundaries, and alter the name of a state.
- A Bill under Article 3 can be introduced in **either House of Parliament**, but only with **prior recommendation of the President**.
- The President and Parliament are **not bound** by the views of the concerned State Legislature.
- India is described as **"an indestructible Union of destructible states"**—Parliament can change or abolish states, but states cannot alter the Union.

97. (d)

- **About the Preamble:** It is like an **identity card of the Constitution** that **embodies the basic philosophy and fundamental values** on which the Constitution is based. It contains the **grand and noble vision of the Constituent Assembly**, and reflects the dreams and aspirations of the founding fathers of the Constitution.
- The Preamble **envisages to secure the following ideals to all its citizens:**
  - **JUSTICE** - Social, Economic and **Political**; **Thus, 1 is correct.**
  - **LIBERTY of** thought, expression, belief, **faith** and worship; **Thus, 3 is correct.**
  - **EQUALITY of** status and of **opportunity**; **Thus, 2 is correct.**
  - FRATERNITY - assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation.

98. (b)

- **Statement 1 is correct: Article 23(2)** explicitly **allows the State to impose compulsory service for public purposes,** provided no discrimination is made on grounds only of religion, race, caste, or class. Therefore, compulsory service per se is not a violation, if done fairly and without such discrimination.
- **Statement 2 is not correct: Article 23(1) prohibits begar** and all other similar forms of forced labour, including bonded labour, regardless of whether it is enforced by the State or a private individual.
- **Statement 3 is not correct:** While compulsory service for public purposes is allowed, imposing it selectively on a **certain**

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

religion amounts to discrimination solely on the ground of religion, which is prohibited under Article 23(2).

99. (d)

- **Option (d) is the correct answer:** The 25th Constitutional Amendment Act, 1971 inserted Article 31C, which protects laws enacted to implement the Directive Principles contained in Article 39(b) (equitable distribution of resources) and Article 39(c) (prevention of concentration of wealth) from being challenged on the grounds of violating Article 14, Article 19, or Article 31 (right to property — now repealed). Thus, for these specific DPSPs, Parliament can enact laws that are immune from challenges based on Article 14.
- **Option (a) is not correct:** Article 14 does not always have primacy. Under Article 31C, laws implementing Article 39(b) and (c) can override Article 14.
- **Option (b) is not correct:** Constitution does not permit **"any DPSP"** to override Fundamental Rights. Under the 42nd Constitutional Amendment Act, 1976, Parliament attempted to expand Article 31C to protect all laws implementing any Directive Principle from being challenged on grounds of violating Articles 14 and 19. However, in Minerva Mills v. Union of India (1980), the Supreme Court struck down this blanket extension as unconstitutional. At present, Article 31C applies only to laws enacted to implement the DPSPs in Article 39(b) and 39(c), which may override Articles 14 and 19 — and even then, they cannot violate the Basic Structure.
- **Option (c) is not correct:** This was the position in early constitutional history (Champakam Dorairajan, 1951), but after the 25th Amendment, certain DPSPs can override Articles 14 and 19.

100.(a)

- **Statement 1 is correct:** A law enacted by Parliament or a State Legislature can be struck down by the judiciary if it violates any provision of Part III (Fundamental Rights) of the Constitution. This is explicitly provided under Article 13(2).
- **Statement 2 is not correct:** Directive Principles of State Policy (DPSPs) under Part IV are non-justiciable (Article 37). A law cannot be invalidated solely for being inconsistent with DPSPs.
- **Statement 3 is not correct:** The Basic Structure Doctrine applies only to Constitutional Amendments, not ordinary laws. Therefore, ordinary laws cannot be invalidated solely for violating the basic structure; they must be tested against the Constitution itself, especially the Fundamental Rights. In the case of In Anjum Qadiri v. Union of India, 2023, the Hon'ble Supreme Court of India held that only constitutional amendments can be tested against the basic structure doctrine. An ordinary law, even if inconsistent with the basic structure, cannot be struck down on that ground alone. It must violate a specific constitutional provision (like a Fundamental Right) to be invalid.

■■■■

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

NEXT IAS

सामान्य अध्ययन

पेपर-I | सेक्शनल टेस्ट -1

राज्व्यास्था, शासन तथा समसामयिक मामले (जनवरी 2025)

1. (d)

- **विकल्प (d) सही उत्तर है:** परमादेश रिट न्यायालय द्वारा किसी लोक अधिकारी को जारी की जाती है, जिसमें उसे अपने **उन आधिकारिक कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए कहा जाता है, जिन्हें वह पूरा करने में विफल रहा है** या करने से इनकार कर दिया है। इस मामले में, लोक प्राधिकारी का कर्त्तव्य है कि वह भर्ती नियमों का अक्षरशः पालन करे। किसी व्यक्ति को वैवाहिक स्थिति के आधार पर (बिना किसी विधिक आधार के) मनमाने ढंग से अयोग्य ठहराना भेदभावपूर्ण है, क्योंकि यह अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समानता) का उल्लंघन करता है। इसलिए, उम्मीदवार अपने मूल अधिकारों को लागू करने और प्राधिकारी को वैध रूप से कार्य करने के लिए बाध्य करने हेतु उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में परमादेश रिट दायर कर सकता है।
- **अतिरिक्त जानकारी:**

रिट	उद्देश्य
बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)	इसकी प्रकृति एक आदेश की है, जिसमें उस व्यक्ति को, जिसने किसी अन्य को हिरासत में लिया है, न्यायालय के समक्ष उसे प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है, ताकि न्यायालय को यह पता चल सके कि उसे किस आधार पर 'निरुद्ध' किया गया है, तथा यदि कारावास का कोई विधिक औचित्य नहीं है, तो उसे मुक्त किया जा सके।
अधिकार पृच्छा (Quo Warranto)	शाब्दिक रूप से इसका अर्थ है, 'किस प्राधिकार या अधिकार द्वारा'। यह न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद पर दावे की वैधता की जाँच के लिए जारी किया जाता है। इस प्रकार, यह किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद के अवैध अतिक्रमण को रोकता है।
उत्प्रेषण (Certiorari)	यह आदेश किसी उच्चतर न्यायालय, जैसे कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय - द्वारा किसी निचली अदालत या न्यायाधिकरण को या तो उसके पास लंबित किसी मामले को अपने पास स्थानांतरित करने के लिए या निचली अदालत के आदेश को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है।
प्रतिषेध (Prohibition)	यह उच्चतर न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को जारी किया जाता है ताकि निचली अदालत या न्यायाधिकरण को अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने या किसी ऐसे अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने से रोका जा सके, जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। इस प्रकार, परमादेश के विपरीत, जो सक्रियता का निर्देश देता है, प्रतिषेध निष्क्रियता का निर्देश देता है।

2. (c)

- **कथन 1 सही है:** संविधान के अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों को शामिल करने या स्थापित करने, तथा अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का गठन करने या मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने के लिए बनाया गया कोई भी कानून अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसे कानून संसद में साधारण विधायी प्रक्रिया के माध्यम से साधारण बहुमत से बनाए जा सकते हैं।
- **कथन 2 सही है: बेरूबारी यूनियन वाद (1960)** में दिए गए उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार, अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य के क्षेत्रफल को कम करने का संसद का अधिकार किसी विदेशी राष्ट्र को भारतीय क्षेत्र सौंपने तक विस्तारित नहीं है।

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

इसलिए, भारत के किसी भी भूभाग को किसी अन्य देश को हस्तांतरित करना केवल अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के माध्यम से ही संभव है।

- **कथन 3 सही है:** उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारत और किसी अन्य देश के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। ऐसा समाधान कार्यकारी कार्रवाई के माध्यम से किया जा सकता है, क्योंकि इसमें भारत के किसी भी भूभाग को किसी विदेशी राष्ट्र को सौंपने की आवश्यकता नहीं है।

3. (a)

- **1 सही नहीं है, लेकिन 2 सही है: नीति निदेशक सिद्धांत सरकार के विधायी और कार्यपालिका अंगों को सकारात्मक निर्देश देते हैं।** ये राज्य के कुछ सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के कर्त्तव्य की घोषणा करते हैं। इस प्रकार, ये विधायी या कार्यपालिका के कार्यों को सीमित नहीं करते। **इसके विपरीत, मौलिक अधिकार नकारात्मक या निषेधात्मक प्रकृति के होते हैं, क्योंकि ये राज्य पर सीमाएँ लगाते हैं।**
- **3 सही नहीं है:** भाग IV(A) [अनुच्छेद 51(A)] में निहित मूल कर्त्तव्य नागरिकों के लिए नैतिक दायित्व हैं, ये राज्य पर बाधा नहीं हैं।
- **इसलिए विकल्प (a) सही उत्तर है।**

4. (b)

- **1, 2 और 3 सही हैं:** अनुच्छेद 13 में उल्लेख किया गया है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती हो या कम करती हो। इस खण्ड का उल्लंघन करने वाली कोई भी विधि, उल्लंघन की सीमा तक, शून्य होगी। यह आगे स्पष्ट करता है कि **यहाँ "विधि" में भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई भी अध्यादेश, आदेश, उप-विधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, परंपरा या प्रथा शामिल है।**
- **4 सही नहीं है:** अनुच्छेद 13(4) में कहा गया है कि अनुच्छेद 13 का कोई भी प्रावधान अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किए गए संविधान के किसी भी संशोधन पर लागू नहीं होगा। इसलिए, अनुच्छेद 13(4) अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किए गए संवैधानिक संशोधनों को इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए "विधि" की परिभाषा से स्पष्ट रूप से बाहर रखता है। इसका अर्थ है कि ऐसे संशोधनों का अनुच्छेद 13 के विरुद्ध परीक्षण नहीं किया जाता है।

अतिरिक्त जानकारी:

- अनुच्छेद 13(1) घोषित करता है कि **संविधान के प्रारंभ से पूर्व प्रवृत्त सभी कानून, यदि मूल अधिकारों के साथ असंगत हैं,** तो वे उस सीमा तक शून्य हो जाएँगे, जहाँ तक वे मूल अधिकारों के साथ असंगत हैं।

5. (c)

- **कथन-I सही है:** पहली अनुसूची में **राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों की सूची** और उनकी क्षेत्रीय सीमाएँ शामिल हैं। सीमाओं में किसी भी परिवर्तन, नए राज्यों के निर्माण या राज्यों के नाम बदलने के लिए इस अनुसूची में संशोधन आवश्यक है।
- **कथन-II सही नहीं है: दूसरी अनुसूची** संवैधानिक प्राधिकारियों **के वेतन और परिलब्धियों** से संबंधित है। यह प्रादेशिक या राज्य पुनर्गठन से प्रभावित नहीं है।
- **कथन-III सही नहीं है: तीसरी अनुसूची में संवैधानिक** पदाधिकारियों के लिए **शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप** शामिल हैं। यह अनुच्छेद 2 या 3 के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों से अप्रभावित रहती है।
- **कथन-IV सही है: चौथी अनुसूची प्रत्येक राज्य और केंद्र-शासित प्रदेश को राज्य सभा में सीटें आवंटित करती है।** राज्य या क्षेत्र में परिवर्तन इस आवंटन को प्रभावित कर सकते हैं, जिसके लिए अनुसूची में अद्यतनीकरण की आवश्यकता होगी।
- इसलिए, जब संसद अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 के तहत कोई कानून बनाती है, तो केवल **पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता होती है।**

अतिरिक्त जानकारी:

- **पाँचवीं अनुसूची -** अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
- **छठी अनुसूची -** पूर्वोत्तर राज्यों (असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम) में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान शामिल हैं।
- **सातवीं अनुसूची** - संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन (संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची) शामिल हैं।
- **आठवीं अनुसूची -** मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची (वर्तमान में 22 भाषाएँ) शामिल हैं।

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

- **नौवीं अनुसूची -** मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर कानूनों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से बचाने के लिए प्रथम संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई।
- **दसवीं अनुसूची –** दल-बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। दल-बदल विरोधी कानून, 52वें संशोधन, 1985 द्वारा जोड़ा गया।
- **11वीं अनुसूची -** पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व शामिल हैं। इसे 73वें संशोधन, 1992 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें 29 विषय शामिल हैं।
- **12वीं अनुसूची -** नगरपालिकाओं की शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व शामिल हैं। इसे 74वें संशोधन, 1992 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें 18 विषय शामिल हैं।

6. (c)

- **कथन 1 सही है:** अनुच्छेद 15(5) के अनुसार, **राज्य विधि द्वारा,** सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नागरिकों के किसी वर्ग या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए कोई **विशेष प्रावधान कर सकता है**। ऐसे विशेष प्रावधान अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अलावा, **राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थानों** सहित शैक्षणिक संस्थानों में उनके प्रवेश से भी संबंधित हैं। इसलिए, निजी सहायता प्राप्त संस्थानों में SC/ST आरक्षण संवैधानिक रूप से अनुमत है।
- **कथन 2 सही है:** अनुच्छेद 15(6) के अनुसार, राज्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS) की उन्नति के लिए निजी (सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त) शिक्षण संस्थानों में उनके प्रवेश हेतु विशेष प्रावधान कर सकता है। ये प्रावधान सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए किए गए प्रावधानों से अतिरिक्त हैं। इसमें अल्पसंख्यक संस्थान शामिल नहीं हैं। यदि इन प्रावधानों में आरक्षण शामिल है, तो यह मौजूदा आरक्षणों से अलग आरक्षण हो सकता है, किंतु प्रत्येक श्रेणी में कुल सीटों के 10% तक सीमित होना चाहिए।

7. (a)

- **कथन 1 सही है:** प्रत्येक प्रांत और रियासत (या छोटे राज्यों के मामले में राज्यों के समूह) को **उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई थीं।** प्रत्येक दस लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की गई थी।
- **कथन 2 सही नहीं है: रियासतों के मनोनीत सदस्य ब्रिटिश गवर्नरों द्वारा नहीं, बल्कि संबंधित राजाओं द्वारा मनोनीत किए जाते थे।** संविधान सभा में 389 सदस्य होने थे, जिनमें से 296 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से चुने जाने थे और 93 विभिन्न रियासतों से मनोनीत होते थे।
- **कथन 3 सही नहीं है:** प्रत्येक प्रांत में सीटें **तीन मुख्य समुदायों: मुस्लिम, सिक्ख और सामान्य,** के बीच उनकी संबंधित जनसंख्या के अनुपात में वितरित की गईं।

8. (a)

- **कथन 1 सही है::** संविधान के शेष भाग को अपनाने के बाद, 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को अपनाया गया।
- **कथन 2 सही नहीं है:** प्रस्तावना में संविधान के लागू होने की तिथि 26 जनवरी, 1950 नहीं लिखी है। इसके स्थान पर, प्रस्तावना में संविधान को अपनाने की तिथि (जो 26 नवंबर, 1949 है) लिखी है।
- **कथन 3 सही है:** केशवानंद भारती वाद (1973) में दिए गए निर्णय के अनुसार, प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। यद्यपि, यह प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात् इसके प्रावधानों को न्यायालय से लागू नहीं करवाया जा सकता।

अतिरिक्त जानकारी:

42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा प्रस्तावना में "समाजवादी" और "पंथनिरपेक्ष" शब्द शामिल किए गए थे।

9. (b)

- **यौन उत्पीड़न निवारण (PoSH) अधिनियम, 2013 की पृष्ठभूमि:** PoSH अधिनियम, 2013 के मूल 1992 के भँवरी देवी वाद से संबंधित हैं, जहाँ राजस्थान की एक सरकारी कर्मचारी के साथ बाल विवाह रोकने पर सामूहिक बलात्कार किया गया था। इसके परिणामस्वरूप उच्चतम न्यायालय ने ऐतिहासिक विशाखा दिशा-निर्देश (1997) जारी किए थे। इसके अंतर्गत कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को मूल अधिकारों का उल्लंघन माना गया। ये दिशा-निर्देश बाद में PoSH कानून का आधार बने।
- **कथन 1 सही है:** PoSH अधिनियम की धारा 2(o) अधिनियम के प्रयोजनार्थ कार्यस्थल को परिभाषित करती है। यह अधिनियम सभी कार्यस्थलों अर्थात् संगठित और असंगठित दोनों पर लागू होता है, जिसमें निजी क्षेत्र, सरकारी कार्यालय, गैर-

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

सरकारी संगठन आदि शामिल हैं। इसमें गैर-पारंपरिक कार्यस्थल, जैसे कि वे जिनमें दूरसंचार शामिल है और वे स्थान भी शामिल हैं, जहाँ कर्मचारी काम के लिए जाते हैं।

- **कथन 2 सही है:** कानून के अनुसार, 10 से अधिक कर्मचारियों वाले किसी भी नियोक्ता के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति (ICC) बनाना अनिवार्य है। कोई भी महिला कर्मचारी औपचारिक यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने के लिए यहाँ संपर्क कर सकती है। इसकी अध्यक्ष एक महिला होनी चाहिए, साथ ही इसमें कम-से-कम दो महिला कर्मचारी और एक अन्य कर्मचारी होना चाहिए। इसके अलावा वरिष्ठ स्तर से किसी भी तरह के अनुचित दबाव से बचने के लिए, इसमें पाँच वर्ष के अनुभव वाले किसी गैर-सरकारी संगठन कार्यकर्ता जैसे तीसरे पक्ष को भी शामिल किया जाना चाहिए।
    - इसके अलावा, अधिनियम में देश के प्रत्येक जिले को एक स्थानीय समिति (LC) बनाने का आदेश दिया गया है। यह समिति 10 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों में काम करने वाली महिलाओं और घरेलू कामगारों सहित अनौपचारिक क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं की शिकायतें दर्ज करेगी।
- **कथन 3 सही नहीं है:** अधिनियम के तहत "पीड़ित महिला" की परिभाषा बहुत व्यापक है। यह अधिनियम कार्यस्थल पर किसी भी महिला को सुरक्षा प्रदान करता है, चाहे वह वहाँ कार्यरत हो या नहीं, जैसे कि क्लाइंट, ग्राहक, प्रशिक्षु, आगंतुक, घरेलू कामगार और छात्राएँ आदि।
- **कथन 4 सही है:** यह अधिनियम विशेष रूप से महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए है। पुरुष और ट्रांसजेंडर व्यक्ति इसके प्रावधानों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।

अतिरिक्त जानकारी:

- PoSH अधिनियम के अनुसार यौन उत्पीड़न में अवांछित कृत्य शामिल हैं, जैसे - शारीरिक संपर्क और यौन प्रस्ताव, यौन संबंधों की माँग या अनुरोध, यौन रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करना, अश्लील साहित्य दिखाना, तथा यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण आदि।
- समिति द्वारा इस मुद्दे का समाधान करने के दो तरीके बताए गए हैं - शिकायतकर्ता और प्रतिवादी के बीच "समझौते के माध्यम से", किंतु यह वित्तीय समझौता नहीं हो सकता, या समितियाँ जाँच शुरू कर सकती हैं, तथा जो कुछ भी उन्हें ज्ञात होता है उसके आधार पर वे उचित कार्रवाई कर सकती हैं।

10. (a)

- **विकल्प (a) सही उत्तर है: सबसे पहले से शुरू करते हुए सही कालानुक्रमिक क्रम इस प्रकार है,**
- **विकल्प (a): भारत का राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई, 1947 को** आयोजित संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था।
- **विकल्प (d): संविधान सभा ने** 26 नवंबर, 1949 को संविधान का अंतिम प्रारूप अपनाया और **यह 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ।**
- **विकल्प (b) और (c):** संविधान सभा की अंतिम बैठक **24 जनवरी, 1950** को हुई थी। रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित गीत **जन-गण-मन को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी, 1950 को** (अर्थात् संविधान सभा के अंतिम सत्र में) भारत के राष्ट्रगान के रूप में हिंदी संस्करण में अपनाया गया था।

11. (b)

- **कथन-I सही है:** उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय की तुलना में व्यापक है।
- **कथन-II सही है, लेकिन कथन-I की व्याख्या नहीं करता है:** उच्चतम न्यायालय को रिट अधिकारिता संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रदान की गई है, जो स्वयं एक मूल अधिकार है। इसलिए, मूल अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में उच्चतम न्यायालय रिट जारी करने से इनकार नहीं कर सकता। इसके विपरीत, उच्च न्यायालय को रिट अधिकारिता अनुच्छेद 226 से प्राप्त होती है, और वह मूल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों में भी रिट जारी करने या न करने का निर्णय लेने का विवेकाधिकार रखता है।
- **कथन-III सही है और कथन-I की सही व्याख्या करता है:** अनुच्छेद 226 में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि उच्च न्यायालय "भाग III [मूल अधिकार] द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार के प्रवर्तन के लिए और **किसी अन्य उद्देश्य के लिए"** रिट जारी कर सकते हैं। इस "किसी अन्य उद्देश्य" का अर्थ किसी भी कानूनी अधिकार (वैधानिक, संवैधानिक लेकिन मौलिक नहीं, आदि) के प्रवर्तन के लिए है। यह तथ्य कि **उच्च न्यायालय "किसी अन्य उद्देश्य के लिए" (अर्थात्, केवल मूल अधिकारों के अतिरिक्त) रिट जारी कर सकते हैं। यह तथ्य उनके रिट क्षेत्राधिकार को उच्चतम न्यायालय की तुलना में अधिक व्यापक बनाता**

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

है। उच्चतम न्यायालय मुख्य रूप से अनुच्छेद 32 के तहत अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए करता है।

- **इसलिए कथन-II और कथन-III दोनों सही हैं, लेकिन उनमें से केवल एक (कथन-III) कथन-I की व्याख्या करता है।**

12. (c)

- **कथन 1 सही है:** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(A) में उल्लिखित **मूल कर्त्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे।** इनमें से दस को **स्वर्ण सिंह समिति** की सिफ़ारिशों के आधार **पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा** गया था। **ग्यारहवें मूल कर्त्तव्य** को बाद में **86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा** शामिल किया गया था।
- **कथन 2 सही नहीं है:** मूल कर्त्तव्य **केवल नागरिकों** पर लागू होते हैं, सभी निवासियों पर नहीं (जिनमें विदेशी भी शामिल हैं)।
- **कथन 3 सही है:** यद्यपि मूल कर्त्तव्य गैर-प्रवर्तनीय हैं, अर्थात् ये न्यायालयों द्वारा स्वयं लागू नहीं करवाए जा सकते, फिर भी संसद उन्हें प्रभावी बनाने के लिए कानून बना सकती है।

13. (b)

- **अनुच्छेद 20 के बारे में:** यह व्यक्तियों - चाहे वे नागरिक हों, विदेशी हों, अथवा कंपनियों और निगमों जैसी कानूनी संस्थाएँ हों - **को मनमाने और अत्यधिक दण्ड से सुरक्षा प्रदान** करता है। यह अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में तीन प्रमुख सुरक्षा प्रदान करता है:
- **अनुच्छेद 20(1) - पूर्वव्यापी कानूनों के विरुद्ध संरक्षण:** किसी भी व्यक्ति को ऐसे कार्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जो किए जाने के समय अपराध नहीं था, न ही उसे अपराध के समय निर्धारित दण्ड से अधिक दण्ड दिया जा सकता है।
  - **परिस्थिति 1 में,** 2025 का कानून 2021 में किए गए अपराध के लिए अधिक सज़ा का प्रावधान करता है - इस बढ़ी हुई सज़ा को पूर्वव्यापी रूप से लागू करना **अनुच्छेद 20(1) का उल्लंघन होगा।**
- **अनुच्छेद 20(2) - दोहरे संकट से संरक्षण:** किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और उसे दण्डित नहीं किया जा सकता।
  - **परिस्थिति 2 में, विभागीय जाँच और आपराधिक मुकदमे के बाद सेवा से बर्खास्तगी दोहरा संकट नहीं है,** क्योंकि विभागीय कार्रवाई आपराधिक अभियोजन नहीं है, बल्कि **एक प्रशासनिक/अनुशासनात्मक उपाय है।**
- **अनुच्छेद 20(3) - आत्म-दोषसिद्धि के विरुद्ध संरक्षण:** किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह साक्ष्य प्रमाण पर लागू होता है, भौतिक साक्ष्य जैसे उंगलियों के निशान, हस्तलिपि के नमूने या रक्त के नमूने पर नहीं।
  - **परिस्थिति 3 में, रक्त का नमूना देने के लिए बाध्य करना अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि यह भौतिक साक्ष्य है, व्यक्तिगत गवाही नहीं।**

14. (b)

- **कथन 1 सही है:** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30(1) में कहा गया है: "सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हों, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।"
- **कथन 2 सही है:** भारत के संविधान में "अल्पसंख्यक" शब्द का प्रयोग किया गया है (अनुच्छेद 29 और 30 में) लेकिन **इसकी परिभाषा नहीं दी गई है।**
- **कथन 3 सही नहीं है:** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धार्मिक हों या भाषायी, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका संचालन करने का अधिकार होगा। इसलिए, अनुच्छेद 30 **केवल धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों को** मान्यता देता है, नस्लीय अल्पसंख्यकों को नहीं।

15. (d)

- **कथन 1 सही नहीं है:**
  - विधि की सम्यक प्रक्रिया नागरिकों को केवल कार्यकारी कार्यों से ही नहीं, बल्कि कार्यकारी और विधायी दोनों प्रकार के कार्यों से सुरक्षा प्रदान करती है।
  - विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया विधायिका द्वारा पारित कानूनों पर भी लागू होती है, लेकिन यह मुख्य रूप से कार्यपालिका की मनमानी कार्यवाहियों से सुरक्षा प्रदान करती है।

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

- **कथन 2 सही नहीं है:**
  - विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया न्यायिक समीक्षा को केवल इस बात की जाँच तक सीमित करती है कि **क्या कानून बनाते समय सही प्रक्रिया का पालन किया गया था** - यह कानून की निष्पक्षता, न्याय या मनमानी की जाँच नहीं करती है।
  - दूसरी ओर, विधि की सम्यक प्रक्रिया, **कानून के प्रक्रियागत अनुपालन और वास्तविक निष्पक्षता दोनों** की समीक्षा करती है।

अतिरिक्त जानकारी:

- मूल:
  - विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया → ब्रिटेन से ली गई है।
  - विधि की सम्यक प्रक्रिया → इसका उल्लेख मैग्नाकार्टा में किया गया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में विकसित हुआ था।
- **भारत की स्थिति:** प्रारंभ में, भारतीय संविधान ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया, लेकिन मेनका गाँधी बनाम भारत संघ वाद (1978) के बाद, उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत प्रक्रिया की "न्यायसंगत, निष्पक्ष और सम्यक" के रूप में व्याख्या करके इसे विधि की सम्यक प्रक्रिया की तरह स्थापित किया।

16. (a)

- मैक्सिको की खाड़ी (GOM) की सीमा संयुक्त राज्य अमेरिका (उत्तर में), मैक्सिको (पश्चिम और दक्षिण में) और क्यूबा (दक्षिण-पूर्व में) से लगती है।
- होंडुरास और ग्वाटेमाला मध्य अमेरिका में स्थित हैं और इनकी सीमाएँ मैक्सिको की खाड़ी को स्पर्श नहीं करती हैं।
- मैक्सिको की खाड़ी, मध्य अमेरिका और कैरिबियन में छोटे, परस्पर संबद्ध महासागरीय बेसिन, विभिन्न भू-क्षेत्रों और स्थलाकृतिक उच्चावचों वाले महासागरीय द्वीपों की श्रृंखलाएँ तथा मध्य अमेरिका का स्थलडमरूमध्य शामिल है, जो उत्तर और दक्षिण अमेरिका के बीच एकमात्र निरंतर, स्थलीय संपर्क प्रदान करता है।

17. (b)

- **संदर्भ**: अमेरिकी राष्ट्रपति ने पनामा नहर को वापस लेने की धमकी दी है और हस्तांतरण संधि को "मूर्खतापूर्ण" बताया है। अमेरिका के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति की नाराज़गी का मुख्य कारण पनामा नहर प्राधिकरण (ACP) द्वारा अमेरिकी जहाज़ों पर लगाया जाने वाला उच्च पारगमन शुल्क है।
- **कथन 1 सही नहीं है:** पनामा नहर एक 82 किलोमीटर लंबा रणनीतिक जलमार्ग है, जो **प्रशांत और अटलांटिक महासागरों** को जोड़ती है।
- **कथन 2 सही है: पनामा नहर संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट (जैसे, न्यूयॉर्क) और पश्चिमी तट (जैसे, लॉस एंजिल्स/सैन फ्रांसिस्को) के बीच यात्रा करने वाले जहाज़ों के लिए एक लघु मार्ग प्रदान करती है।** नहर के बिना, जहाज़ों को दक्षिण अमेरिका के चारों ओर लंबे और दुर्गम मार्ग से यात्रा करनी पड़ती है, जिससे हज़ारों किलोमीटर की दूरी बढ़ जाती।
- **कथन 3 सही नहीं है:** वर्ष 1977 में, तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर और पनामा के सैन्य नेता उमर टोरिजोस ने दो संधियों - स्थायी तटस्थता संधि और पनामा नहर संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत वर्ष 1999 में अमेरिका ने नहर का नियंत्रण पनामा को सौंप दिया।

18. (b)

- **संदर्भ**: हाल ही में (2024-2025) चल रहे इज़राइल-हमास संघर्ष के कारण, फ़िलाडेल्फिया कॉरिडोर सीमा नियंत्रण पर वार्ता का केंद्रबिंदु बन गया है। सैन्य अभियानों के लिए इसके संभावित उपयोग और राफा में फ़िलिस्तीनियों पर इसके मानवीय प्रभाव को लेकर चिंताएँ व्यक्त की गई हैं।
- **फ़िलाडेल्फिया कॉरिडोर** (जिसे **सलाह अल-दीन कॉरिडोर** के नाम से भी जाना जाता है) **भूमि की एक संकरी पट्टी है,** जो **ग़ज़ा पट्टी और मिस्र,** विशेष रूप से मिस्र के **राफा** शहर **की सीमा पर स्थित** है।
- यह एक **बफ़र ज़ोन** के रूप में कार्य करता है और इसका सामरिक महत्त्व है, क्योंकि इसका उपयोग **वस्तुओं और लोगों के आवागमन** के लिए किया जाता रहा है। पूर्व में इसका उपयोग ग़ज़ा और मिस्र के बीच **तस्करी सुरंगों** के लिए किया जाता था।

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

19. (b)

- **संदर्भ**: 21 जनवरी, 2025 को "क्वाड सहयोग" की 20वीं वर्षगाँठ के उपलक्ष्य में समूह के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया।
- **1 और 3 सही हैं:** भारत क्वाड और ब्रिक्स का सदस्य है।
  - **क्वाड**: यह **ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका** के बीच एक कूटनीतिक साझेदारी है, जो एक शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो समावेशी और लचीला हो।
  - **ऑकस (AUKUS):** यह **ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका** के बीच एक सुरक्षा समझौता है, जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र में प्रौद्योगिकी साझाकरण पर केंद्रित है।
  - **ब्रिक्स**: यह प्रमुख विकासशील देशों द्वारा गठित एक समूह है, जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ़्रीका, ईरान, मिस्र, इथियोपिया, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल हैं।
  - **फ़ाइव आईज़ अलायंस:** यह अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूज़ीलैंड के बीच एक खुफ़िया जानकारी साझा करने वाला गठबंधन है।

20. (d)

- **कथन 1 सही है: नीति आयोग के शासकीय अधिदेश के अनुसार, भारत के प्रधानमंत्री** इस संस्था के पदेन अध्यक्ष होते हैं।
- **कथन 2 सही है:** नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी, 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक कार्यकारी प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी, इसने योजना आयोग का स्थान लिया था। संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। **यह संसद के अधिनियम द्वारा निर्मित नहीं है (इसलिए यह एक वैधानिक निकाय नहीं है)। अतः यह एक कार्यकारी/अतिरिक्त-संवैधानिक निकाय है।**
- **कथन 3 सही है: नीति आयोग का शासी परिषद्** 16 फरवरी, 2015 को कैबिनेट सचिवालय द्वारा एक अधिसूचना के माध्यम से प्रभावी हुआ था। इसमें **सभी राज्यों और विधानसभाओं वाले केंद्र-शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री** और अन्य केंद्र-शासित प्रदेशों के उप-राज्यपाल शामिल होते हैं।

21. (c)

- **दिए गए विकल्पों में से, केवल 2, 4 और 5 ही भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं।**
- केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार इस प्रकार हैं:
  - **अनुच्छेद 15:** धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध (अतः 2 सही है)
  - **अनुच्छेद 16:** लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता
  - **अनुच्छेद 19:** निम्नलिखित स्वतंत्रता से संबंधित छह अधिकारों का संरक्षण:
    i. वाक्-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य,
    ii. शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन,
    iii. संगम या संघ ' [या सहकारी सोसाइटी] बनाने,
    iv. भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण,
    v. भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने,
    vi. कोई वृत्ति अपनाने या व्यवसाय करने का अधिकार (इसलिए पॉइंट 4 और 5 सही हैं)
- **अनुच्छेद 29:** अल्पसंख्यक वर्गों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण
- **अनुच्छेद 30:** अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार

22. (b)

- **विकल्प (b) सही उत्तर है:** शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में निहित है। इसमें निम्नलिखित अधिकार शामिल हैं:

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

- **अनुच्छेद 23** मानव के दुर्व्यापार और बेगार (बलात श्रम) और इसी प्रकार के अन्य बलात श्रम का प्रतिषेध करता है।
- **अनुच्छेद 24** में कहा गया है **कि चौदह वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।**

23. (d)

- **कथन 1 सही है:** अनिवासी भारतीय (NRI) एक भारतीय नागरिक होता है, जो सामान्यतः भारत से बाहर रहता है। OCI कार्डधारक भारत के नागरिक नहीं हैं। OCI भारतीय मूल का व्यक्ति है, जो एक विदेशी नागरिक होता है और नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7(A) के तहत प्रवासी भारतीय नागरिक कार्डधारक के रूप में पंजीकृत होता है।
- **कथन 2 सही है:** OCI कार्डधारक भारत में सार्वजनिक पद धारण करने के हकदार नहीं हैं और न ही वे भारत में चुनावों में मतदान कर सकते हैं।
- **कथन 3 सही है:** एक OCI कार्डधारक को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं:
  - भारत आने के लिए बहुउद्देश्यीय, बहु-प्रवेश, आजीवन वीज़ा।
  - भारत में किसी भी अवधि के प्रवास के लिए स्थानीय पुलिस प्राधिकरण के साथ पंजीकरण से छूट।
  - कृषि/बागवानी संपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित मामलों को छोड़कर, आर्थिक, वित्तीय और शिक्षा के क्षेत्रों में अनिवासी भारतीयों के समान अधिकार प्राप्त है।

24. (b)

- **कथन 1 सही नहीं है: 'उद्देश्य प्रस्ताव' 13 दिसंबर, 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू** द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इसे संविधान सभा ने 22 जनवरी, 1947 को अपनाया था। इसने संविधान निर्माण के लिए दर्शन और मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान किए और बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में रूपांतरित हो गया।
- **कथन 2 सही नहीं है: प्रस्तावना न तो विधायिका को शक्ति प्रदान करती है और न ही उसकी प्राधिकारिता पर कोई प्रतिबंध लगाती है।** हालाँकि, यह संविधान की व्याख्या करने और अस्पष्ट प्रावधानों को स्पष्ट करने में एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाती है।
- **कथन 3 सही है:** प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार **42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976** द्वारा संशोधन किया गया है। इस संशोधन ने प्रस्तावना में "समाजवादी" और "पंथनिरपेक्ष" शब्द जोड़े और "राष्ट्र की एकता" वाक्यांश में "अखण्डता" शब्द भी जोड़ा।

25. (c)

- प्रस्तावना में **42वें संविधान संशोधन अधिनियम (1976)** द्वारा संशोधन किया गया था, जिसमें तीन नए शब्द जोड़े गए - **समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखण्डता।**
- **अतिरिक्त जानकारी: प्रस्तावना के 4 मुख्य तत्त्व:**
  - **अधिकार का स्रोत:** प्रस्तावना यह पुष्टि करती है कि संविधान को शक्ति भारत की जनता से प्राप्त होती है।
  - **भारतीय राज्य की प्रकृति:** यह भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य घोषित करती है।
  - **उद्देश्य**: यह न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को मार्गदर्शक लक्ष्य के रूप में निर्धारित करती है।
- **न्याय**: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक
- **स्वतंत्रता**: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की
- **समता**: प्रतिष्ठा और अवसर की
- **बंधुत्व**: व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करना
  - **अंगीकरण की तिथि:** इसमें 26 नवंबर, 1949 को संविधान को अंगीकृत करने की तिथि के रूप में उल्लेख किया गया है।

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

26. (c)

- **कथन 1 सही है:** यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता ऐसी प्राप्ति की तिथि से स्वतः ही समाप्त हो जाती है।
- **कथन 2 सही है:** यह उन व्यक्तियों पर लागू होता है, जो पंजीकरण या देशीयकरण के माध्यम से नागरिकता अर्जित करता है। यदि ऐसे व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त करने के पाँच वर्षों के भीतर किसी भी देश में कम-से-कम दो वर्ष की अवधि के कारावास की सज़ा सुनाई जाती है, तो केंद्र सरकार उसे भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है।
- **कथन 3 सही नहीं है: अधिनियम भारत के बाहर सात वर्षों के निरंतर निवास को निर्दिष्ट करता है, पाँच वर्षों को नहीं।**
- **कथन 4 सही है**: यदि किसी नागरिक ने युद्ध के दौरान, जिसमें भारत शामिल है, किसी शत्रु के साथ व्यापार या संचार किया है, या भारत की संप्रभुता, सुरक्षा या अखण्डता के विरुद्ध कार्यों में लिप्त रहा है, तो सरकार ऐसे व्यक्ति को नागरिकता से वंचित कर सकती है।
- **अतिरिक्त जानकारी:** नागरिकता के संबंध में संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार हैं:
  1. कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा या भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, यदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर ली है।
  2. प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जो संसद द्वारा बनाई जाए, भारत का नागरिक बना रहेगा।
  3. संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति और नागरिकता से संबंधित अन्य सभी मामलों के संबंध में कोई भी प्रावधान करने की शक्ति होगी।

27. (d)

- **कथन 1 सही है:** अनुच्छेद 18(1) राज्य , सेना या शैक्षणिक उपाधियों के अलावा कोई भी उपाधि प्रदान करने से रोकता है।
- **कथन 2 सही है:** अनुच्छेद 18(2) भारतीय नागरिकों को किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार करने से रोकता है।
- **कथन 3 सही नहीं है:** अनुच्छेद 18(3) राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार करने के लिए **राष्ट्रपति** की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है, न कि प्रधानमंत्री की।
- **अतिरिक्त जानकारी:** उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय पुरस्कारों - **भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री - की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है।** इसने निर्णय दिया है कि ये पुरस्कार अनुच्छेद 18 के अर्थ में 'उपाधियाँ' नहीं हैं, क्योंकि अनुच्छेद केवल वंशानुगत कुलीनता की उपाधियों को रोकता है। इसलिए, ये अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं करते, क्योंकि समता के सिद्धांत के तहत यह आवश्यक नहीं है कि योग्यता और उपलब्धियों को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए।

28. (b)

- **भारतीय संविधान के भाग IV** (राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व) के अनुच्छेद 50 में **न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्** करने की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि "राज्य, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् करने के लिए कदम उठाएगा।"

29. (b)

- **कथन 1 और कथन 3 सही हैं:** जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाले किसी कानून के तहत पारित आदेश के अंतर्गत हिरासत में लिया जाता है, तो आदेश देने वाला प्राधिकारी, यथाशीघ्र, ऐसे व्यक्ति को उन आधारों से अवगत कराएगा जिन पर आदेश पारित किया गया है और उसे आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का शीघ्रातिशीघ्र अवसर प्रदान करेगा।
- **कथन 2 सही नहीं है:** अनुच्छेद 22(2) में कहा गया है कि गिरफ़्तार किए गए और अभिरक्षा में निरुद्ध किए गए व्यक्ति को गिरफ़्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर, ऐसी गिरफ़्तारी के 24 घंटे की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। लेकिन **अनुच्छेद 22(3) में कहा गया है कि अनुच्छेद 22(2) की कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी, जिसे किसी निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ़्तार या निरुद्ध किया गया है।**

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

अतिरिक्त जानकारी:

- अनुच्छेद 22 का दूसरा भाग उन व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है, जिन्हें निवारक निरोध कानून के तहत हिरासत में लिया गया है। यह सुरक्षा नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध है और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
  - (i) किसी व्यक्ति की हिरासत अवधि तीन महीने से अधिक नहीं हो सकती है, जब तक कि सलाहकार बोर्ड विस्तारित हिरासत के लिए पर्याप्त कारण की रिपोर्ट न दे। बोर्ड में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल होंगे।
  - (ii) प्राधिकारियों को हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत के कारणों के बारे में सूचित करना होगा, सिवाय इसके कि जब प्रकटीकरण को जनहित के विरुद्ध माना जाए।
  - (iii) निवारक रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

30. (b)

- **कथन 1 सही नहीं है:** संविधान के भाग II के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है, लेकिन इस विषय पर न तो स्थायी और न ही विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। यह केवल यह निर्दिष्ट करता है कि 26 जनवरी, 1950 को इसके लागू होने के समय कौन भारत का नागरिक बना, यह यह नहीं बताता कि उसके बाद नागरिकता कैसे प्राप्त या समाप्त किया जा सकता है। इसके बजाय, यह संसद को इन मामलों पर कानून बनाने का अधिकार देता है, जिसके तहत नागरिकता अधिनियम, 1955 लागू किया गया था।
- **कथन 2 सही है:** नागरिकता अधिनियम, 1955 पंजीकरण और देशीयकरण के साथ-साथ जन्म, वंश और क्षेत्र के समावेश जैसे अन्य तरीकों से नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान करता है।

31. (a)

- रानी वेलु नाचियार का जन्म 1730 ईसवी में हुआ था। यह तमिलनाडु के शिवगंगा रियासत की एक साहसी और दूरदर्शी रानी थीं। इन्हें वर्ष 1857 के विद्रोह से बहुत पहले, **ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध सशस्त्र प्रतिरोध का नेतृत्व करने वाली प्रथम भारतीय रानी** के रूप में जाना जाता है।
- जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके राज्य पर कब्ज़ा करने के लिए अर्काट के नवाब के साथ गठबंधन किया, तो उन्होंने आत्म-समर्पण करने से इनकार कर दिया और निर्वासन में चली गईं। इस अवधि के दौरान, उन्होंने **आठ वर्ष तक रणनीतिक रूप से अपने जवाबी हमले की रणनीति बनाई**, गठबंधन को मज़बूत किया और सेना को एकत्रित किया।
- उनकी वापसी एक साहसिक और सुव्यवस्थित सैन्य अभियान द्वारा चिह्नित थी। इस अभियान का एक महत्त्वपूर्ण मोड़ उनकी सेनापति कुइली के साहसी बलिदान से आया, **जिन्होंने ब्रिटिश गोला-बारूद डिपो को नष्ट करने के लिए आत्मदाह कर लिया,** जिससे नाचियार की सेना को एक महत्त्वपूर्ण बढ़त मिली।
- इसके अलावा, **रानी वेलु नाचियार ने "उदय्यल पदई" नामक एक महिला रेजिमेंट का गठन** किया, जो युद्ध में महिलाओं को सशक्त बनाने के उनके प्रगतिशील नेतृत्व को दर्शाता है।
- उनका वीरतापूर्ण संघर्ष और सफल प्रतिरोध भारत में **किसी महिला द्वारा ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व करने का प्रथम दर्ज उदाहरण है,** जिससे उन्हें भारतीय इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।

32. (a)

- **खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देने और पुरस्कृत करने के लिए प्रति वर्ष राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।**
- **युग्म 1 सही सुमेलित है:** 'खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार' पिछले चार वर्षों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन और नेतृत्व, खेल कौशल और अनुशासन की भावना दिखाने के लिए दिया जाता है।
- **युग्म 2 सही सुमेलित है:** 'खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार' प्रशिक्षकों को निरंतर उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए दिया जाता है।
- **युग्म 3 सही सुमेलित नहीं है:** 'मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार' पिछले चार वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है।
- **अतिरिक्त जानकारी:** अर्जुन पुरस्कार (आजीवन) उन खिलाड़ियों को सम्मानित और प्रेरित करने के लिए दिया जाता है, जिन्होंने अपने प्रदर्शन के माध्यम से खेलों में योगदान दिया है और सक्रिय खेल करियर से संन्यास लेने के बाद भी खेलों के प्रचार में योगदान देना जारी रखते हैं।

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

33. (c)

- एक औपचारिक समूह के रूप में, ब्रिक की शुरुआत वर्ष 2006 में रूस, भारत और चीन के नेताओं की सेंट पीटर्सबर्ग में G8 आउटरीच समिट के दौरान हुई बैठक के बाद हुई थी। इस समूह को वर्ष 2006 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान हुई ब्रिक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में औपचारिक रूप दिया गया था। पहला ब्रिक शिखर सम्मेलन वर्ष 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया था।
- **ब्रिक्स** समूह—जिसमें मूल रूप से **ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ़्रीका** शामिल थे—का वर्ष 2024 में विस्तार किया गया और इसमें **मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात** को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया।
- **जनवरी 2025 में, इंडोनेशिया** आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स में शामिल किया गया।
- हालाँकि, **इराक़** ब्रिक्स का सदस्य **नहीं** है।

34. (b)

- **बिज़नेस रेडी (B-READY)** विश्व बैंक समूह की एक प्रमुख रिपोर्ट है, जिसे वर्ष 2024 में प्रारंभ किया गया।
- यह पूर्ववर्ती **डूइंग बिज़नेस** परियोजना का स्थान लेती है तथा उसमें सुधार करती है।
- **उद्देश्य:** वैश्विक स्तर पर व्यापार एवं निवेश वातावरण का मूल्यांकन करना, जिसमें केवल उद्यमों के हित ही नहीं, बल्कि श्रमिकों, उपभोक्ताओं, नए उद्यमों तथा पर्यावरण के हितों को भी सम्मिलित किया जाता है।
- **ढाँचा:** अर्थव्यवस्थाओं का आकलन तीन स्तंभों पर किया जाता है — विनियामक ढाँचा, सार्वजनिक सेवाएँ तथा परिचालन दक्षता।
  वर्ष 2024 में कवरेज: 50 अर्थव्यवस्थाएँ; आगे चलकर पद्धति का विस्तार एवं परिष्कार करने की योजना है।

अतिरिक्त जानकारी:

- **10 विषय किसी फ़र्म के जीवन चक्र** से जुड़े होते हैं (जैसे, व्यवसाय शुरू करना, करों का भुगतान करना, उपयोगिताओं तक पहुँच)।
- **तीन परस्पर संबद्ध विषय:** डिजिटल अपनाना, पर्यावरणीय स्थिरता, और लिंग।
- डेटा के लिए **विशेषज्ञ प्रश्नावली** और **फ़र्म-स्तरीय सर्वेक्षण** का उपयोग करता है।
- **सुधार हेतु पक्षसमर्थन**, **नीति मार्गदर्शन** और आगे के अनुसंधान का समर्थन करता है।

35. (a)

संदर्भ: इस वर्ष 22 जनवरी, 2025 को **10 वर्ष पूरे हो रहे हैं। सुकन्या समृद्धि योजना** परिवारों को अपनी बेटियों के उज्ज्वल भविष्य में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है, तथा समावेशिता और प्रगति की संस्कृति को बढ़ावा देती है।

- **कथन 1 सही है:** एक अभिभावक बालिका के जन्म के तुरंत बाद से लेकर उसके **10 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक खाता खोल सकता है।**
- **कथन 2 सही है: खाते में जमा राशि** खाता खोलने की तिथि से अधिकतम **15 वर्षों तक की जा सकती है।**
- **कथन 3 सही नहीं है:** समय से पहले खाता बंद करना **केवल मृत्यु तक ही सीमित नहीं है** - परिपक्वता से पहले इच्छित विवाह के मामलों में और **अनुकंपा/करुणा के आधार पर** (खाता धारक की जीवन-घातक चिकित्सीय स्थिति या अभिभावक की मृत्यु) भी इसकी अनुमति है।

अतिरिक्त जानकारी:

- **प्रति बच्चा एक खाता**; प्रति परिवार अधिकतम **दो खाते (जुड़वाँ/तीन बच्चों** के लिए अपवाद)।
- जब तक लड़की **18 वर्ष की नहीं हो जाती, तब तक अभिभावक खाते का प्रबंधन करता है,** उसके बाद वह स्वयं इसका संचालन कर सकती है।
- **परिपक्वता:** खाता खोलने की तिथि से 21 वर्ष।

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

- **आहरण: शिक्षा हेतु शेष राशि (पिछले वित्तीय वर्ष के अनुसार) का अधिकतम 50%** निकाला जा सकता है — एकमुश्त या किस्तों में (अधिकतम 1 बार प्रतिवर्ष, अधिकतम 5 वर्षों तक)।

36. (a)

- **विकल्प (ए) सही उत्तर है:**
  - **अंत:करण की स्वतंत्रता:** किसी व्यक्ति की आंतरिक स्वतंत्रता, जिसके अंतर्गत वह ईश्वर अथवा अन्य जीवों के साथ अपने संबंध को अपनी इच्छानुसार ढाल सकता है। अत: A-2 सही है।
  - **मानने का अधिकार:** अपनी धार्मिक मान्यताओं और आस्था की खुलेआम और स्वतंत्र रूप से घोषणा। इसलिए, B-1 सही है।
  - धार्मिक पूजा-अर्चना, अनुष्ठान, समारोह और विश्वासों एवं विचारों के प्रदर्शन **का अधिकार। अत: C-4 सही है।**
  - **प्रचार का अधिकार:** अपने धार्मिक विश्वासों को दूसरों तक पहुँचाना या अपने धर्म के सिद्धांतों का प्रतिपादन करना। अत:, D-3 सही है।

अतिरिक्त जानकारी:

- अनुच्छेद 25 गैर-नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों को **अंत:करण की स्वतंत्रता तथा धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने के** अधिकार की गारंटी देता है।
- **सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य** और अन्य मौलिक अधिकारों के अधीन है।
- बलात् धर्मांतरण की अनुमति नहीं है, क्योंकि इससे किसी अन्य व्यक्ति की अंतरात्मा की स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है।
- राज्य धर्म से जुड़ी धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को विनियमित कर सकता है और सामाजिक सुधार को बढ़ावा दे सकता है, जिसमें हिंदू धार्मिक संस्थानों को सभी वर्गों और तबकों के लिए खोलना भी शामिल है।
- कृपाण पहनना और लेकर चलना सिक्ख धर्म के पालन का अभिन्न अंग माना जाता है।
- इस संदर्भ में, "हिंदुओं" में **सिक्ख, जैन और बौद्ध भी शामिल हैं।**

37. (d)

कथन 1 सही है: अनुच्छेद 51(A)(f) में कहा गया है कि देश की समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्त्व देना और संरक्षित करना प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है।

कथन 2 सही है: अनुच्छेद 51(A)(i) में प्रावधान है कि नागरिकों को सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करनी चाहिए और हिंसा से दूर रहना चाहिए।

कथन 3 सही है: अनुच्छेद 51(A)(g) निर्दिष्ट करता है कि नागरिकों को वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना चाहिए, और जीवित प्राणियों के प्रति दया रखनी चाहिए।

अतिरिक्त जानकारी: अनुच्छेद 51(A) के तहत मौलिक कर्त्तव्य: अनुच्छेद 51(A) के अनुसार, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा:

a. संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करे।

b. स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे।

c. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे तथा उसे अक्षुण्ण रखे।

d. देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे।

e. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे; जो धर्म, भाषा व प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो; ऐसी प्रथाओं का त्याग करे, जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं।

f. हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे।

g. प्राकृतिक पर्यावरण; जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव आते हैं; की रक्षा और संवर्धन करे तथा प्राणीमात्र के लिए दया भाव रखे।

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

h. वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे।

i. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे।

j. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करे, जिससे राष्ट्र प्रगति की और निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को प्राप्त किया जा सके।

k. **छह से चौदह वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चे बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना** (इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया)।

38. (b)

- **विकल्प (b) सही उत्तर है: उत्प्रेषण (Certiorari)** रिट का अर्थ है, "प्रमाणित करना" या "सूचित किया जाना"। यह **उच्च न्यायालय द्वारा निचली न्यायालय या न्यायाधिकरण को किसी चल रहे मामले को अपने पास स्थानांतरित करने या उसके आदेश को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है।** इसके जारी होने के **आधार में अधिकार क्षेत्र से परे कार्य करना, अधिकार क्षेत्र का अभाव या कानूनी त्रुटि** शामिल है। प्रतिषेध (Prohibition) के विपरीत, जो विशुद्ध रूप से निवारक है, उत्प्रेषण रिट एक निवारक और सुधारात्मक दोनों भूमिका निभाता है।
- **अतिरिक्त जानकारी: उत्प्रेषण** रिट **न्यायिक प्राधिकारियों, अर्ध-न्यायिक प्राधिकारियों के** साथ-साथ **प्रशासनिक प्राधिकारियों के विरुद्ध भी जारी की** जा सकती है।

39. (a)

- **युग्म 1 सही सुमेलित है: राज्यपाल का पद भारत सरकार अधिनियम, 1935** से प्रेरित है। इस अधिनियम से प्रेरित अन्य विशेषताओं में **संघीय योजना, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण शामिल हैं।**
- **युग्म 2 सही सुमेलित है: सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया** संयुक्त **राज्य अमेरिका के संविधान** से प्रेरित है। अन्य विशेषताओं में **मौलिक अधिकार**, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, **न्यायिक समीक्षा**, **राष्ट्रपति पर महाभियोग** और उप-राष्ट्रपति का पद शामिल हैं।
- **युग्म 3 सही सुमेलित नहीं है: समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलियाई संविधान** से प्रेरित है। ऑस्ट्रेलियाई संविधान से प्रेरित अन्य विशेषताओं में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक शामिल हैं।
- **अतिरिक्त जानकारी:** भारतीय संविधान की विशेषताएँ, जो अन्य देशों के संविधानों से प्रेरित हैं:
  - **ब्रिटेन** - संसदीय सरकार, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रिट, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीयता।
  - **आयरलैंड** - राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत, राज्य सभा के सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि।
  - **कनाडा** - एक मज़बूत केंद्र वाला संघ, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, तथा सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार।
  - **जर्मनी** - आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन।
  - **यूएसएसआर (रूस)** - उद्देशिका में मौलिक कर्त्तव्य और न्याय का आदर्श (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक)।
  - **फ़्रांस** - गणराज्य और उद्देशिका में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श।
  - **दक्षिण अफ़्रीका** - संविधान संशोधन और राज्य सभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया।
  - **जापान** - विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।

40. (d)

- **कथन-I सही नहीं है:** संविधान का अनुच्छेद 21(A) (86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया) **निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा** प्रदान करना **राज्य की ज़िम्मेदारी बनाता है। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया।**

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

- **कथन-II सही है:**
  - **राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत**: अनुच्छेद 45 राज्य को निर्देश देता है कि वह सभी बच्चों को **छह वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करे।**
  - **मौलिक कर्त्तव्य: अनुच्छेद 51(A)(k) माता-पिता/अभिभावकों पर यह कर्त्तव्य डालता है कि वे 6 से 14 वर्ष की आयु के** अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

41. (c)

- **अनुच्छेद 19 के बारे में: यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता** आदि से संबंधित नागरिकों के कुछ अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। **अनुच्छेद 19(1) में** कहा गया है कि सभी नागरिकों को निम्नलिखित का अधिकार होगा:
  - वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
  - शांतिपूर्ण और निरायुद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता
  - संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता
  - भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता
  - भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र कही भी बस जाने की स्वतंत्रता
  - कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता
- **अनुच्छेद 19(2) अनुच्छेद 19(1) द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर युक्तिसंगत प्रतिबंधों** से संबंधित है। इन प्रतिबंधों में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - भारत की संप्रभुता और अखंडता के हितों की रक्षा करना।
  - राज्य की सुरक्षा।
  - **विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। अतः, 1 सही है।**
  - **लोक व्यवस्था। इस प्रकार, 4 सही है।**
  - शालीनता या नैतिकता
  - न्यायालय की अवमानना
  - मानहानि
  - **किसी अपराध के लिए उकसाना। इस प्रकार, 2 सही है।**
- **3 सही नहीं है: किसी भी अनुसूचित जनजाति के हितों का संरक्षण भारत के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने के अधिकार और** भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने के अधिकार पर प्रतिबंध है।

42. (b)

- **विकल्प (b) सही उत्तर है:** उच्चतम न्यायालय ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के विरुद्ध एक ऐसे मौलिक अधिकार को संविधान में एक पृथक् अधिकार के रूप में मान्यता दी है, जिसकी आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी, परंतु जिस पर अब तक स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति नहीं की गई थी।
- "यह अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है कि लोगों को जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के विरुद्ध आवाज़ उठाने का अधिकार है। ऐसा शायद इसलिए है, क्योंकि यह अधिकार और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।"
- जैसे-जैसे जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न तबाही वर्ष-दर-वर्ष बढ़ती जा रही है, इस अधिकार को एक पृथक् अधिकार के रूप में अभिव्यक्त करना आवश्यक हो गया है। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 (समता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है," ऐसा उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा।
- यह निर्णय पहले लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रजाति के अस्तित्व से जुड़े एक मामले में आया था।

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

43. (b)

- **युग्म 1 सही सुमेलित नहीं है: प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. बी.आर. अंबेडकर थे।** बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, किसी समिति के अध्यक्ष नहीं।
- **युग्म 2 सही सुमेलित नहीं है: सरदार वल्लभभाई पटेल ने प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता की।** इस समिति ने नए संविधान में प्रांतों के शासन से संबंधित प्रावधानों पर कार्य किया।
- **युग्म 3 सही सुमेलित नहीं है:** डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने प्रक्रिया संबंधी नियम समिति की अध्यक्षता की।
- **अतिरिक्त जानकारी: अन्य समितियाँ और उनके अध्यक्ष**
  1. संघ शक्ति समिति - जवाहरलाल नेहरू
  2. संघीय संविधान समिति - जवाहरलाल नेहरू
  3. मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति - सरदार पटेल
  4. राज्य समिति (राज्यों के साथ बातचीत के लिए समिति) - जवाहरलाल नेहरू
  5. संचालन समिति - डॉ. राजेंद्र प्रसाद

44. (a)

- **कथन 1 सही है:** संविधान के भाग IV में निहित अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य "भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा"।
- **कथन 2 सही नहीं है:** व्यक्तिगत कानून जैसे कि निर्वसीयतता (Intestacy) और उत्तराधिकार; वसीयत; संयुक्त परिवार और विभाजन; विवाह और तलाक, संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-III-समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 से संबंधित हैं, और इसलिए, संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को उन पर कानून बनाने का अधिकार है।

45. (b)

- **विकल्प (b) सही उत्तर है: संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन** वसंत **कृष्ण वैद्य** द्वारा किया गया था, जबकि **दोनों संस्करणों के लिए** कलाकृति और सौंदर्यीकरण शांतिनिकेतन से नंदलाल बोस और उनकी टीम द्वारा योगदान दिया गया था।
- **अतिरिक्त जानकारी: संविधान से संबंधित अन्य प्रमुख व्यक्तित्व—**
  - **सर बी.एन. राव** - संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार (कानूनी सलाहकार)।
  - **एच.वी.आर. आयंगर** - संविधान सभा के सचिव।
  - **एस.एन. मुखर्जी** - संविधान सभा में संविधान के मुख्य प्रारूपकार।
  - **व्यौहार राममनोहर सिन्हा** - मूल उद्देशिका (Preamble) को, जिसका सुलेखन प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा ने किया था, चित्रित एवं अलंकृत किया।

46. (a)

- **कथन 1 सही है:** भारत के संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार, भाग IV (राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत) में निहित प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकेंगे, लेकिन **फिर भी इसमें निर्धारित सिद्धांत देश के शासन में मौलिक हैं और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्त्तव्य होगा।**
- **कथन 2 सही नहीं है:** राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (DPSP) **प्रकृति में गैर-न्यायसंगत हैं,** जिसका अर्थ है कि वे न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं हैं। इसलिए, न्यायपालिका किसी कानून को केवल इसलिए अमान्य घोषित नहीं कर सकती, क्योंकि वह DPSP का उल्लंघन करता है।

47. (b)

विकल्प (b) सही है: एक कठोर संविधान को अपने संशोधन के लिए सामान्य कानून से अलग प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, जबकि एक लचीले संविधान को सामान्य विधायी प्रक्रिया के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है।

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

अतिरिक्त जानकारी:

- **कठोर संविधान:** संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है (उदाहरणार्थ, अमेरिकी संविधान)।
- **लचीला संविधान:** सामान्य कानूनों की तरह इसमें संशोधन किया जा सकता है (जैसे, यूके संविधान)।
- **भारतीय संविधान:** दोनों का मिश्रण —
  - कुछ प्रावधानों के लिए संसद के **विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।**
  - कुछ के लिए **विशेष बहुमत के साथ-साथ आधे राज्यों के अनुमोदन की भी आवश्यकता होती है।**
  - अन्य को साधारण कानूनों की तरह **साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है** (ये अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं)।

48. (b)

- **44वाँ संशोधन अधिनियम (1978):** इसमें एक नीति निदेशक सिद्धांत जोड़ा गया, जिसके तहत राज्य को आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को न्यूनतम करने की आवश्यकता थी (अनुच्छेद 38)। अतः, **A-3 सही है।**
- **86वाँ संशोधन अधिनियम (2002):** अनुच्छेद 45 में संशोधन करके राज्य को सभी बच्चों के लिए छह वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने हेतु बाध्य किया गया। अतः, **B-2 सही है।**
- **97वाँ संशोधन अधिनियम (2011):** अनुच्छेद 43B जोड़ा गया, जिससे राज्य को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्यप्रणाली, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया। अतः, **C-1 सही है।**

अतिरिक्त जानकारी:

- **42वें संशोधन अधिनियम (1976) ने** पहले कानूनी सहायता, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, पर्यावरण संरक्षण और बाल विकास के प्रावधानों के साथ निदेशक सिद्धांतों की सूची का विस्तार किया।
- 44 **वां संशोधन** संवैधानिक संतुलन बहाल करने और सामाजिक-आर्थिक निर्देशों को मज़बूत करने के लिए आपातकाल के बाद के सुधारों का हिस्सा था।
- 86 वें **संशोधन ने** प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार [अनुच्छेद 21(A)] बना दिया तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल को नीति निदेशक सिद्धांतों में स्थानांतरित कर दिया।
- 97**वें संशोधन को** आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन के अभाव में वर्ष 2021 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया था, लेकिन DPSP में सहकारी समितियों से संबंधित हिस्सा वैध बना हुआ है।

49. (d)

- **विकल्प (d) सही उत्तर है:** संविधान के भाग IV में **राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों (DPSP)** में **महात्मा गाँधी के आदर्शों से प्रेरित कुछ प्रावधान शामिल हैं, जिन्हें प्रायः गाँधीवादी सिद्धांत** कहा जाता है। ये आत्मनिर्भरता, ग्रामीण विकास और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं, और इनमें शामिल हैं:
  - ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना (अनुच्छेद 43)
  - स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेय और मादक द्रव्यों का निषेध (अनुच्छेद 47)
  - गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध (अनुच्छेद 48)
- हालाँकि, **नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता** (अनुच्छेद 44) सुनिश्चित करना **उदारवादी-बौद्धिक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है,** न कि गाँधीवादी सिद्धांतों के अंतर्गत।

अतिरिक्त जानकारी:

- गाँधीवादी DPSP का लक्ष्य आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और नैतिक उत्थान के दृष्टिकोण को साकार करना है।
- अन्य गाँधीवादी प्रावधानों में पंचायती राज (अनुच्छेद 40) को बढ़ावा देना और ग्राम स्तर पर खादी एवं कुटीर उद्योगों का आयोजन करना शामिल है।

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

50. (c)

- **कथन 1 सही है:** मॉर्ले-मिंटो सुधार के नाम से प्रसिद्ध भारतीय परिषद् अधिनियम, 1909 ने **मुसलमानों के लिए पृथक् निर्वाचक मंडल का सिद्धांत प्रस्तुत किया।** इस प्रणाली के तहत, मुस्लिम मतदाता एक अलग मतदाता सूची के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकते थे। इसने भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की।
- **कथन 2 सही है:** इस अधिनियम ने पहली बार भारतीयों को वायसराय की कार्यकारी परिषद् में शामिल होने की अनुमति दी। सत्येंद्र प्रसन्नो सिन्हा (बाद में लॉर्ड सिन्हा) वर्ष 1909 में वायसराय की कार्यकारी परिषद् के सदस्य नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने, और उन्हें विधि विभाग का कार्यभार सौंपा गया।
- **कथन 3 सही नहीं है:** भारतीय परिषद् अधिनियम, 1909 में लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान नहीं था। लोक सेवा आयोग का विचार बाद में भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत प्रस्तुत किया गया था।
- **कथन 4 सही है:** इस अधिनियम ने केंद्रीय विधान परिषद् और प्रांतीय विधान परिषदों, दोनों के आकार में वृद्धि की। केंद्रीय स्तर पर, सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई, और प्रांतीय स्तर पर भी संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की गई।

51. (c)

- **कथन 1 सही है:** राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत (भाग IV, अनुच्छेद 36-51) भारत सरकार अधिनियम, 1935 में प्रदान किए गए **"अनुदेश- प्रपत्र (Instrument of Instructions)" से प्रेरित हैं।** इन प्रपत्रों ने गवर्नर-जनरल और गवर्नर को अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में मार्गदर्शन किया, ठीक उसी तरह जैसे DPSP नीति-निर्माण में राज्य का मार्गदर्शन करते हैं।
- **कथन 2 सही है: प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने DPSP को** भारतीय संविधान की "नई विशेषताएँ" कहा, क्योंकि उनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना था।
- **अतिरिक्त जानकारी:**
  - भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्त्व का प्रावधान *आयरलैंड के संविधान, 1937* से प्रेरित है, जिसने इसे *स्पेन के संविधान* से ग्रहण किया था।

52. (c)

- **कथन 1 सही है: 30 दिसंबर, 2024** को **यूएनएफसीसीसी** को सौंपी गई भारत की **चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट (BUR-4) में वर्ष 2019** की तुलना में वर्ष **2020** में **कुल ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन** में **7.93% की कमी** दर्ज की गई।
- **कथन 2 सही है: वर्ष 2020** में, **ऊर्जा क्षेत्र** भारत के जीएचजी उत्सर्जन में **सबसे बड़ा योगदानकर्ता** था, जो कुल उत्सर्जन का **75.66% था।**
  - **अन्य क्षेत्र:** कृषि, औद्योगिक प्रक्रियाएँ, अपशिष्ट और **LULUCF** (भूमि उपयोग, भूमि उपयोग परिवर्तन और वानिकी)।
  - **LULUCF** गतिविधियों ने **लगभग 522 मिलियन टन CO_2 को अलग करने में मदद की, जिससे** सकल उत्सर्जन का लगभग **22% कम हो गया।**

अतिरिक्त जानकारी:

- **LULUCF को छोड़कर: वर्ष** 2020 में भारत का उत्सर्जन **2,959 मिलियन टन CO_2e था।**
- **LULUCF सहित: शुद्ध उत्सर्जन 2,437 मिलियन टन CO_2e** रहा।
- **NDC लक्ष्य: वर्ष 2070** तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन (**COP26, 2021** में घोषित)।
- द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट (BURs) प्रत्येक दो वर्ष में प्रस्तुत की जाती हैं, जिनमें GHG सूची का अद्यतन, शमन उपायों की रिपोर्टिंग तथा प्राप्त सहयोग का विवरण शामिल होता है।

53. (c)

संदर्भ: मराठी और बंगाली सहित पाँच नई भाषाओं को शास्त्रीय (श्रेण्य) भाषा का दर्जा देने का केंद्रीय मंत्रिमंडल का निर्णय उस महत्त्वपूर्ण प्रावधान को **हटाए जाने के बाद आया है, जिसके तहत यह अनिवार्य किया गया था कि किसी भाषा की मूल साहित्यिक परंपरा होनी चाहिए।**

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

- **पहले के मानदण्ड (2005): शास्त्रीय भाषा** के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए, आवश्यकताओं में से एक यह था कि **"साहित्यिक परंपरा मूल होनी चाहिए और किसी अन्य भाषायी समुदाय से उधार नहीं ली गई होनी चाहिए"**।
- **हालिया परिवर्तन (2024):** संशोधित मानदंडों में **"साहित्यिक परंपरा की मौलिकता" की** आवश्यकता को **हटा दिया गया, जिससे अधिक भाषाओं को अर्हता प्राप्त करने में मदद मिली।**
- **प्रभाव:** संशोधित मानदंडों के तहत, **मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत को** शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया (राजपत्र अधिसूचना: **4 अक्टूबर, 2024**)।

अतिरिक्त जानकारी:

- **शास्त्रीय भाषा के लिए वर्तमान मानदण्ड:**
  - प्रारंभिक ग्रंथों/लिखित इतिहास की उच्च प्राचीनता, जो 1500–2000 वर्षों की अवधि से अधिक हो।
  - प्राचीन साहित्य/ग्रंथों का ऐसा संकलन, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी वक्ताओं द्वारा विरासत के रूप में माना गया हो।
  - ज्ञान ग्रंथ, विशेष रूप से गद्य ग्रंथ, काव्य ग्रंथ, पुरालेखीय और अभिलेखीय साक्ष्य।
  - शास्त्रीय भाषाएँ और साहित्य अपने वर्तमान स्वरूप से अलग हो सकते हैं या अपनी शाखाओं के बाद के स्वरूपों से अलग हो सकते हैं।
- **संशोधन से पहले:** 6 शास्त्रीय भाषाएँ - **तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओड़िया**।
- **संशोधन के बाद:** 11 शास्त्रीय भाषाएँ - उपर्युक्त छह **+ मराठी, बंगाली, असमिया, पाली, प्राकृत**।

54. (c)

- **विकल्प (c) सही उत्तर है: प्रधानमंत्री यशस्वी योजना (प्रधानमंत्री यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फ़ॉर वाइब्रेंट इंडिया) का उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (EBC) तथा विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू जनजातियों (DNT) के छात्रों को सशक्त बनाना है।**
- **प्राथमिक घटकों में शामिल हैं:**
  - **प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति:** कक्षा 9-12 के छात्रों के लिए प्रतिवर्ष ₹1.25 लाख
  - **पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति:** उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता (₹12.75 करोड़ वितरित)
  - **उच्च श्रेणी की विद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षा**
  - ओबीसी छात्रों के लिए **छात्रावास निर्माण**

अतिरिक्त जानकारी:

- **शुभारंभ का उद्देश्य:** वंचित समूहों को **शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण** प्रदान करना।
- **विशेष मान्यता: वर्ष** 2025 में, **21 राज्यों के 400 छात्र लाभार्थियों को** गणतंत्र दिवस परेड में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।
- **नोडल मंत्रालय:** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय।

55. (d)

- **कथन 1 सही नहीं है: भारत में, संविधान प्रधानमंत्री को संसद के किसी भी सदन का सदस्य होने की अनुमति देता है।** उदाहरण के लिए, **इंदिरा गाँधी, देवेगौड़ा और मनमोहन सिंह ने राज्य सभा के सदस्य** रहते हुए प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। इसके विपरीत, **ब्रिटेन में, प्रधानमंत्री को निचले सदन** (हाउस ऑफ़ कॉमन्स) का सदस्य होना आवश्यक है।
- **कथन 2 सही है: ब्रिटेन में, राजा द्वारा जारी प्रत्येक सार्वजनिक आदेश पर एक मंत्री का प्रतिहस्ताक्षर होना आवश्यक है, जो उसके लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी होता है।** यदि आदेश किसी कानून का उल्लंघन करता है, तो मंत्री को न्यायालय में उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। वहाँ यह सिद्धांत लागू होता है कि, "राजा कोई गलती नहीं कर सकता"। भारत में, मंत्रियों को इस प्रकार कानूनी रूप से उत्तरदायी बनाने का **कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, और न ही यह अनिवार्य है कि राष्ट्रपति के सार्वजनिक आदेश पर किसी मंत्री का प्रतिहस्ताक्षर हो।**

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

- **कथन 3 सही नहीं है: ब्रिटेन में, अध्यक्ष (स्पीकर) से** पूरी तरह से निष्पक्ष रहने की अपेक्षा की जाती है। राजनीतिक तटस्थता बनाए रखने के लिए वह **चुनाव के बाद दल की सदस्यता से इस्तीफ़ा दे देता है।** हालाँकि, **भारत में इस परंपरा का पूरी तरह से पालन नहीं किया जाता है, और अध्यक्ष सामान्य तौर पर पदभार ग्रहण करने के बाद भी दल की सदस्यता बरकरार रखता है।**

56. (d)

- **वर्ष 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम के बारे में:** इसने राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों की सूची में चार नए नीति निदेशक सिद्धांत **जोड़े। ये राज्य को निर्देशित करते हैं:**
  - बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर सुनिश्चित करना (अनुच्छेद 39)।
  - **समान न्याय को बढ़ावा देना** और गरीबों को **मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना [अनुच्छेद 39(A)]। इस प्रकार, कथन 3 सही है।**
  - **उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए** कदम उठाना [अनुच्छेद 43 (A)]। **इस प्रकार, कथन 2 सही है।**
  - पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना तथा वनों एवं वन्यजीवन की सुरक्षा करना [अनुच्छेद 48 (A)]।
- **कथन 1 सही नहीं है: आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने** का निर्देश **(अनुच्छेद 38) बाद में वर्ष 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम** द्वारा जोड़ा गया था।
- **अतिरिक्त जानकारी:** DPSP में अन्य संशोधनों में शामिल हैं:
  - **86वाँ संशोधन अधिनियम, 2002 - अनुच्छेद 45** की विषय-वस्तु में संशोधन किया गया। इसके तहत राज्य को सभी बच्चों के लिए छह वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है।
  - **97वाँ संशोधन अधिनियम, 2011** - सहकारी समितियों से संबंधित एक नया DPSP जोड़ा गया। इसके अंतर्गत राज्य को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्यप्रणाली, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है **[अनुच्छेद 43(B)]।**

57. (c)

- **कथन 1 सही है:** यह अधिनियम लोक सेवकों (जिसमें मंत्री भी शामिल हैं) द्वारा भ्रष्टाचार या शक्ति के दुरुपयोग के मामलों का खुलासा करने की अनुमति देता है, जिसे केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) जैसे सक्षम प्राधिकरण के समक्ष किया जा सकता है।
- **कथन 2 सही नहीं है:** अधिनियम **अनाम शिकायतों की जाँच का आदेश नहीं देता**, भले ही साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हों। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि शिकायतकर्ता या लोक सेवक की **पहचान इंगित नहीं की जाती है या गलत पाई जाती है, तो कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।**
- **कथन 3 सही है:** अधिनियम **झूठी या निकृष्ट शिकायतों के लिए दो वर्ष** तक की कैद और **30,000 रुपये** तक के जुर्माने का प्रावधान करता है।
- **कथन 4 सही है:** विशेष **सुरक्षा दल (एसपीजी) को** इस अधिनियम के प्रावधानों से छूट प्राप्त है।
- **अतिरिक्त जानकारी:** व्हिसल **ब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014 व्हिसल ब्लोअर की पहचान की सुरक्षा** और यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है कि उन्हें **प्रताड़ित न किया जाए। खुलासे सद्भावनापूर्वक, लिखित रूप में** या **ईमेल के माध्यम से, सहायक दस्तावेज़ों** या ठोस साक्ष्यों के साथ किए जाने चाहिए। **सरकार** ऐसी शिकायतें प्राप्त करने के लिए **CVC** के अलावा अन्य प्राधिकारियों को नामित कर सकती है।

58. (d)

- **विकल्प (d) सही उत्तर है: 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा अनुच्छेद 51(A) को** सम्मिलित करके संविधान में मौलिक कर्त्तव्य जोड़े गए। मूल रूप से, **10 मौलिक कर्त्तव्य** थे।
- **इसकी सूची में केवल एक बार संशोधन हुआ है,** जो **86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002** द्वारा किया गया।
- इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51(A) में खण्ड **(k) जोड़ा गया:**

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

"यह प्रत्येक माता-पिता या अभिभावक का कर्त्तव्य होगा कि वह अपने बच्चे या प्रतिपाल्य को छह से चौदह वर्ष की आयु के बीच शिक्षा के अवसर प्रदान करे।"

- **यह संशोधन अनुच्छेद 21(A) के अनुरूप था, जिसने इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया।**

59. (b)

- **1 सही है:** संसदीय शासन प्रणाली में, **सामूहिक उत्तरदायित्व संसद के प्रति मंत्रियों की जवाबदेही** एक **मूलभूत सिद्धांत है। अनुच्छेद 75** के तहत, **मंत्री सामूहिक रूप से संसद और विशेष रूप से लोक सभा के प्रति जवाबदेह होते हैं।** इसका अर्थ है कि लोक सभा अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली पूरी मंत्रिपरिषद् को बर्खास्त कर सकती है।
- **2 सही नहीं है: द्विसदनीयता संसदीय प्रणाली की अंतर्निहित आवश्यकता नहीं है।** कई संसदीय लोकतंत्र एकल विधायी सदन के साथ सफलतापूर्वक संचालित होते हैं। संसदीय प्रणाली की पहचान यह है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, न कि यह कि विधायिका में एक या दो सदन हैं।
- **3 सही है: निचले सदन का विघटन संसदीय प्रणाली की** एक अंतर्निहित विशेषता है। **कार्यपालिका को विघटन की सिफ़ारिश करने का अधिकार है,** जो इस प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है।
- **अतिरिक्त जानकारी:** संसदीय प्रणाली (भारत में) की अन्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:
  - नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिका की उपस्थिति।
  - बहुमत दल का शासन।
  - मंत्री, विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं।
  - प्रधानमंत्री का नेतृत्व।

60. (c)

- **विकल्प (c) सही उत्तर है: वर्ष 1833 का चार्टर अधिनियम** ब्रिटिश भारत के संवैधानिक विकास में एक महत्त्वपूर्ण कदम था। यह मुख्य रूप से **विधायी शक्तियों के केंद्रीकरण से संबंधित था।** इसने **बंबई और मद्रास प्रेसीडेंसी की विधायी शक्तियों को समाप्त कर दिया और कानून बनाने का सारा अधिकार भारत के गवर्नर-जनरल को सौंप दिया।** इसने बंगाल के गवर्नर-जनरल को भारत के गवर्नर-जनरल में बदल दिया, जिसका अधिकार पूरे ब्रिटिश भारत पर था।
- वर्ष 1833 के चार्टर ऐक्ट ने **कानूनों के संहिताकरण की भी नींव रखी।** इसने **लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया,** जिसने भारतीय कानूनों का व्यवस्थित संहिताकरण शुरू किया (जिसके परिणामस्वरूप भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता आदि का निर्माण हुआ)।

61. (b)

- **विकल्प B सही उत्तर है:** संविधान का अनुच्छेद 326 यह प्रावधान करता है कि लोक सभा और प्रत्येक राज्य की विधान सभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे।
- प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से कम न हो, उसे जाति, नस्ल, धर्म, लिंग, साक्षरता, आर्थिक स्थिति आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार है।
- **वर्ष 1988 के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 1989 में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।**

62. (a)

संविधान के तहत कुछ मौलिक अधिकार न केवल 'राज्य' (जैसा कि अनुच्छेद 12 में परिभाषित किया गया है) के विरुद्ध लागू किए जा सकते हैं, बल्कि **निजी व्यक्तियों या संस्थाओं के विरुद्ध भी लागू किए जा सकते हैं।**

1 सही है: मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध (अनुच्छेद 23): राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों पर लागू होता है। यह मानव दुर्व्यापार, बेगार और इसी तरह के अन्य बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 और बंधुआ मज़दूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 इस अधिकार को लागू करते हैं।

2 सही है: कारखानों में बच्चों के नियोजन का निषेध (अनुच्छेद 24): राज्य और निजी दोनों नियोक्ताओं पर लागू होता है। कारखानों, खदानों और अन्य ख़तरनाक व्यवसायों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध है। बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 (संशोधित 2016) के माध्यम से लागू।

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

3 सही नहीं है: धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28): धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25–28) – यह मुख्य रूप से राज्य के विरुद्ध प्रवर्तनीय है, ताकि धार्मिक आचरण में हस्तक्षेप न हो; हालाँकि कुछ मामलों में कानून निजी कार्यों पर भी लागू हो सकता है।

4 सही है: अस्पृश्यता उन्मूलन (अनुच्छेद 17) : यह राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों पर लागू होता है। यह अस्पृश्यता का निषेध करता है और इसके आचरण को अपराध मानता है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के माध्यम से इसे लागू किया गया है।

63. (a)

- **अलिखित संविधान के बारे में:** यह एक ऐसे **संविधान को संदर्भित करता है, जो किसी एकल औपचारिक दस्तावेज़ में संहिताबद्ध नहीं होता, बल्कि कानूनों, न्यायिक निर्णयों, परिपाटियों और परंपराओं पर आधारित होता है। इन्हें** "अलिखित" संविधान भी कहा जाता है।
- दुनिया के **6 देशों के संविधान अलिखित या असंहिताबद्ध हैं।** इनमें **यूनाइटेड किंगडम, सैन मैरिनो, न्यूज़ीलैंड, कनाडा, स्वीडन और इज़राइल शामिल हैं। अतः, 1 सही है।**
- **2 सही नहीं है: ऑस्ट्रेलिया का** एक **लिखित संविधान है,** जो वर्ष 1901 में लागू हुआ।
- **3 सही नहीं है: जापान का** एक **लिखित संविधान है,** जो वर्ष 1947 में लागू हुआ।

64. (c)

- **विकल्प (c) सही है:** हालाँकि नागरिकता अधिनियम, 1955 पाँच तरीकों से भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान करता है— **जन्म से, वंश द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा, और क्षेत्र के समावेश द्वारा** — किसी भारतीय नागरिक से विवाह करना **अपने आप में** नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका **नहीं** है। किसी भारतीय नागरिक से विवाहित कोई विदेशी व्यक्ति नागरिकता अधिनियम की धारा 5(1)(c) के तहत **केवल पंजीकरण के माध्यम से ही नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है, बशर्ते कि वे आवेदन करने से पहले कम-से-कम 7 वर्षों** तक भारत में सामान्य रूप से निवास कर रहे हों। इस प्रकार, पंजीकरण श्रेणी के अंतर्गत विवाह केवल एक पात्रता का एक आधार है, न कि एक स्वतंत्र विधि।

65. (d)

- **विकल्प (d) सही उत्तर है: डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार)** को **"संविधान का हृदय और आत्मा" कहा था।** ऐसा इसलिए है, क्योंकि **अनुच्छेद 32 व्यक्तियों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है।** इस प्रकार, यह राज्य द्वारा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध गारंटी के रूप में कार्य करता है। यह प्रावधान **सुनिश्चित करता है कि मौलिक अधिकार केवल सैद्धांतिक ही नहीं, बल्कि व्यवहार में भी प्रवर्तनीय हैं।**
- सर्वोच्च **न्यायालय और उच्च न्यायालय** मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए **बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार पृच्छा** रिट जारी कर सकते हैं।

66. (b)

- **कथन 1 सही नहीं है: कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों का कठोर पृथक्करण अध्यक्षीय शासन प्रणाली** की विशेषता है, संसदीय शासन प्रणाली की नहीं। संसदीय शासन प्रणाली में, **शक्तियों का संलयन होता है:** कार्यपालिका (प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद्) विधायिका से ली जाती है और सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है।
- **कथन 2 सही है:** संसदीय शासन प्रणाली **नीति निर्माण में कार्यपालिका और विधायिका के बीच बेहतर समन्वय को सुगम बनाती है।** शक्तियों के संलयन के कारण, मंत्री विधायिका के सदस्य होते हैं और सीधे उसके प्रति जवाबदेह होते हैं। इससे नीति निर्माण और क्रियान्वयन में बेहतर संचार और समन्वय संभव होता है।
- **कथन 3 सही नहीं है: निश्चित कार्यकाल अध्यक्षीय शासन प्रणाली** की एक विशेषता है। संसदीय प्रणाली में, सरकार को किसी भी समय अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है, इसलिए कार्यकाल निश्चित नहीं होता है।
- **अतिरिक्त जानकारी:** भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएँ हैं:
  (a) नाममात्र एवं वास्तविक कार्यपालिका की उपस्थिति,
  (b) बहुमत दल का शासन,
  (c) कार्यपालिका की विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व,

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

(d) मंत्रियों की विधायिका में सदस्यता,

(e) प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व,

(f) निचले सदन (लोक सभा या विधान सभा) का विघटन।

67. (a)

- **कथन 1 सही है: राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR)** नागरिकता अधिनियम, 1955 और नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम, 2003 के प्रावधानों के तहत तैयार किया जाता है।
- **कथन 2 सही नहीं है: NPR में भारत के सभी "सामान्य निवासियों"** का विवरण शामिल है, न कि केवल नागरिकों का। एक "सामान्य निवासी" वह व्यक्ति होता है, जो पिछले 6 महीनों से किसी स्थानीय क्षेत्र में निवास कर रहा है या अगले 6 महीनों या उससे अधिक समय तक वहाँ निवास करने का इरादा रखता है, चाहे उसकी राष्ट्रीयता कुछ भी हो।
- **कथन 3 सही नहीं है:** NPR में पंजीकरण प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए **अनिवार्य है, स्वैच्छिक नहीं।**
- **अतिरिक्त जानकारी:**
- NPR गृह मंत्रालय के अधीन **भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा अनुरक्षित एक डेटाबेस है।**
- इसे पहली बार वर्ष 2010 में तैयार किया गया था और वर्ष 2015 में अद्यतन किया गया था, तथा सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार के लिए इसे आधार और अन्य डेटाबेस से जोड़ा गया था।

68. (d)

- **कथन-I सही है:** अनुच्छेद 33 संसद को सशस्त्र बलों, अर्ध-सैन्य बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर एजेंसियों तथा उनसे संबंधित बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है।
- **कथन-II सही नहीं है:** अनुच्छेद 33 के अंतर्गत केवल संसद को ही यह अधिकार प्राप्त है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य विधानसभाओं को सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है। संसद द्वारा बनाए गए ऐसे किसी भी कानून को किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
- **कथन-III सही नहीं है:** अनुच्छेद 33 का प्रयोग इस बात पर निर्भर नहीं करता कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू है या नहीं। यह प्रावधान संसद को एक सामान्य अधिकार प्रदान करता है ताकि सशस्त्र एवं संबंधित बलों में अनुशासन बनाए रखा जा सके।
- **अतिरिक्त जानकारी:** "सशस्त्र बलों के सदस्य" शब्द में वे गैर-युद्धकर्मी भी सम्मिलित हैं, जैसे—नाई, बढ़ई, मैकेनिक, रसोइए, चौकीदार, जूता बनाने वाले एवं दर्जी, जो सशस्त्र बलों में सेवा देते हैं।

69. (c)

- **कथन 1 सही है: केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) मामले** में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संविधान का संघीय स्वरूप **मूल संरचना** सिद्धांत का हिस्सा है। इसका अर्थ यह है कि संसद अधिकांश प्रावधानों में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वह राजव्यवस्था के आवश्यक संघीय ढाँचे में बदलाव नहीं कर सकती।
- **कथन 2 सही है:** संविधान के पाठ में "संघवाद" शब्द का **स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इसके बजाय, भारत की संघीय प्रकृति का अनुमान संघ और राज्य सूचियों (सातवीं अनुसूची)**, विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के वितरण, और केंद्र-राज्य विवादों को सुलझाने में न्यायपालिका की भूमिका जैसे प्रावधानों से लगाया जाता है। संविधान के **अनुच्छेद 1 में भारत को** "राज्यों का संघ" बताया गया है, जो एक मज़बूत एकात्मक प्रवृत्ति वाली संघीय व्यवस्था को दर्शाता है।

अतिरिक्त जानकारी:

- भारत के संघीय ढाँचे को प्रायः "अर्ध-संघीय" कहा जाता है, क्योंकि यह संघीय विशेषताओं (शक्तियों का विभाजन, द्विसदनीयता, स्वतंत्र न्यायपालिका) को एकात्मक विशेषताओं (मज़बूत केंद्र, आपातकालीन शक्तियाँ) के साथ जोड़ता है।
- मूल संरचना सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण, धर्मनिरपेक्षता, न्यायिक समीक्षा और संविधान की सर्वोच्चता जैसे अन्य सिद्धांतों की भी रक्षा करता है।

70. (c)

- **विकल्प (c) सही उत्तर है:** मौलिक **कर्त्तव्यों को 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा** संविधान में **जोड़ा गया** था। इन कर्त्तव्यों को **अनुच्छेद 51(A)** के तहत संविधान के **भाग IV(A) के रूप में शामिल किया गया था।**

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

- वे आंशिक रूप से **सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित थे** और स्वर्ण **सिंह समिति की सिफ़ारिशों पर आधारित थे**।
- प्रारंभ में मौलिक कर्त्तव्यों की संख्या 10 थी। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा 11वाँ कर्त्तव्य जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करना सम्मिलित है।

71. (a)

- **कथन 1 सही है:** ब्याज इक्विलाइज़ेशन/समकारी योजना (Interest Equalisation Scheme) का उद्देश्य पात्र निर्यातकों को रुपये में मूल्यवर्गित शिपमेंट-पूर्व और शिपमेंट-पश्चात् ऋण पर ब्याज दर सब्सिडी प्रदान करके निर्यात ऋण को सस्ता बनाना है।
- **कथन 2 सही है:** यह योजना भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है, जो परिचालन दिशा-निर्देश जारी करता है और बैंकों को प्रतिपूर्ति (Reimburse) करता है।
- **कथन 3 सही नहीं है:** यह योजना विशेष रूप से पात्र लाभार्थियों में से MSME विनिर्माण क्षेत्र को कवर करती है।

72. (b)

- **कथन 1 सही है:** प्रतिभूति लेन-देन कर (STT) भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय पर लगाया जाता है। यह कर, लेन-देन निष्पादित करते समय लगाया जाता है और स्टॉक, इक्विटी वायदा व विकल्प सहित सभी इक्विटी और व्युत्पाद लेन-देन पर लागू होता है। कर चोरी रोकने, व्यापार में पारदर्शिता बढ़ाने और निवेशकों के लिए कराधान प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए STT की शुरुआत की गई थी।
- **कथन 2 सही नहीं है:** STT की दरें केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर बजट के माध्यम से निर्धारित की जाती हैं।
- **कथन 3 सही नहीं है:** STT एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। STT की लागत निवेशकों/व्यापारियों को उनकी लेन-देन लागत के हिस्से के रूप में स्थानांतरित कर दी जाती है; स्टॉक एक्सचेंज केवल इसे एकत्र करते हैं और सरकार को भेजते हैं।

73. (a)

- **संदर्भ:** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जनवरी, 2015 को उजाला योजना शुरू की थी। हाल ही में, ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व पहल संबंधी इस योजना की 10वीं वर्षगाँठ मनाई गई।
- **कथन 1 सही है:** यह ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (EESL) और विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली DISCOMs का संयुक्त प्रयास है।
- **कथन 2 सही नहीं है:** पिछले एक दशक में, 'उजाला' विश्व के सबसे बड़े शून्य-सब्सिडी घरेलू प्रकाश कार्यक्रम के रूप में विकसित हुआ है।

अतिरिक्त जानकारी:

- इस योजना को शुरू में, 'घरेलू कुशल प्रकाश कार्यक्रम' (DELP) के रूप में पेश किया गया था और बाद में, इसका नाम बदलकर उजाला कर दिया गया।
- इसका उद्देश्य भारतीय घरों को किफायती ऊर्जा-कुशल LED बल्ब, ट्यूबलाइट और पंखे उपलब्ध कराना था।
- इस पहल ने उच्च विद्युतीकरण लागत और उच्च कार्बन उत्सर्जन का समाधान करने का प्रयास किया।
- एक 7W का LED बल्ब, 14W CFL और 60W तापदीप्त (Incandescent) लैंप के समान प्रकाश प्रदान करता है, जिससे 90% तक ऊर्जा की बचत होती है।

74. (b)

- उपर्युक्त राज्यों के गठन का सही कालानुक्रम 2-1-3 है।
- नागालैंड 1 दिसंबर, 1963 को भारत का 16वाँ राज्य बना।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 के तहत, मणिपुर 21 जनवरी, 1972 को एक पूर्ण राज्य बना।
- अरुणाचल प्रदेश 20 फ़रवरी, 1987 को भारत का 24वाँ राज्य बना।

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

75. (c)

- **विकल्प (c) सही उत्तर है:** भारत सरकार अधिनियम, 1935, ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए पारित सबसे लंबा कानून था और इसने कई महत्त्वपूर्ण संवैधानिक परिवर्तन किए। इसकी एक प्रमुख विशेषता 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना थी, जिसका उद्देश्य प्रांतों और केंद्र के बीच विवादों को सुलझाना और कानूनी प्रावधानों की व्याख्या करना था।
- **अतिरिक्त जानकारी:** वर्ष 1935 के अधिनियम के अन्य महत्त्वपूर्ण प्रावधानों में शामिल थे:
  - प्रांतीय स्वायत्तता (प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, जो कि भारत सरकार अधिनियम, 1919 द्वारा लागू किया गया था।)
  - केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई, किंतु कभी लागू नहीं हुआ।
  - अखिल भारतीय संघ का प्रावधान (रियासतों की भागीदारी की कमी के कारण लागू नहीं)
  - संघीय, प्रांतीय और समवर्ती सूचियों में शक्तियों का विभाजन।
  - पृथक् निर्वाचक मंडलों का विस्तार।

76. (a)

- **विकल्प (a) सही उत्तर है:** महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त (RGI) का पद भारत सरकार के गृह मंत्रालय (MHA) के अधीन कार्य करता है। भारत में जनगणना प्रति 10 वर्ष में होती है; पहली समकालिक जनगणना ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1881 में हुई थी।

77. (c)

- **कथन 1 सही है:** अनुच्छेद 17 "अस्पृश्यता" का अंत करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास पर रोक लगाता है। यह प्रावधान इसे 'आत्यंतिक' (Absolute) और 'बिना शर्त' (Unconditional) स्वरूप प्रदान करता है।
- **कथन 2 सही नहीं है:** संविधान 'अस्पृश्यता' शब्द को परिभाषित नहीं करता है। न्यायपालिका ने अपने विभिन्न निर्णयों में इसकी व्याख्या जाति-आधारित भेदभाव से संबंधित प्रथाओं के रूप में की है। अस्पृश्यता का संबंध कुछ जातियों में जन्म लेने के कारण, कुछ वर्गों के व्यक्तियों पर थोपी जाने वाली सामाजिक अक्षमताओं से है।
- **कथन 3 सही है:** संविधान के अनुच्छेद 17 और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अनुसार, अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी अक्षमता को लागू करना, चाहे वह किसी निजी व्यक्ति द्वारा हो या लोक प्राधिकारी द्वारा, विधि के अधीन दण्डनीय अपराध है।

78. (d)

- विकल्प (d) सही उत्तर है।
- **संविधान सभा की महिला सदस्यों के बारे में:** 15 प्रतिष्ठित महिलाओं के योगदान ने भारत के संवैधानिक परिदृश्य को आकार दिया। उनके कुछ योगदान निम्नलिखित हैं:
  - **श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन-** संवैधानिक प्रावधानों में लैंगिक समानता की मुखर पैरोकार, महिलाओं के अधिकारों को उचित मान्यता प्रदान करना सुनिश्चित किया।
  - **श्रीमती एनी मस्कारेन-** संघवाद और राज्य एकीकरण पर चर्चाओं में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत की विविधता में एकता को सुदृढ़ किया।
  - **बेगम कुदसिया ऐजाज़ रसूल-** संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला, धर्मनिरपेक्षता की प्रबल समर्थक रहीं और एक समावेशी राष्ट्रीय पहचान की वकालत की।
  - **श्रीमती दक्षायनी वेलायुधन-** संविधान सभा में पहली दलित महिला, उन्होंने निर्भीकता से छुआछूत का विरोध किया और वंचित समुदायों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया।
  - **श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख-** उन्होंने सामाजिक कल्याण नीतियों को आकार देने और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत में सामाजिक न्याय के आरंभिक ढाँचे में योगदान दिया।
  - **श्रीमती हंसा जीवराज मेहता-** उन्होंने भारत के मौलिक अधिकारों का प्रारूप तैयार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई और यह सुनिश्चित किया कि लैंगिक न्याय संवैधानिक विमर्श के केंद्र में बना रहे।

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

- **राजकुमारी अमृत कौर-** एक अग्रणी राजनेता, भारत की लोक स्वास्थ्य नीतियों की निर्माता थीं और उन्होंने देश में आधुनिक स्वास्थ्य सेवा की नींव रखी।
- **श्रीमती सरोजिनी नायडू-** उन्हें "भारत कोकिला" कहा जाता है, नागरिक स्वतंत्रता की एक मुखर समर्थक थीं, जिन्होंने भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों पर अमिट छाप छोड़ी।
- **श्रीमती सुचेता कृपलानी-** ये बाद में भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं, संविधान सभा में एक प्रमुख आवाज़ थीं और उन्होंने श्रम अधिकारों व शासन सुधारों की वकालत की।
- **श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित-** एक प्रतिष्ठित राजनयिक थी, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक शासन में भारत की भूमिका का पुरज़ोर समर्थन किया।

- **प्रीतिलता वद्देदार-** एक बंगाली क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थीं, जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, लेकिन वर्ष 1946 में संविधान सभा के गठन से बहुत पहले ही, वर्ष 1932 में उनकी मृत्यु हो गई।

79. (d)

- भूल जाने का अधिकार (RTBF) किसी व्यक्ति के उस अधिकार को संदर्भित करता है, जिसके तहत वह इंटरनेट प्लेटफ़ॉर्म, सर्च इंजन या सार्वजनिक डेटाबेस से अपनी व्यक्तिगत जानकारी हटवा सकता है, विशेषकर जब वह जानकारी पुरानी, अप्रासंगिक या अब आवश्यक न रह गई हो। यह निजता के अधिकार से संबद्ध है, जिसे न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ वाद (2017) में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी थी।

80. (b)

- **संविधान की प्रकृति के बारे में:** एक लचीले संविधान में सामान्य कानून की तरह ही संशोधन किया जा सकता है, बिना किसी विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता के। दूसरी ओर, एक कठोर संविधान वह होता है, जिसमें संशोधन के लिए एक विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, उदाहरण के लिए- अमेरिकी संविधान।
- भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन का अनूठा मिश्रण है। संविधान के कुछ प्रावधानों को संसद में साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, जिससे यह कुछ भागों में लचीला हो जाता है। हालाँकि, कई अन्य विशेषताओं के लिए संशोधन हेतु विशेष बहुमत और आधे राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
- **1 सही है:** अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना एक साधारण विधायी प्रक्रिया के माध्यम से किए जा सकते हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि संविधान लचीला है।
- **2 सही है:** 5वीं अनुसूची के किसी भी प्रावधान में संशोधन साधारण विधायी प्रक्रिया के माध्यम से भी किया जा सकता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि संविधान लचीला है।
- **3 सही नहीं है:** राष्ट्रपति का चुनाव और उसकी कार्यप्रणाली राज्य व्यवस्था के संघीय ढाँचे से संबंधित है। इसे संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति से साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। यह प्रावधान भारतीय संविधान की कठोर प्रकृति को दर्शाता है।

81. (d)

- **विकल्प (d) सही उत्तर है:** अनुच्छेद 21 गारंटी देता है कि "किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा।" इसमें निजता, संचरण की स्वतंत्रता और राज्य की मनमानी कार्रवाइयों से सुरक्षा शामिल है, जैसा कि सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी वाद (2017) के निर्णय में पुष्टि की गई है।
- विधिक ढाँचे के बिना AI-आधारित निगरानी इन अधिकारों के लिए प्रत्यक्ष ख़तरा उत्पन्न करती है, क्योंकि इससे व्यक्तियों की गतिविधियों पर लगातार नज़र रखी जा सकती है, उनकी प्रोफ़ाइल बनाई जा सकती है और व्यक्तिगत डेटा का संभावित दुरुपयोग हो सकता है, और यह सब बिना किसी वैध निगरानी के हो सकता है।

82. (b)

- **कथन 1 सही नहीं है: वर्ष** 1948 में, राज्यों के पुनर्गठन की जाँच के लिए धर आयोग का गठन किया गया था। इसने भाषा के बजाय, प्रशासनिक सुविधा को 'आधार' बनाने की सिफ़ारिश की थी। वर्ष 1949 में, इसी मुद्दे की जाँच के लिए संयुक्त विकास परिषद् (JVP) समिति (जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, पट्टाभि सीतारमैय्या) का गठन किया गया था। JVP समिति ने 'भाषा' को पुनर्गठन का एकमात्र आधार मानने से इनकार कर दिया और कहा कि इससे प्रशासनिक व सांप्रदायिक समस्याएँ पैदा हो सकती हैं। इसके बजाय, इसने भाषायी मानदंडों की तुलना में एकता, सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि को प्राथमिकता दी।

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

- **कथन 2 सही है:** एक अलग तेलुगु भाषी राज्य की तीव्र माँग के कारण वर्ष 1952 में 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई। इसके परिणामस्वरूप, 1953 में आंध्र राज्य (मद्रास प्रेसीडेंसी से अलग करके) का निर्माण हुआ, जो स्वतंत्र भारत में भाषायी आधार पर गठित हुआ पहला राज्य था।

अतिरिक्त जानकारी:

- राज्य पुनर्गठन आयोग (SRC) का गठन (फ़ज़ल अली, के.एम. पणिक्कर, एच.एन. कुंजरू) वर्ष 1953 में हुआ था और इसने वर्ष 1955 में अपनी रिपोर्ट दी थी। इसने राज्यों के पुनर्गठन हेतु 'आधार' के रूप में 'भाषा' को व्यापक रूप से स्वीकार किया, लेकिन इसने 'एक भाषा-एक राज्य' के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया।
- राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत 14 राज्यों और 6 संघ राज्यक्षेत्रों का निर्माण हुआ।

83. (b)

- **विकल्प (b) सही उत्तर है:** संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36 से 51) में निहित राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांत (DPSP), सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के आदर्शों को प्राप्त करने के उद्देश्य से कानून और नीतियाँ बनाने हेतु राज्य के लिए दिशा-निर्देश हैं।
- DPSP के तहत सामाजिक लोकतंत्र में सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को कम करके सभी नागरिकों के लिए समानता, न्याय और सम्मान सुनिश्चित करना शामिल है।
- आर्थिक लोकतंत्र का उद्देश्य संपत्ति का समान वितरण, शोषण की रोकथाम और समाज के सभी वर्गों के लिए पर्याप्त आजीविका का प्रावधान करना है।
- **अतिरिक्त जानकारी:** DPSP आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित हैं। ये गैर-न्यायसंगत हैं, अर्थात् इन्हें न्यायालय के माध्यम से प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है। हालाँकि, ये देश के शासन में मौलिक (अनुच्छेद 37) हैं।

84. (d)

- **युग्म 1 सही सुमेलित है:** डिजिलॉकर, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की एक प्रमुख पहल है। डिजिलॉकर का उद्देश्य नागरिकों के डिजिटल दस्तावेज़ वॉलेट में प्रामाणिक डिजिटल दस्तावेज़ों तक पहुँच प्रदान करके नागरिकों का 'डिजिटल सशक्तीकरण' करना है। डिजिलॉकर दस्तावेज़ों और प्रमाण-पत्रों के भंडारण, साझाकरण और सत्यापन के लिए एक सुरक्षित क्लाउड-आधारित मंच है।
- **युग्म 2 सही सुमेलित है:** EntityLocker एक प्रमुख पहल है, जिसे डिजिटल दस्तावेज़ों और प्रमाण-पत्रों के भंडारण, साझाकरण और सत्यापन के लिए एक सुरक्षित, क्लाउड-आधारित मंच प्रदान करके संगठनों को सशक्त बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। डिजिटल रूपांतरण के लक्ष्यों के अनुरूप, EntityLocker एक 'डिजिटल सशक्तीकरण' समाधान प्रदान करता है, जो संगठनों को उनके डिजिटल दस्तावेज़ वॉलेट के माध्यम से प्रामाणिक डिजिटल दस्तावेज़ों तक पहुँच प्रदान करता है। यह मंच व्यवसायों और संस्थानों के लिए सुरक्षित, कुशल और सुव्यवस्थित दस्तावेज़ प्रबंधन सुनिश्चित करता है।
- **युग्म 3 सही सुमेलित है:** UMANG (नए युग के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल ऐप्लिकेशन/Unified Mobile Application for New-age Governance – UMANG) एक बहु-चैनल मंच है; जो केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों की सेवाओं के साथ-साथ उपयोगिता बिल भुगतान, आधार सेवाओं, EPFO, पासपोर्ट सेवा आदि को एक ही ऐप में एकीकृत करता है। UMANG में कई सरकारी निकायों और संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली अनेक सेवाएँ हैं।

85. (b)

- **विकल्प (b) सही उत्तर है:** 'परिवेश पोर्टल' (Pro-Active and Responsive facilitation by Interactive, Virtuous and Environmental Single-Window Hub – PARIVESH) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) द्वारा विकसित एक एकीकृत ऑनलाइन मंच है। इसका उद्देश्य विभिन्न पर्यावरणीय स्वीकृतियों के लिए एकल-विंडो क्लीयरेंस प्रदान करना है, जिनमें शामिल हैं: पर्यावरणीय मंज़ूरी (EC), वन मंज़ूरी (FC), वन्यजीव मंज़ूरी, तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) मंज़ूरी। यह परियोजना प्रस्तावकों के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करता है और पारदर्शिता, जवाबदेही व तीव्र निर्णयन सुनिश्चित करता है।

अतिरिक्त जानकारी:

- अगस्त 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया।

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

- यह सभी हितधारकों - परियोजना प्रस्तावकों, नागरिकों और सरकारी एजेंसियों - को एक एकीकृत डैशबोर्ड के माध्यम से जोड़ता है।
- यह अनुप्रयोगों की वास्तविक समय निगरानी और अनुपालन रिपोर्टिंग को सक्षम बनाता है।
- यह पर्यावरणीय मानदंडों की सुरक्षा करते हुए ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयास का एक हिस्सा है।

86. (c)

- **कथन 1 सही है:** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28(1) के अनुसार, राज्य निधि से पूर्णतः संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। हालाँकि, यह प्रतिबंध किसी ऐसे प्रतिष्ठान या ट्रस्ट के तहत स्थापित राज्य-संचालित संस्थानों पर लागू नहीं होता है, जहाँ विशेष रूप से धार्मिक शिक्षा प्रदान करना आवश्यक हो।
- **कथन 2 सही है:** अनुच्छेद 28(3) के अंतर्गत, राज्य द्वारा मान्यता या सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना की अनुमति है, लेकिन ऐसे संस्थानों में पढ़ने वाले किसी भी व्यक्ति को उसकी सहमति (या नाबालिगों के मामले में अभिभावक की सहमति) के बिना इसमें भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।

87. (a)

- **भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के बारे में:** यह ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के मामलों के संबंध में पारित किया गया अंतिम कानून था। इसने अंततः भारत से ब्रिटिश वापसी की नींव रखी।
- **कथन 1 सही है:** इस अधिनियम ने 15 अगस्त, 1947 से भारतीय रियासतों पर से ब्रिटिश सर्वोच्चता की समाप्ति की घोषणा की। इसने रियासतों को या तो भारत अधिराज्य या पाकिस्तान अधिराज्य में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प प्रदान किया।
- **कथन 2 सही नहीं है:** इस अधिनियम ने गवर्नर-जनरल का पद समाप्त नहीं किया। प्रत्येक अधिराज्य (भारत और पाकिस्तान) में ब्रिटिश सम्राट द्वारा नियुक्त एक गवर्नर-जनरल होना था (जब तक कि उनके संविधान नहीं बन जाते)। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर-जनरल बने, जबकि सी. **राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर-जनरल** बने।
- **अतिरिक्त जानकारी:** भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 की अन्य विशेषताएँ इस प्रकार थीं:
  - इसने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया और 15 अगस्त, 1947 से भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित कर दिया।
  - इसने भारत का विभाजन किया और उसे ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार दिया। साथ ही, इसने भारत और पाकिस्तान के रूप में दो स्वतंत्र अधिराज्य बनाने का भी प्रावधान किया।
  - इसने दोनों अधिराज्यों की संविधान सभाओं को अपने-अपने राष्ट्रों के लिए कोई भी संविधान बनाने और अपनाने व ब्रिटिश संसद के किसी भी अधिनियम को, जिसमें स्वतंत्रता अधिनियम भी शामिल है, निरस्त करने का अधिकार दिया।
  - इसने नए संविधानों के निर्माण तक, वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रत्येक अधिराज्य और प्रांतों के शासन-संचालन का प्रावधान किया।

88. (a)

- **विकल्प (a) सही उत्तर है:** बोधगम्य विभेद का सिद्धांत (Doctrine of Intelligible Differentia) संविधान के अनुच्छेद 14 की व्याख्या करते समय लागू किया जाने वाला एक न्यायिक सिद्धांत है, जो विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। इस सिद्धांत के अनुसार:
  - विधि द्वारा किया गया कोई भी वर्गीकरण बोधगम्य विभेद एक ऐसे स्पष्ट व उचित विभेद पर आधारित होना चाहिए, जो एक समूह को दूसरों से स्पष्टतः अलग करता हो।
  - इस विभेद का उस 'उद्देश्य' के साथ एक तार्किक संबंध होना चाहिए, जिसे कानून के माध्यम से प्राप्त किया जाना है।
- इससे यह सुनिश्चित होता है कि कानून व्यक्तियों या समूहों के बीच मनमाने ढंग से भेदभाव न करे, बल्कि तर्कसंगत होने पर युक्तियुक्त वर्गीकरण की अनुमति दे। उदाहरण के लिए, दिव्यांग व्यक्तियों को विशेष लाभ प्रदान करने वाले कानून में एक बोधगम्य विभेद (शारीरिक/मानसिक दिव्यांगता) और एक तार्किक संबंध (वंचित समूह के कल्याण को बढ़ावा देना) होता है।

89. (b)

- संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) नागरिकों को वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन अनुच्छेद 19(2) भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था आदि के हित में युक्तियुक्त निर्बंधनों की अनुमति देता है।

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

- **कथन 2 सही है:** "भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना और उसकी रक्षा करना" अनुच्छेद 51(A)(c) के तहत एक मौलिक कर्त्तव्य है। यह प्रत्यक्षतः अनुच्छेद 19(2) के तहत निर्बंधनों से संबंधित है। एक व्यंग्यात्मक कृत्य आलोचनात्मक हो सकता है, लेकिन वह भारत की संप्रभुता, एकता या अखंडता को कमज़ोर करने वाला या भड़काने वाला नहीं चाहिए; अन्यथा, इसे अनुच्छेद 19(2) की सीमाओं के तहत विधिक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
- **कथन 1 सही नहीं है:** यद्यपि उत्कृष्टता प्राप्ति हेतु प्रयास करना [अनुच्छेद 51(A)(j)] एक मौलिक कर्त्तव्य है, लेकिन यह अनुच्छेद 19(2) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आरोपित किसी भी संवैधानिक निर्बंधन से विशेष रूप से संबद्ध नहीं है।

90. (c)

- संविधान के भाग IV (अर्थात् DPSP) में संशोधन करने वाला विधेयक, संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत एक संविधान संशोधन विधेयक माना जाता है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत एक संविधान संशोधन विधेयक के लिए आवश्यक है:
  1. सदन की कुल सदस्यता का बहुमत
  2. उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत
- **पहली शर्त पूरी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम मत:** सदन की कुल सदस्य संख्या के 50% से अधिक = 245 का 50% (राज्य सभा की वर्तमान सदस्य संख्या 245 है) = 123
- **दूसरी शर्त पूरी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम मत:** (⅔ x 180) = 120
- विधेयक पारित होने के लिए, दोनों शर्तें एकसाथ पूरी होनी चाहिए।
  - **शर्त 1:** 123 मतों की आवश्यकता
  - **शर्त 2:** 120 मतों की आवश्यकता
- उच्च संख्या निर्णायक सीमा है। इसलिए, विधेयक का समर्थन न्यूनतम 123 सदस्यों द्वारा किया जाना आवश्यक है।

91. (d)

- **कथन 1 सही है:** 26 जनवरी, 1950 को, संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल देशों में भारत की सदस्यता की पुष्टि की तथा एक गणराज्य के रूप में संघ में बने रहने पर सहमति व्यक्त की।
- **कथन 2 सही है:** सभा ने 24 जनवरी, 1950 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना।
- **कथन 3 सही है:** संविधान लागू होने के बाद, संविधान सभा भारत की अनंतिम संसद में परिवर्तित हो गई और वर्ष 1952 में हुए पहले आम चुनावों तक उसी क्षमता में कार्य करती रही।
- **अतिरिक्त जानकारी:** भारत की संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य:
  - इसने 22 जुलाई, 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया।
  - इसने 24 जनवरी, 1950 को राष्ट्रगान अपनाया।
  - इसने 24 जनवरी, 1950 को राष्ट्रगीत अपनाया।

92. (a)

- **कथन 1 सही है:** नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 1985 के माध्यम से नागरिकता अधिनियम, 1955 में धारा 6(A) जोड़ी गई थी। इसका उद्देश्य भारत सरकार और असम सरकार के बीच हस्ताक्षरित 'असम समझौते' के प्रमुख प्रावधानों को कानूनी प्रभाव देना था। असम समझौते का उद्देश्य पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से असम में बड़े पैमाने पर होने वाले प्रवासन का समाधान करना था और एक विशिष्ट कट-ऑफ़ तिथि से पहले और बाद में आने वाले प्रवासियों के बीच अंतर करना था।
- **कथन 2 सही है:** धारा 6(A) के तहत, भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति, जो 25 मार्च, 1971 को या उससे पहले निर्दिष्ट क्षेत्रों (बांग्लादेश सहित) से असम में प्रवेश कर गए थे, वे भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के पात्र हैं, बशर्ते वे कुछ निवास और अन्य शर्तों को पूरा करते हों।
- **कथन 3 सही नहीं है:** धारा 6(A) नागरिकता को केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों या उत्पीड़न झेल रहे लोगों तक सीमित नहीं करती है। यह प्रावधान धर्म से तटस्थ, प्रवेश-तिथि और मूल स्थान पर आधारित है।

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

93. (c)

- **विकल्प (c) सही उत्तर है:** एक वास्तविक संघ में, दो अलग-अलग न्यायिक प्रणालियाँ होती हैं– एक संघ के लिए और दूसरी राज्यों के लिए। इसके विपरीत, भारत एक एकीकृत न्यायिक संरचना का पालन करता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है, उसके बाद उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय हैं, जो एकात्मक विशेषता को दर्शाता है।
- **अतिरिक्त जानकारी:** भारतीय संविधान की अन्य संघीय विशेषताओं में शामिल हैं:
  - द्वैध शासन व्यवस्था - संघ और राज्य स्तर पर
  - लिखित संविधान
  - केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन
  - संविधान की सर्वोच्चता

94. (d)

- **कथन 1 सही नहीं है:** "मूल ढाँचा" शब्द संविधान की उन मौलिक और आवश्यक विशेषताओं को संदर्भित करता है, जिन्हें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधनों द्वारा परिवर्तित या नष्ट नहीं किया जा सकता है। इस अवधारणा को सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) वाद में प्रतिपादित किया था। संविधान में न तो "मूल ढाँचा" शब्द का उल्लेख है, न ही संसद ने इसके दायरे को परिभाषित करने के लिए कोई कानून बनाया है। इस हेतु न्यायपालिका ने न्यायिक घोषणाओं की एक शृंखला के माध्यम से इस सिद्धांत को विकसित और स्पष्ट किया है।
- **कथन 2 सही नहीं है:** सभी मूल अधिकारों को मूल ढाँचे का हिस्सा नहीं माना जाता है। केवल कुछ मूल अधिकारों, जैसे- विधि का शासन सुनिश्चित करने वाले अधिकार, न्यायिक समीक्षा तथा अनुच्छेद 14, 19 और 21 के कुछ प्रावधानों को सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढाँचे का हिस्सा माना है।
- **अतिरिक्त जानकारी:** संविधान के 'मूल ढाँचे' के अन्य तत्त्वों में शामिल हैं:
  - संविधान की सर्वोच्चता (केशवानंद भारती मामला)
  - भारतीय राजव्यवस्था की संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक प्रकृति
  - संविधान का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप (केशवानंद भारती मामला)
  - विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण
  - संविधान का संघीय स्वरूप (केशवानंद भारती मामला)
  - राष्ट्र की एकता और अखंडता (SR बोम्मई मामला)
  - कल्याणकारी राज्य (सामाजिक-आर्थिक न्याय)
  - न्यायिक समीक्षा (इंदिरा नेहरू गाँधी मामला)
  - व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा
  - संसदीय प्रणाली
  - विधि का शासन (इंदिरा नेहरू गाँधी मामला)
  - मूल अधिकारों और नीति-निदेशक सिद्धांतों के बीच सामंजस्य और संतुलन
  - समानता का सिद्धांत
  - स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव (इंदिरा नेहरू गाँधी मामला)
  - न्यायपालिका की स्वतंत्रता
  - संविधान-संशोधन करने की संसद की सीमित शक्ति (मिनर्वा मिल्स मामला)
  - न्याय तक प्रभावी पहुँच
  - मौलिक अधिकारों के अंतर्निहित सिद्धांत (या सार)

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

- अनुच्छेद 32, 136, 141 और 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ
- अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की शक्तियाँ (एल. चंद्र कुमार मामला)

95. (c)

- **अनुच्छेद 35 के बारे में:** यह निर्दिष्ट करता है कि केवल संसद, न कि राज्य विधानमंडल, कुछ निर्दिष्ट मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए विधि निर्माण का अधिकार रखती है। यह प्रावधान इन अधिकारों की प्रकृति और उनके उल्लंघन पर दण्ड-निर्धारण हेतु पूरे देश में एकरूपता सुनिश्चित करता है।
- **कथन 1 सही है:** अनुच्छेद 16 के अंतर्गत, किसी राज्य, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण में कुछ रोज़गारों या नियुक्तियों के लिए 'निवास' को एक शर्त के रूप में निर्धारित करने की शक्ति केवल संसद में निहित है।
- **कथन 2 सही है:** अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और इसके आचरण को दण्डनीय अपराध बनाता है। अनुच्छेद 35 आगे यह प्रावधान करता है कि केवल संसद ही अस्पृश्यता सहित मूल अधिकारों के अंतर्गत घोषित ऐसे अपराधों के लिए दण्ड निर्धारित कर सकती है।
- **अतिरिक्त जानकारी:** अन्य उदाहरण, जहाँ संसद को कानून बनाने की विशेष शक्ति प्राप्त है, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
  - सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अलावा, न्यायालयों को मूल अधिकारों को लागू करने के लिए विभिन्न निर्देश, आदेश और रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करना (अनुच्छेद 32)।
  - सशस्त्र बलों, पुलिस और समान बलों के सदस्यों पर मूल अधिकारों की प्रयोज्यता को सीमित करना या हटाना (अनुच्छेद 33)।
  - किसी भी क्षेत्र में सेना विधि लागू होने के दौरान की गई कार्रवाइयों के लिए सरकारी कर्मचारियों या किसी भी व्यक्ति को विधिक सुरक्षा प्रदान करना (अनुच्छेद 34)।
  - मानव तस्करी और बलात् श्रम को बढ़ावा देने के अपराध के लिए दण्ड निर्धारित करना (अनुच्छेद 23)।

96. (a)

कथन 1 सही है: अनुच्छेद 3 संसद को किसी राज्य से क्षेत्र अलग करके या दो या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाकर, या किसी राज्य के किसी भाग में किसी क्षेत्र को मिलाकर एक नया राज्य बनाने का अधिकार देता है।

कथन 2 सही है: राज्य की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित किसी विधेयक की अनुशंसा करने से पहले, राष्ट्रपति को उसे एक निश्चित अवधि के भीतर संबंधित राज्य विधानमंडल के पास उसके विचार जानने के लिए भेजना होगा।

कथन 3 सही नहीं है: ऐसा कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है कि किसी राज्य का नाम बदलने वाला विधेयक केवल राज्य सभा में ही पेश किया जा सकता है। ऐसा विधेयक लोक सभा या राज्य सभा में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।

कथन 4 सही नहीं है: संबंधित राज्य विधानमंडल की सहमति अनिवार्य नहीं है; संसद उनकी स्वीकृति के बिना भी सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है, भले ही उनके विचार प्रस्ताव के विरुद्ध हों।

अतिरिक्त जानकारी:

- अनुच्छेद 3 संसद को किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाने या घटाने, सीमाओं में परिवर्तन करने और राज्य का नाम बदलने का भी अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कोई विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लेकिन केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही।
- राष्ट्रपति और संसद संबंधित राज्य विधानमंडल के विचारों को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं।
- भारत को "विनाशकारी राज्यों का अविनाशी संघ" कहा गया है। संसद राज्यों को परिवर्तित या समाप्त कर सकती है, लेकिन 'राज्य' संघ को नहीं बदल सकते हैं।

97. (d)

- **प्रस्तावना के बारे में:** यह संविधान के पहचान-पत्र की तरह है, जो उस मूल दर्शन और मौलिक मूल्यों को समाहित करती है, जिन पर संविधान आधारित है। इसमें संविधान सभा का बेहतरीन और महान दृष्टिकोण निहित है और यह संविधान-निर्माताओं के सपनों और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करती है।
- प्रस्तावना अपने सभी नागरिकों के लिए निम्नलिखित आदर्शों को सुरक्षित करने की परिकल्पना करती है:

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/

- न्याय- सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अतः, 1 सही है।
- विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। अतः, 3 सही है।
- प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अतः, 2 सही है।
- बंधुत्व - व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना।

98. (c)

- **कथन 1 सही है:** अनुच्छेद 23(2) राज्य को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा लागू करने की स्पष्ट अनुमति देता है, बशर्ते कि केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए। इसलिए, यदि ऐसा निष्पक्ष रूप से और बिना किसी भेदभाव के किया जाए, तो अनिवार्य सेवा अपने आप में उल्लंघन नहीं है।
- **कथन 2 सही नहीं है:** अनुच्छेद 23(1) बेगार और बंधुआ मज़दूरी सहित अन्य सभी प्रकार के बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाता है, चाहे वह राज्य द्वारा लागू किया गया हो या किसी निजी व्यक्ति द्वारा।
- **कथन 3 सही नहीं है:** यद्यपि सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा की अनुमति है, लेकिन इसे किसी विशेष धर्म पर चयनित रूप से लागू करना केवल धर्म के आधार पर भेदभाव के समान है, जो अनुच्छेद 23(2) के तहत निषिद्ध है।

99. (d)

- **विकल्प (d) सही उत्तर है:** 25वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 ने अनुच्छेद 31(C) जोड़ा, जो अनुच्छेद 39(b) (संसाधनों का समान वितरण) और अनुच्छेद 39(c) (धन के संकेंद्रण का निषेध) में निहित निदेशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए निर्मित विधियों को अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, या अनुच्छेद 31 (संपत्ति का अधिकार - अब निरस्त) के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दिए जाने से संरक्षित करता है। इस प्रकार, इन विशिष्ट DPSPs के लिए, संसद ऐसे कानून बना सकती है, जो अनुच्छेद 14 के आधार पर चुनौतियों से मुक्त हों।
- **विकल्प (a) सही नहीं है:** अनुच्छेद 14 की हमेशा प्रधानता नहीं होती है। अनुच्छेद 31(C) के तहत, अनुच्छेद 39(b) और (c) को लागू करने वाले कानून अनुच्छेद 14 की अपेक्षा प्राथमिक हो सकते हैं।
- **विकल्प (b) सही नहीं है:** संविधान किसी भी DPSP को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता नहीं देता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के तहत, संसद ने अनुच्छेद 31(C) का विस्तार करने का प्रयास किया, ताकि किसी भी निदेशक सिद्धांत को लागू करने वाले सभी कानूनों को अनुच्छेद 14 और 19 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती न दी जा सके। हालाँकि, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस व्यापक विस्तार को असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया। वर्तमान में, अनुच्छेद 31(C) केवल अनुच्छेद 39(b) और 39(c) से संबंधित DPSPs को लागू करने के लिए बनाए गए कानूनों पर लागू होता है, जो अनुच्छेद 14 और 19 को रद्द कर सकते हैं और तब भी, वे मूल ढाँचे का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं।
- **विकल्प (c) सही नहीं है:** आरंभिक संवैधानिक इतिहास (चंपकम दोराईराजन, 1951) में यही स्थिति थी, लेकिन 25वें संशोधन के बाद, कुछ नीति-निदेशक सिद्धांत अनुच्छेद 14 और 19 पर प्राथमिक हो सकते हैं।

100. (a)

- **कथन 1 सही है:** संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून को न्यायपालिका द्वारा रद्द किया जा सकता है, यदि वह संविधान के भाग-III (मौलिक अधिकार) के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है। यह अनुच्छेद 13(2) के तहत स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है।
- **कथन 2 सही नहीं है:** भाग IV के तहत राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांत (DPSP) गैर-न्यायसंगत (अनुच्छेद 37) हैं। किसी कानून को केवल नीति-निदेशक सिद्धांतों के साथ असंगत होने के कारण अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता है।
- **कथन 3 सही नहीं है:** मूल ढाँचे का सिद्धांत केवल संविधान संशोधनों पर लागू होता है, सामान्य कानूनों पर नहीं। इसलिए, सामान्य कानूनों को केवल मूल ढाँचे का उल्लंघन करने के कारण अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता; उन्हें संविधान, विशेषकर मूल अधिकारों के आधार पर परखा जाना चाहिए। अंजुम कादिरी बनाम भारत संघ, 2023 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि केवल संवैधानिक संशोधनों को ही मूल ढाँचे के सिद्धांत के आधार पर परखा जा सकता है। एक सामान्य विधि, भले ही वह मूल ढाँचे से असंगत हो, केवल इसी आधार पर रद्द नहीं की जा सकती। अमान्य होने के लिए उसे किसी विशिष्ट संवैधानिक प्रावधान (जैसे- मौलिक अधिकार) का उल्लंघन करना होगा।

■■■■

https://upscpdf.com/ https://upscpdf.com/